हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1990

खण्ड 2, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 19 मार्च, 1990

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)28
विभिन्न विशयो को उठाया जाना	(6)33
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	

असन्ध उप–मण्डल के कुछ गांवों को करनाल जिले में सम्मिलित करने सम्बन्धी	(6)35
वक्तव्य –	
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(6)36
वर्श 1990–91 के बजट पर अनुदोनों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान तारांकित प्रश्न संख्या 1100 पर आधे घंटे की चर्चा –	(6)37
डिजनी लैंड सम्बन्धी	(6)99
अपैन्डिक्स–1	(6)111
अपैन्डिक्स–2	(6)111

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 19 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियणा विधान सभा हाल,विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ मे 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Employees in Faridabad Complex

***1070. Sh. Udai Bhan**: Will the Minister for Local Govt. be pleased to state –

(a) the categorywise number of employees working in the Faridabad Complex togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes amongst them; and

(b) whether there is any backlog in the reserved posts; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which these posts are likely to be filled up?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

***Interim reply**

“SUBHASH KAYTAL

D.O. No. 26-6-90-3CII

Local Government Minister,

Haryana, Chandigarh.

March 16, 1990.

Subject: Starred Assembly Question No. 1070 asked by Sh. Udai Bhan, M.L.A. regarding Employees in Faridabad Complex.

My dear Sh. Chatha,

Sh. Udai Bhan, M.L.A. has asked Starred Assembly Questioin No. 1070 (fixed for reply on 19-3-90) as follows:-

“Will the Minister for Local Government be pleased to state –

(a) the categorywise number of employees working in the Faridabad Complex togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes amongst them; and’

(b) whether there is any backlog in the reserved posts; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which these posts are likely to be filled up?”

2. The question involves huge information ot be supplied which will take some more time. I, therefore, request for one week time for supply of this information, Extension may kindly be granted accordingly.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Subhash Katyal)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana, Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Allotment of Plot to the Landless and Weaker Section persons

***1059. Comrade Harpal Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state –

(a) the names and addresses of the landless and weaker section persons who have been allotted residential posts during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 in the State; and

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above who have not been given the actual possession of the posts so far?

उप–मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) भूमि रहित एवं कमजोर वर्ग के लोग जिन्हें वर्श 1987–88 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान में रिहायशी प्लौट

नियत किये गये हैं उनकी दो@ विवरणियां सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) कब्जे अभी तक नहीं दिये गये हैं क्योंकि विकास कार्य प्रगति में है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन प्लौटस की अलौटमैंट से पहले भी कुछ वीकर सैक्शन के लोगों को प्लौट अलौट किये गये थे। उनका आज तक कब्जा नहीं मिला है। मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनका कब्जा दिलाने के बारे में कोई कार्यवाही करने जा रही है? इसके अलावा, करनाल जिले में स्टौंडी गांव है। वहां कब्जा होने के बाद भी उनसे प्लौटस छुडाये गये हैं। क्या सरकार उन्हे दुबारा से कब्जा दिलवाने के बारे में प्रयास कर रही हैं?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, पर्टिकुलर गांव के बारे में तो मैं कुछ नहीं बतला सकूंगा। लेकिन जब यह स्कीम 1980 में वीकर सैक्शन के लोगों को प्लौटस देने के बारे में बनायी गई तो उस सरकार ने स्कीम बनाने के बाद प्लौटस देने की घोशणा भी कर दी, ऐप्लीकेशनज भी इन्वाइट कर ली, पोस्टर्ज छपवा कर पब्लिसिटी की गई। मैंने भी वह पोस्टर जो सन् 1987 के चुनाव से पहले छपा था आज फाईल में लगा देखा है। उस पोस्टर पर चीफ मिनिस्टर, चौ. बंसी लाल, प्रधान मंत्री श्री राजीव

गांधी और सेठ श्री किशनदास जो इन्चार्ज मंत्री थे, उनके फोटो छपे थे। लेकिन जहां प्लौटस अलौट किये गये वहां जमीन भी ऐकवायर नहीं की गई थी। ये प्रोपेगैंडा करते रहे। हमारी सरकार आने के बाद प्लौटस भी दिये गये। कब्जा अभी हम दे नहीं पाये हैं क्योंकि डिवैल्पमैंट के काम इनप्रोग्रैस हैं और इसी साल में अम्बाला और पंचकूला के डिवैल्पमैंट के काम पूरे कर लेंगे तो उन्हें कब्जा भी देंगे।

कामरेड हरपाल सिंह: उप–मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि इन्होंने अलौटमैंट की है। जहां तक हमें पता है कि यह अलौटमैंट पहले भी हुई है और पर्टिकुलर हरिजन और वीकर सैक्शन के लोगों को अलौट हुए हैं लेकिन वे प्लौटस जोहड़ों में हैं किसी अच्छी जगह नहीं दिये जाते। क्या सरकार कोई पालिसी बना कर उन्हें अच्छी जगह प्लौटस अलौट करेंगी और उन्हें कब्जा दिलाया जायेगा? करनाल में स्टौडी गांव का नाम मैंने लिया है वहां पर रजिस्टरी होने के बावजूद दुबारा से प्लौटस नीलाम करने की कोशिश की गई है।

श्री बनारसी दास गुप्त: सम्मानित सदस्य इस प्रश्न को कन्फयूज कर रहे हैं। दो तरह के प्लौटस हैं। एक प्लौटस रैवेन्यू डिपार्टमैंट की तरु से जो लैंडलैस लोग हैं, उनको शामलातदेह में से दिये जाते हैं या पंचायत भूमि में से दिये जाते हैं, कहीं जोहड़ में भी दिये जाते होंगे लेकिन मेरे से क्वैश्चन यह पूछा गया था कि हुड्डा द्वारा प्लौटस वीकर सैक्शन के लोगों को दिये गये हैं

या नहीं। हमने प्लौटस दिये हैं लेकिन वहां सड़क, बिजली, वाटर सप्लाई और सिवरेज का प्रबन्ध होना है। जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि किन किन वर्शो में कितने कितने प्लौटस दिये हैं, उसका विवरण दिया गया है। इस साल दो तीन ऐस्टेटस में जो ऐसे प्लौटस है उनके कब्जे दे देंगे।

श्री परमा नन्द: स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा उप–मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब के बड़े–बड़े लैन्डलाईज अपनी भूमि को बेनामी करवाने के लिए किसी का नाम मिर्चीकौर और किसी का आलु सिंह लिखवा देते थे क्या इसी प्रकार पेज 55 पर 104 नम्बर पर जो मिठाई राम लिखा गया है, इसमें हेराफेरी तो नहीं है, यह बेनामी तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष: प्रोफैसर साहब, इस बारे में आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरे क्वैश्चन में हुड्डा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने वीकर सैक्शन के लोगों को दिये जाने वाले प्लौटस के बारे में पूछा था। मुझे रिटन जवाब में भी कुछ और ही बता दिया गया है और अब भी कुछ और ही जवाब दिया जा रहा है।

Mr. Speaker: You have not put the question to the Revenue Minister. You have put the question to the Deputy Chief Minister. इनके पास कौन सा डिपार्टमैंट है, उसके हिसाब से ही जवाब आयेगा।

कामरेड हरपाल सिंह: प्लौटस तो पंचायतें भी अलौट करती हैं।

Mr. Speaker: That question pertains to the Development Minister.

कामरेड हरपाल सिंह: सर, हमें तो इस बात की दिक्कत है कि कौन सा मंत्री किस डिपार्टमैंट का है। रोज यह बदल जाते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो वीकर सैक्शन के लोगों को प्लौटस दिये जाते हैं, इन प्लौटस को देने का क्राईटेरिया क्या है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार का क्राईटेरिया तो यह था कि जिस व्यक्ति की वार्शिक आय साढ़े तीन सौ रूपया या उससे कम होगी, उसको वीकर सैक्शन में माना जाएगा। लेकिन अब हमारी सरकार ने इस आय की सीमा को बढ़ा कर 1500 रूपया कर दिया है यानी जिस फैमिली की इन्कम 1500 रूपया हो या इससे कम हो, उसको यह प्लौटस दिया जाता है।

श्री रतन लाल कटारिया: क्या हमारे उप–मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस तरह की कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ लौगों ने लैंडलैस के या वीकर सैक्शन्ज से सम्बन्धित होने के सर्टीफिकेटस लेकर ये प्लौटस ले

लिये और आगे उनको ट्रासंसफर कर दिया? अगर ऐसी कोई शिकायत मिली है तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, प्लौटस को ट्रांसफर करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब उनको पोजैशन ही नहीं मिला तो वे ट्रांसफर कैसे करेंगे।

श्री कैलाश नन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्य मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। जिन स्थानों पर अभी तक हुड्डा ने कोई कालोनी नहीं बनायी है, प्लौटस कोर्ट ही नीं हैं, वहां पर वीकर सैक्शन के लोगों का आज तक तो नम्बर आया ही नहीं है। क्या ऐसे स्थानों पर वीकर सैक्शन के लोगों को नगरपालिका के माध्यम से प्लौटस देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की बात तो मैं नहीं कह सकता। यह तो कन्सर्न्ड मिनिस्टर ही बता पायेंगे कि इस बारे में क्या स्थिति है। मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि हरियाणा के लगभग सभी जगहों पर अर्बन ऐस्टैटस हम बनाने जा रहे हैं और सैक्टर बनाने जा रहे हैं जहां–जहां पर यह सैक्टर बनने हैं या बनेंगे, हम 10 परसैंट प्लौटस वीकर सैक्शन के लोगौं के लिये रिजर्व रखते हैं और रखेंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो यह

कहा है कि विकास कार्य प्रगति परन है यह किस स्टेज पर है और क्या वीकर सैक्शन के लोगों से पहली किस्त भरवानी शुरू कर दी है?

श्री बनारसी दास गुप्त: इनकी यह बात ठीक है कि विकास कार्य प्रगति पर है, ऐसा मैंने कहा है। कैथल को छोड़कर बाकी सभी ऐस्टेटस में 31 दिसम्बर, 1990 तक विकास कार्य पूरा हो जायेगा और उनको कब्जा दे दिया जायेगा।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री महोदय ने यह जो जवाब दिया है, इस बारे में हुड्डा का तो सवाल ही नहीं था। (व्यवधान व शोर) लेकिन मैं एक जनरल सी बात पूछना चाहता हूं .....

Mr. Speaker: No Please, I am very sorry.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं वैसे ही सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं तो किसी आधार पर सवाल पूछा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा पूछिए।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, हुड्डा और फरीदाबाद काम्पलैक्स का एक जैसा काम है। इसलिए मैं एक पुरानी स्कीम के मुताबिक पूछना चाहता हूं। जिसकी गुप्ता जी को भी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पुट कीजिये।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं सवाल ही पुट करने जा रहा हूं। चौ. बंसी लाल जी के साथ गुप्ता जी रहे हैं। इनको जानकारी होगी। मेरा सप्लीमैंट्री सवाल यह है कि चूंकि 18–20 पंचायतों में तकरीबन हर जगह जमीन नहीं थी इसलिए पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि वीकर सैक्शन के लोगों को काम्पलैक्स एरिया में प्लौटस दिये जायें।

Mr. Speaker: Mahender Partap ji, I can allow a supplementary which is connected with the main question. It is not the question. You put a relevant supplementary.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: उस समय यह फैसला किया गया था। किन्ही कारणों से चूंकि वह स्कीम लागू नहीं हो सकी इसलिये उन 18–20 गांवों की पंचायतों की जो जमीन काम्पलैक्स में पड़ती थीं, उसमें से वीकर सैक्शन के लोगों को प्लौटस नहीं दिये जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारने उस योजना को अब तक लागू क्यों नहीं किया है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के वे लीडर हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के सम्मानित सदस्य हो यह पता होना चाहिये कि मैं क्या सप्लीमैंट्री कर रहा हूं। मूल प्रश्न से क्या इसका कोई कन्सर्न है।

Mr. Speaker: Yes, it does not concern your department.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: मैंने तो इसलिए पूछा है क्योंकि श्री हरपाल सिंह ने कहा है कि उनका हुड्डा के बारे में सवाल नहीं था बल्कि उन्होंने तो जनरल सवाल पूछा था। (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker: Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर मुझे सवाल की वह कापी दिखा दी जाती जो मैंने सवाल भेजा था तो मेरा कंफयूजन दूर हो जाता। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। If you want to see that please come to my Chamber. श्री उदयभान।

श्री उदय भान: मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट पेश की उससे पता लगता है कि वर्श 1988–89 और 1989–90 में कोई प्लौट नहीं दिया गया लेकिन वर्श 1987–88 में 330 प्लौटस दिए गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये प्लौट पहली सरकार द्वारा दिए गए थे या हमारी सरकार द्वारा दिये गए हैं? अध्यक्ष महोदय पिछले दो साल में कोई प्लौट नहीं दिए गए हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने तीन साल का पूछा है और वे साल हैं 1987–88, 1988–89 और 1989–90। अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार का तो प्लौट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 1104 प्लौट अलौट किए हैं।

पंचकूला के अन्दर वर्श 1987–88 मे 151 प्लौट अलौट किए हैं। वर्श 1987–88 में कुल 550 प्लौट अलौट किए, 1988–89 में 440 प्लौट अलौट दिए और 1989–90 में 114 प्लौट दिए गए हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह बात सर्वविदित है कि शहरों में दिन प्रति दिन आबादी बढ़ती जा रही है। देहात के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई सर्वे करवाया था कि लोगों की मांग कि कदर बढ़ती जा रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए, सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अगर माननीय सदस्य अलग से नोटिस देंगे तो सारी इंफमेशन मिल जाएगी।

Plying of Local Buses in the State

***1053. Sh. Sita ram Singla**: Will the Minister of State of Transport be pleased to state –

(a) the name of cities in which local buses are plying in the state togetherwith the number thereof separately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to ply local buses in some other cities during the next financial year?

Home Minister (Prof. Sampat Singh):

(a)

Ambala	76
Panchkula	20
Yamuna Nagar	5
Kurukshetra	5
Karnal	2
Panipat	1
Rohtak	7
Faridabad	2
Gurgaon	2
Hisar	6

(b) No such proposal in under consideration of the State Government.

श्री सीता राम सिंगला: मंत्री महोदय ने बताया है कि अम्बाला में 26 पंचकूला में 20, यमुनानगर में 5, कुरूक्षेत्र में 5, करनाल में 2, पानीपत में 1, रोहतक में 7, फरीदाबाद में 2, गुड़गांव में 2 और हिसार में 6 लोकल बसें चल रही हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा केरंगे कि लोकल बसिज चलाने का क्या आधार है और इनका बंटवारा कैसे होता है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांग के आधार पर बसिज चलाई जाती है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव इतना बड़ा शहर है और मैंने वहां की बसिज की डिमांड को देखते हुए दो डी.ओ. लैटर परिवहन मंत्री को लिखे थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन डी.ओ. लैटर्ज पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ज्यों–ज्यों मांग आती है उसको ऐग्जामिन करवाते हैं उसके बाद अगर जरूरी समझते हैं तो बसिज चलाते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी शहर में कोई भी लोकल बस नहीं चलतीं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्श 1990–91 में रिवाडी में लाकल बसिज चलाई जाएंगी?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी से कोई मांग नहीं आई हैं। इसलिए यह बात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोकल बसिज की बहुत जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: आप आज लिखकर दे दें।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, नारनौल के आसपास बहुत से गांव हैं और वहां से बच्चे स्कूल और कालेजिज में पढ़ने के लिए आते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर लोकल बसिज चलाने का इन्तजाम किया जाएगा?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल सिटीज का है और इन्होंने गांव का पूछा है। इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि मांग आने पर उसको प्रोसैस कराते हैं और जरूरी कार्यवाही करते हैं। माननीय सिंगला साहब ने अपने चुनाव क्षेत्र में लोकल बसिज ज्यादा चलाने सम्बन्धित दो डी.ओ. लैटर्ज इनको भेजे हैं। क्या सरकार उन पर नये सिरे से विचार करेगी?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बाकायदा करेंगे।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि अम्बाला में 26 और पंचकूला में 20 लोकल बसिज चल रही हैं। दूसरी कई जगहों का जिक्र भी इन्होंने किया है जहां पर बहुत कम बसिज चलाई जा रही हैं। मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद जो एक घनी आबादी वाला शहर है वहां केवल 2 बसिज ही क्यों चलाई जा रही हैं? क्या वहां के लोगों की कोई डिमांड इनके पास नहीं आई थी

कि वहां पर भी ज्यादा लोकल बसिज चलाने का प्रबन्ध किया जाए?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पब्लिक की मांग को देखते हुए हम खुद भी इस तरह का प्रबन्ध करते हैं और जो उनकी मांग हो उसके मुताबिक हम बसिज मुहैया करते हैं लेकिन फरीदाबाद से हमारे पास लोगों की कोई डिमांड नहीं थी। अगर वहां से लोगों की इस बारे में कोई मांग आएगी तो हम उस पर गौर करेंगे।

Bus accidents on G.T. Road

***1081. Seth Lachman Dass Bajaj**: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the total number of fatal accidents involving Haryana Roadways buses occurred on G.T. Road in State during the Calendar year 1989; and

(b) whether any amount as compensation has been paid as a matter of policy depending upon the nature of casualty suffered to the dependent of the deceased and the persons injured in the accidents referred to in part (a) above; if so, the total amount paid as compensation?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

***Interim reply**

“Sampat Singh

D.O. No. 72-HM-90

Home Minister, Haryana,

Chandigahr.

Dated: 16th March, 1990.

Subject: Starred Assembly Question No. 1081.

Dear Sh. H.S. Chatha, Sahib,

Reply to the starred Assembly Question No. 1081 by Sh. Lachhman Das Bajaj. M.L.A. is due for reply on the 19th Marc, 1990. The reply involves collection and consolidation of information pertaining to the number of accidents took place on the G.T. Road from 1-1-89 to 31-12-89 involving Haryana Roadways buses being operated by 16 depots of Haryana Roadways together with the accident claims decided by the courts and paid to the claimants. This information has to be collected frm the various depots of Haryana Roadways and is likely to take some time. Under these circumstances, I would request you to kindly grant and extension of three weeks time for furnishing the reply to this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(SAMPAT SINGH)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Southern Haryana Development Board

***1089. Capt. Ajay Singh Yadav**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Southern Haryana Development Board for the development of he economically backward area of Districts Rewari and Mohindergarh; and

(b) if, so the time by which the aforesaid Board is likely to be constituted?

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और लोहारू के इलाके सारे हरियाणा में काफी पिछड़े हुए हैं और दक्षिण हरियाणा विकास मण्डल गठन करने के लिए भूतपूर्व विधायक श्री रघु यादव जी ने भी सरकार से मांग की थी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह का बोर्ड गठन करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है? जिस तरह से

मेवाल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया गया था उसी प्रकार से इन इलाकों के विकास के लिये इसका गठन भी आवश्यक है ताकि इस इलाके की डिवैल्पमैंट हा सके। क्या सरकार इस पर दोबारा विचार करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड वर्श 1980 में गठित हुआ था और वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। सारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर इससे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका हमारे विचार से और कोई नहीं होगा लेकिन 1986 से जब से डिसैन्ट्रेलाइर्जड प्लानिंग की स्कीम बनी है तब से किसी क्षेत्र के लिये अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की गयी।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं अपने जवाब में माना है कि महेन्द्रगढ़ वगैरह के इलाके काफी पिछड़ हुए हैं। क्या सरकार इन इलाकों को ऐक्स्ट्रा सहायता देने का विचार रखती है ताकि इस इलाके की खुशहाली हो सके?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, डिसैन्ट्रेलाइज्ड स्कीम के तहत हर जिला में एक प्लानिंग बोर्ड बना है। वहां जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है, वह उसका चेयरमैन, जिला के डिप्टी कमिश्नर उसके वाइस चेयरमैन, ब्लाक समिमि के चेयरमैन, वहां के अधिकारी और म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष वगैरह सभी उसके मैम्बर्ज होते हैं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको स्पैशल फण्डज

ऐलोकेट किये जाते हैं लेकिन महेन्द्रगढ़ जिला की बैकवर्डनैस को दूर करने के लिये इस इलाके में इस तरह का अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ये जो इलाके हैं, टेल पर लगते हैं, राजस्थान की सीमा पर हैं वहां पर बिजली, पानी व विकास की जो गंगा बहती थी, वह सूख चुकी है। अगर सरकार दक्षिण हरियाणा विकास मण्डल का गठन करने का विचार नहीं रखती तो क्या ऐसे इलाके के लिये कोई अतिरिक्त धन की उपलब्धि कराने की सरकार की कोई योजना है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जो भी इलाका टेल पर होता है उसको हर चीज बहुत कम मिलती है। पूरी चीज वहां तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयास हो रहा है। जे.एल.एन. कैनाल वहां बन चुकी है। उसकी डिस्ट्रीब्यूस्ट्रीज तथा माईनर्ज भी बन चुके हैं और उनमें पानी भी चल रहा है। लेकिन पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जिस रोज एस.वाई.एल. नहर के पानी का हिस्सा हमें प्राप्त होगा, मुझे इस बात की पूरी आशा है कि महेन्द्रगढ़ जिले के चप्पे चप्पे को पानी लगेगा।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि रिवाड़ी, नारनौल और महेन्द्रगढ़

पिछड़े हुए इलाके हैं। पानी के बारे में इन्होंने फरमाया कि एस. वाई.एल. का पानी आने के बाद पानी टेल तक पहुंच जाएगा। पहले तो सैंटर में कांग्रेस की सरकार थी जो हरियाणा के साथ बे–इंसाफी किया करती थी। अब तो वहां हरियाणा के हितैशी बैठे हुए हैं। इस लिए क्या मंत्री जी बताएंगे कि एस.वाई.एल. का पानी कब तक आ जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, सैंटर में राश्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे ओर संबंधित मंत्री जी से भी मिले थे और उनको इस नहर को जल्दी बनवाने के लिए पुरजोर आग्रह किया था। अब ते हमारे साथ पक्षपात होता रहा है लेकिन अब हमें आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि 31 दिसम्बर, 1990 तक वह नहर बन कर तैयार हो जाएगी।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम तो यह जानना चाहते हैं कि पानी कब आएगा?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हिस्से में तो नहर बन चुकी है लेकिन जहां से पानी चलना है वहां नहर नहीं बनी है। हरियाणा के हिस्से की नहर तो कई जगह से टूट भी गई है। उसकी रिपेयर के लिए भी हमने भारत सरकार से पैसे की डिमांड की है। जब पंजाब के हिस्से में नहर बन कर

तैयार हो जाएगी तो हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन पूरा पानी हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक थीन डैम बन कर तैयार नहीं हो जाएगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात के लिए भी दबाव डाला है कि थीन डैम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। थीन डैम से जो बिजली पैदा होगी, हमने उसमें से अपना हिस्सा भी क्लेम किया है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं उप–मुख्य मंत्री जी ने जानना चाहता हूं .....

Mr. Speaker: This question is not regarding the Irrigation Department.

Dr. Mangal Sein: I am quite relevant, Sir, I am within my scope.

श्री अध्यक्ष: डा. साहब आप जरा बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, उप–मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि महेन्द्रगढ़ जिला पिछड़ा हुआ है। महेन्द्रगढ़ के इलाके के लिए लोहारू कैनाल, जुई कैनाल और जे.एल.एन. कैनाल की टेल पड़ती है .....

श्री अध्यक्ष: आर्य जी, मंत्री जी ने अगर जवाब दे दिया तो इसका मतलब यह नही है कि सप्लीमैंटरीज नहरों पर चली जाएं। आप मेन सवाल के बारे सप्लीमैंटरी कर सकते हैं। I would not permit irrelevant supplementaries.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, उस इलाके में नहरों में सालों साल से मिट्टी भरी पड़ी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस इलाके में पानी पहुंचाने के लिए और उन नहरों की सफाई करवाने के लिए पैसा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: इसका मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। It is not possible for the Minister to reply to this supplementary.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, उप–मुख्य मंत्री जी ने अभी हाउस को ऐनलाइटन किया कि हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जी पर दबाव डाला है इन्हौंने यह भी कहा कि जब तक थीन डैम नहीं बनेगा तब तक पानी नहीं आ सकता। मैं जानना चाहता हूं कि थीन डैम कब बनना शुरू हुआ था और कब तक बन जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो नहीं कहा कि पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा मैंने तो यह कहा है कि जब तक थीन डैम बन नहीं जाएगा हमें पूरा पानी नहीं मिलेगा। रावी व्यास का सरप्लस वाटर का जितना हिस्सा हमारा बनता है वह पूरा हिस्सा तभी मिलेगा जब थीन डैम बन जाएगा लेकिन कुछ पानी मिलना उससे पहले शुरू हो जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास की दृश्टि से किसी जगह को बैकवर्ड एरिया घोशित करने का क्या क्राइटेरिया है?

श्री अध्यक्ष: कामरेड साहब, इस सप्लीमैंटरी का औफ हैंड जवाब देना बहुत मुश्किल है।

Construction of Link/Aproach Road

***1078. Sh. Parma Nand**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the number of link/approach roads, if any, constructed by the Haryana Agricultural Marketing Board in each Constituency of the State during the years 1988&89 and 1989-90 togetherwith kilometers of roads constructed in Jind Constituency?

मुख्य मंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): वर्श 1988–89 के दौरान हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा किसी योजक/पहुंच सड़क के निर्माण को पूरा नहीं किया गया। वर्श 1989.90 के दौरान 28.2.1990 तक राज्य में कुल 30.69 किलोमीअर लम्बाई 22 सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। निर्वाचन क्षेत्रवार अनुलग्नक ''क'' में दिया गया विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(अनुलग्नक ''क'')

वर्श 1989–90 में बनाई गई सड़कों की सूची:–

विधान सभा क्षेत्र		सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी. में

अम्बाला जिला			
नारायणगढ़	1	भरोन से कालन माजंरी	1.47
	2	रसीदपुर से शहजादपुर	2.00
	3	उज्जल माजरी से फिरोजपुर	1.14
मुलाना	1	डेरा हरगोबिन्दपुरा से कम्बासी	1.75
छछरौली	1	नहर कालोनी दादूपुर से गांव दादूपुर	0.38
कुरूक्षेत्र जिला			
थानेसर	1	राम नगर से सुलतानपुर	1.00
गुहला	1	डेरा जगदीश सिंह से खरकां से पी.सी. रामथली	2.16
	2	थे बनरा से सब–यार्ड भागल	3.10
पेहवा	1	सैनी फार्म से पी.सी. बोदनी	1.57
	2	डेरा बाजीग्राम से सैदां शेरपुर	1.15
	3	डेरा बाजीग्राम से ककरौली	1.30

		से नीमवाला तक	
रदौर	1	सुलतानपुर से डांगला	1.80
	2	कलवा से सुनारियां	1.21
करनाल जिला			
नीलोखेड़ी	1	तखना से तरावड़ी मण्डी	0.72
भिवानी जिला			
दादरी	1	भरवी से दादरी लोहारू रोड	0.20
	2	इमलोटा से भिगोवा	3.69
फरीदाबाद जिला			
फरीदाबाद	1	बैनसरावाली मझावाली सड़क से टिगोंव सब यार्ड तक	0.41
गुड़गांव जिला			
फिरोजपुर झिरका	1	अहमदवास से पाडला	1.10
रोहतक जिला			

मेहम	1	पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से पूथी सड़क तक	1.52
सिरसा जिला			
सिरसा	1	धानी साहिब सिंह से सिरसा कलनिया सड़क तक	0.58
रोड़ी	1	भांगू से छतरियां	1.75
दरबां कलां	1	दरबां कलां से मानिक दीवान	0.69
		कुल	30.69

बाकी विधान सभा क्षेत्रों में इस समय के दौरान कोई सड़क पूरी नहीं बनीं।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि योजक और पहुंच सड़कें बनाने के लिए वर्श 1989–90 में कुल कितना धन रखा गया था? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्श 1989–90 में योजक और पहुंच सड़कें बनाने के लिए जितना धन रखा गया था उससे कितनी सड़कें बननी थीं और जितनी सड़कें बननी थीं क्या वे पूरी हो गई यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रूरल लिंक और ऐप्रोच रोड बनाने के लिए वर्श 1989–90 में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था। इससे पहले कोई फैसला नहीं था। वर्श 1988–89 में 900 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने का फैसला नहीं था। एक किलोमीअर सड़क रिपेयर करने पर तकरीबन 16 हजार रूपए खर्चा आता है। इस रेशो से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

Mr. Speaker: Smt. Kamla Verma. Parma Nand ji, please sit down. I will give you an opportunity.

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, शहरों की सड़कों की मुरम्मत के बारे में मार्किटिंग बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि 2 लाख 40 हजार रूपए खर्च किए जाएंगे। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या शहरों की सड़कों की मुरम्मत के लिए उस पैसे की स्वीकृति दी जा चुकी है और क्या वह पैसा रीलीज हो चुका है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो मार्किटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाने की तजवीज है उसमें एक किलोमीटर पर तकरीबन साढ़े तीन लाख रूपए खर्च होता है। वर्श 1989–90 में इस काम के लिए 13 करोंड रूपए रखे गए थे।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, शहरों में नई सड़कें तो बननी नहीं उनकी तो केवल रिपेयर ही करवानी थी। शहरों की सड़कों की हालत बहुत खराब है। शहरों में जो सड़कें मंडी तक जाती हैं उनके लिए यह निर्णय लिया गया था कि उनकी मुरम्मत पर मार्किटिंग बोर्ड 2 लाख 40 हजार रूपए खर्च करेगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह धन स्वीकृत हो चुका हे? यदि स्वीकृत नहीं हो सका है तो उस पैसे की स्वीकृति दे कर कब तक काम भुरू करवा दिया जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मार्किटिंग बोर्ड से सम्बन्धित जितने लिंक रोडज हैं उनकी मुरम्मत का काम शुरू किया जा चुका है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस दौरान में कितनी लम्बी सड़कें बन चुकी हैं और कितनी कितनी सड़कें अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं? जो सड़कें अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं वे कितनी लम्बी हैं और वे कम तक बन कर तैयार हो जाएंगी।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: सरकार ने ऐसी 900 कि.मी. लम्बी सड़कें बनाने का फैसला लिया था। इस साल 50 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर काम चल रहा है और इनमें से 90 किलोमीटर सड़कें इस साल के अंत तक मुकम्मल हो जाएंगी। मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि कुछ सड़कें

अन्डर कन्स्ट्रक्शन है, कुछ पर अर्थ वर्क हो चुका हैं, कुछ पर पत्थर बिछाया जा चुका है और कुछ की सोलिंग हो चुकी है।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह फैसाल लिया गया था उस वक्त मार्किटिंग कमेटी जीन्द ने भी कन्डेला से कैरखेड़ी, अहिरला से झांज, जुलानी से झांज, संगतपुरा से झांज, मनोरपुर से वासाना, राजपुरा से इन्दल खुर्द, जलालपुर कलां से जुलानी और कईस से जलालपुरा तक सड़कें बनाने का फैसला किया था लेकिन इन सड़कों पर आज तक काम आरम्भ नहीं हुआ है जबकि ये सारी सड़कें आपस में 200–200 मीटर से अधिक फासले की भी नहीं है। जो सड़कें मैंने बताई हैं इन पर एक इंच भी काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी कांस्टिच्यूंसी की बात कर रहे है?

श्री परमा नन्द: मैं अपनी ही कांस्टिच्यूंसी की बात कर रहा हूं?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो एक गांव से दूसरे गांव को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया है वह पहले वहां के लिए लिया गया है जहां पहले कोई गांव किसी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ। अगर यै उस गांव को जो पहले ही किसी सड़क से जुडा

हुआ है, किसी दूसरे गांव से सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं तो वह अभी संभव नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टिच्यूंसी के अन्दर मार्किटिंग बोर्ड ने जो सड़कें मन्जूर की थीं उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। वैसे यहां हिसार जिले का जिकर नहीं है।

Mr. Speaker: Comrade Sahib, it is not possible to reply to this question off hand. The main question is regarding the contruction of roads by Haryana State Agricultural Marketing Board and it is humanly impossible to reply to your general question off hand.

कामरेड हरपाल सिंह: यह सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में सवाल पूछा गया था। अध्यक्ष महोदय, क्या ये बताएंगे कि मेरे हल्के के अन्दर जो सड़कें मन्जूर की थीं, उनका क्या हुआ?

Mr. Speaker: Comrade Sahib, as I said earlier, it is not possible to reply to this question.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी की जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनके टोहाना हल्के में भी काजूवाला सड़क पर काम चल रहा है और इसकी लम्बाई साढ़े सात किलोमीटर है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड जो सड़कें बना रहा है वह खुद बना रहा है या पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से बनवा रहा है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब हाउस को जोड़क सड़कों के बारे में बता रहे हैं। इसी सवाल के बारे में बहन कमला जी ने बताया है कि जब मार्किटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया तो उस समय शहरों की जो सड़कें गांवों के साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी बनाने का निर्णय लिया गया था। जो सड़कें गावों की शहरों के साथ लिक्ड हैं उनसे गांवों के लोग अपनी उपज लाते ले जाते हैं। वे काफी टूटी हुई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी टूटी हुई सड़कों पर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटी से संबंधित जो सडकें हैं उन के बनाने में शहर और देहात की कोई तमीज नहीं रखी गई है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिन सड़कों की सूची इन्होंने यहां रखी है उसके अनुसार महेन्द्रगढ़ जिले के कोई सड़क नहीं बनी हे। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर काम शुरू नहीं किया गया है या वहां के लिए अभी पैसा मुकर्रर

नहीं किया गया है? दूसरे जिन सड़कों पर वहां काम शुरू किया जाना है उन पर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो सूची मैंने रखी है उसमें लिखित सभी सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। कुछ सड़कें इस साल में मुकम्मल हो जाएंगी और कुछ अगले साल में मुकम्मल हो जाएंगी।

Recruitment of Drivers and Conductors in Transport Department

***1099. Sh. Yogesh Chand Sharma**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state –

(a) the total number of Drivers and Conductors recruited on ad-hoc and on 89 days basis by the Transport Departemnt during the period from 1st June, 1987 to data; and

(b) the names and addresses of persons alongwith their initial place of recruitment as referred above togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and ex-servicemen out of those referred to in part (a) above\

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

Interim reply

Home

“Prof. Sampat Singh

मंत्री,

विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़।

Dated:

16.3.1990

Subject: **Starred Assembly Question No. 1099.**

Dear Sh. H.S. Chatha Sahib,

Reply to the Starred Assembly Question No. 1099 by Sh. Yogesh Sharma, MLA is due reply on the 19th March, 1990. The reply involves collection and consolidation of the information pertaining to the recruitment of drivers and conductors on adhoc and 89 days basis for a period of three years alongwith their names and addresses and place of recuitment. This information has to be collected from various depots of Hayrana Roadways as General Managers are the Appointing Authorities for the Drivers and Conductors. Under these circumstances, I would request you to kindly grant an Under these cirucumstances, I would request you to kindly grant an extension of three weeks time for furnishing the reply to this question.

Yours sincerely,

Sd/-

(SAMPAT SINGH)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

CHANDIGARH."

तारांकित प्रश्न संख्या 1102

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, डा. बृज मोहन, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Breaches in Dam

***1104. Ch. Mahender Partap Singh**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that the breaches occurred in the Dam of Village s Lalpur and Sherpur due to floods during the year 1987-88 and 1988-89; and

(b) if so, the details of damages caused thereform togetherwith the steps, if any, taken or porposed to be taken to check the re-occurrence of breaches?

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री सचदेव त्यागी):

(क) वर्श 1988 की बाढ़ में केवल लालपुर गांव के सामने बंध में कटाव हुआ।

(ख) कटाव के कारण फसलों को कोई नुक्सान नहीं हुआ था लेकिन लालपुर और शेरपुर गांवों की ढानी में बने कुछ कच्चे घर प्रभावित हुए थे।

वर्श 1989 के बाद से पहले बचाव उपायों के तौर पर 20.77 लाख रूपये की लागत से साल स्टडज बनाए गए थे और नदी के किनारे के साथ पत्थर लगाये गये थे।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप फिर कहेंगे कि सीधी सप्लीमैंटरी नहीं की जा रही है इसलिए मैं पहले आपसे व्यवस्था चाहूंगा। पहली बात तो जो सवाल मैंने किया वह सवाल इसमें नहीं है। जो सवाल मैंने किया था उसकी कापी मेरे पास है। जो सवाल मैंने पॉद था उसमें ''दरार'' शब्द नहीं था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब के भाग ''ख'' में लिखा है कि कटाव के कारण फसलों को कोई नुक्सान नहीं हुआ था। जहां तक कटाव का सम्बन्ध है, किडावल गांव के पास बांध में 100 मीटर का कटाव आज भी देखा जा सकता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी नसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कटाव उनके नोटिस में है? जहां तक फसलों के नुक्सान की बात है, इस बारे में मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट

लैवल पर गिरदावरियां हुई हैं और क्या फसलों को हुए नुक्सान के बारे में इनके पास कोई रिपोर्ट आई है?

श्री सचदेव त्यागी: वर्श 1987–88 में कोई ड्रौट या फलड नहीं आया। वर्श 1988–89 में फल्ड आया था जिससे यह बांध टूट गया था लेकिन इससे फसल को कोई नुक्सान नहीं हुआ। लेकिन दो गांवों की ढानी में कुछ कच्चे मकान थे जिनको नुक्सान हुआ था। इन ढानियों में जो नुक्सान हुआ था उसका पूरा मुआवजा दिया गया है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी भी यह कह रहे हैं कि फसलों को नुक्सान नहीं हुआ। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, 1988–89 में कटावा से दो गांव बहुत खराब हुए थे। मैं माननीय मंत्री जी से हय जानना चाहूंगा कि क्या जिला प्रशासन की ओर से इन्हें कोई रिपोर्ट मिली है या नहीं मिली है, यदि नहीं मिली है तो इसका क्या कारण है?

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया है कि फसल का कोई भी नुक्सान नहीं हुआ है। 1988–89 में किडावल गांव के पास बांध टूट गया था परन्तु उसके कारण कोई भी फसल खराब नहीं हुई थी।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में माननीय मंत्री महोदय फिर फरमा रहे हैं कि कोई नुक्सान नहीं हुआ। मैं गुजारिश करूंगा कि यह सही स्थिति नहीं है। मैं आपके

माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात इनकी जानकारी में नहीं है या कि ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूं यह बात इनकी जानकारी में होनी चाहिए। जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी कोई जांच की गई है? क्या कोई लाईन औफ ऐक्शन तैयार की जाएगी ताकि जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई की जाए?

श्री अध्यक्षः चौ. महेन्द्र प्रताव जी, गिरदावरी का मामला तो रैवेन्यू डिपार्टमैंट से सम्बन्ध रखता है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी से ही तो तय होगा कि कितनी फसला को नुक्सान हुआ है। यह गिरदावरी ही तो मुआवजे का आधार होती है। माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि कोई नुक्सान ही नहीं हुआ जब कि मैं कह रहा हूं कि नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि सरकार इसके लिए कोई कमेटी या आयोग मुकर्रर कर दे ताकि सच्चाई सामने आ जाए और आगे के लिए भी व्यवस्थ सुधर जाए।

श्री सचदेव त्यागीः अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1988 में जो फ्लड आया उस समय उससे कोई कटाव नहीं हुआ और न ही किसी मकान को कोई नुक्सान पहुंचा। जो कच्ची ढानियां खेतों में होती हैं उनको जरूर नुकसान हुआ था और उनके लिए प्रभावित गांवों को मुआवजा दिया गया है। गांव दसिया में 10000 रूपये,

गांव शेर पुर में 8 हजार रूपये और गांव लालपुर में 6 हजार रूपये का मुआवजा दिया गया है। इस इलाके में कोई कटाव नहीं हुआ। किडावल गांव में सितम्बर के फलड से जो कटाव हुआ है, उससे कोई भी गांव या फसल प्रभावित नहीं हुई। इससे वहां की जनता बहुत खुश है। लौग कहते हैं कि कटाव से हमें पानी मिल रहा है। कटाव के कारण आबादी को कोई खतरा नहीं। वहां की जनता खुश है। वे चाहते हैं कि खेतों में पानी आए। वहां के लोग इस बात से खुश हैं लेकिन पता नहीं मेरे भाई कहां रहते हैं। वहां की जनता यह डिमांड करती है कि खेतों में पानी आये।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा सदन का गुमराह करने के कारण मैं फिर से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने अभी कहा कि पता नहीं वे कहां रहते हैं। मैं इस बारे में कहता हूं कि एक कमेटी बना दी जाये, वह कमेटी वहां जाकर पता करे कि वहां के लोग खुश हैं या दुखी हैं। इस बारे में जांच हो जाये और मेरी मांग है कि अगर मैं गलत हूं तो हाउस मुझे दण्ड दे और मैं उसे सहर्श स्वीकार कर लूंगा लेकिन मंत्री जी गलत हुए तो फिर वे भी दण्ड के अधिकारी होंगें। (शोर एवं विघ्न) ये कब तक गलतब्यानी करते रहेंगे। इस तरह की बात इन्हें नहीं करनी चाहिए।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, अगर जवाब इनकी इच्छा के अनुसार न आये और सच्चाई पर आधारित हो तो ये भड़कने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी के बारे में इन्होंने कहा

कि वे गलतब्यानी कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। इन्हें सवाल सोच समझ कर पूछना चाहिए। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह ठीक दिया है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, ये फिर गलत कह रहे हैं। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब सही नहीं दिया गया। अगर मेरी बात सही नहीं है तो मैं दण्ड का अधिकारी हूं।

Mr. Speaker: Mahender Partap Ji, please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर सर, अभी गृह मंत्री महोदय ने बताया कि जब किसी सवाल का जवाब हमारे अनुरूप नहीं आता है तो हम भड़क उठते हैं। क्या मेरे सवालों के लिए मंत्री महोदय कोई कमेटी बना कर उनके सारे फैक्टस में जाने की कोशिश करेंगे?

Mr. Speaker: It is not supplementary. Please take your seat.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, कोई कमेटी आप ही बना दें। आप ही इस बात को देख लें और आप ही फैसला कर लें।

Mr. Speaker: Mahender Partap ji, it is for me to see, I am not going to do anything as dictated by you. Please take your seat.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: * * * *

Mr. Speaker: This is not to be recorded. Please take your seat.

Occupation of P.W.D. Land

***1083. Sh. Ved Singh Malik**: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether it is a fact that Vidya Devi Jindal Public School, Mayar in District Hisar has occupied P.W.D. land; if so, the action if any, taken or porposed to be taken to get back the possession of said land?

Public Works Minister (Sh. Om Parkash Bhardwai): No land belonging to P.W.D. (B&R) has been occupied by Vidya Devi Jindal Public School near village Mayar in District Hisar.

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई निशानदेही करायी है और करायी है तो कब करायी है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) की जमीन पर जिन्दल पब्लिक स्कूल ने कोई कब्जा नहीं किया है।

श्री वेद सिंह मलिक: मैं निशानदेही की बात पूछ रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: सवाल तो कब्जे का है, पता नहीं ये निशानदेही कहां से करवाना चाहते हैं?

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में कोई ऐसी जगह है जहां पी.डब्ल्यू.डी. की जगह पर किसी प्राईवेट एजेन्सी द्वारा कब्जा किया गया हो या आपके पास कोई कम्पलेन्ट हो?

Mr. Speaker: It is not possible to reply this question off hand.

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि क्या इस स्कूल ने पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन पर कब्जा किया है, अगर किया है तो कब किया है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: मैंने बताया है कि कब्जा ही नहीं किया हुआ हे।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने श्री वेद सिंह मलिक के प्रश्न का जो जवाब दिया है, वह यह है कि वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बात को देखने के लिये कि वाकई नाजायज कब्जा हुआ है या नहीं, निशानदेही करवायी गयी है या नहीं। अगर नहीं करवायी गयी है तो किस आधार पर इन्होंने यह कहा है कि कब्जा वहां पर नहीं हुआ है और क्या वह निशानदेही करवाने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने प्रश्न के लिखित उत्तर में यह कहा है और

मौखिक रूप में भी जवाब दिया है कि वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. की किसी जमीन पर इस स्कूल द्वारा कोई कब्जा नहीं किया गया है। इस स्कूल को लेकर हमें किसी प्रकार की कोई कम्पलेंट नहीं आयी है जिसमें यह कहा गया हो कि पी.डब्ल्यू.डी. की कोई जमीन दबायी गयी हैं। ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो बाकायदा इन्कवायरी की जायेगी।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को यह पता होगा कि प्रभावशाली जो लोग होते हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमैंट में कोई कम्पलेंट नहीं करता और जब सरकार के नौलेज में भी यह बात आ गयी है कि वहां पर कब्जा हो रहा है तो सरकार क्या ऐसे नाजायज कब्जे को प्रभावशाली लोगों के कब्जे से निकलवाने की कोशिश करेंगी?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: सर, अगर सरकार के सामने कोई भी शिकायत आयेगी, चाहे वे कितनी भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, सरकार उसकी बाकायदा इंकवायरी करवाने की जिम्मेवारी लेती है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन ही कम्पलेंट है .....

श्री अध्यक्ष: आपने इसका जवाब भी तो पढ़ लिया है। He has said that no land belonging to PWD (B&R) has been occupied by Vidya Devi Jindal Public School.

कामरेड हरपाल सिंह: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये उसकी निशानदेही कब तक करवा लेंगे?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती क्योंकि वहां पर नाजायज कब्जा ही नहीं है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल के आस–पास पी.डब्ल्यू.डी. की कोई जमीन है?

Mr. Speaker: This is the relevant question.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मैमबर साहब को यह बताना चाहूंगा कि यह जो स्कूल है, यह नेशनल हाई वे न. 10 पर हिसार के माइड़ गांव के रकबा में है। सारे का सारा सड़क का एरिया जो इस स्कूल और सड़क के बीच में है, वह पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का है। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की एक इंच जमीन भी इस स्कूल के नीचे नहीं दबी हुई है।

General Hospital at Ambala City

***1095. Sh. Shiv Parshad**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the construction work of General Hospital, Ambala City has been started, if not the reasons therefor?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): हां।

श्री शिव प्रशाद: स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह पता होगा कि अम्बाला के इस हौस्पिटल का शिलान्यास फरवरी, 1980 में रखा गया था। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक के डोनेशन से और आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल ने मैंचिग ग्रान्ट की पालिसी के तहत इसके लिये पैसा देकर वहां पर टी.बी. ब्लौक तो बना दिया है लेकिन सरकार की तरफ से इसका निर्माण कार्य अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस हस्पताल को कब तक पूरा करवा देंगे और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मैम्बर महोदय की जानकारी के लिये अम्बाला सिटी के अस्पताल के बारे में यहां पर बताना चाहता हूं। यह अस्पताल 242. 90 लाख रूपये की लागत से बनना है और इसके लिये सरकार की तरफ से 31.12.1987 तक 66.86 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं। ज्यों–ज्यों सरकार पैसा खर्च करने की पोजीशन में होगी, उस पर काम जारी रखा जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा: क्या आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करैंगे कि इस अस्पताल के लिये अम्बाला में जनता ने कितना कान्ट्रीब्यूशन इक्ट्ठा किया और किस अधिकारी के प्रोत्साहन के बलबूते पर यह इकट्ठा हुआ है और सरकार ने

उसको प्रोत्साहन देने की नीहत से क्या कोई प्रशंसा पत्र या सर्टीफिकेट दिया है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास इस प्रकार से जो भी कोई पैसा डोनेट करता है, वह और उसके साथ सरकार द्वारा मैचिंग ग्रान्ट पालिसी के तहत कुछ पैसा डालकर इस प्रकार के कामों पर खच्र किया जाता है। जैसे अभी भी करनाल में इस प्रकार का एक अस्पताल बन रहा है। इससे पहले अपना अस्पताल के नाम से अम्बाला में एक अस्पताल बन रहा है और इसके लिए अम्बाला के लोगों की तरफ से 17 लाख रूपया आया हुआ है।

श्री शिव प्रशाद: अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जितना पैसा खर्च हुआ है यह केवल रैलीडैंशियल क्वार्टर्ज पर खर्च हुआ है। अपना अस्पताल के लिए अम्बाला के लोगों की तरफ से जो डोनेशन आया है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से ग्रांट के तौर पर जो पैसा आया उससे तो टी.वी. ब्लौक बना है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट सैन्टर है और इसके साथ साथ बहुत से देहात लगते हैं। वहां पर अस्पताल न होने से लोगों को काफी परेशानी है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब यह अस्पताल 1980 में सैंक्शन हो गया था तो इसको कितने दिन में बनाने का प्रयत्न किया जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि यह अस्पताल जल्दी से जल्दी बने लेकिन इसके लिए पैसे की कमी है। पैसे की कमी इसके बनने के रास्ते में बाधा है। ज्यों–ज्यों बजट के हिसाब से पैसा सैंक्शन होता जाएगा उस पर खर्च होता जाएगा।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, करनाल में 3 जनवरी को अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। उस वक्त यह कहा गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर इस पर काम शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल पर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बजाज साहब का मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि मूल प्रश्न अम्बाला के बारे में है लेकिन मैं बजाज साहब को बताना चाहूंगा कि एक सोसायटी बनी हुई है और शायद उसका नाम नागरिक विकास परिशद है और इसके वाइस प्रैजीडैंट श्री लक्षमण दास बजाज हैं। उस दिन 34 लाख के करीब रूपया इन्होंने दिया था और सरकार ने उसको दुगना किया और इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी कुछ पैसा दिया था। उस दिन यह तय हुआ था कि इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यदि उस पर काम शुरू नहीं हुआ है तो इस बारे में पता करवा लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी काम शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री शिव प्रशाद: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल की कस्ट्रक्शन के लिए कितनी राशि रखी गई है और क्या अम्बाला के लिए अधिक धनराशि देकर उसको प्राथमिकता दी जाएगी?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो पैसा जिस विभाग के लिए सैंक्शन होता है उसको उसी रेशो से पैसा दिया जाता है। किसी को प्रैफरैंस देना और किसी के साथ दूसरा रवैया अख्तियार करना, हमारी सरकार यह नहीं करती।

चौ. सतबीर सिंह कादियान: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि करनाल में 1983 में जिस अस्पताल की फाउंडेशन रखी गई थी उसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा?

Mr. Speaker: It is not possible to reply this question off hand.

C.M.O. Office in District Yamuna Nagar

***1105. Smt. Kamla Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration to the Government to open an office of the Chief Minister Officer in district Yamuna Nagar; and

(b) if so, the time by which the said Office is likely to be opened?

मुख्य मंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां।

(ख) शीघ्र ही।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, जब से यमुनानगर जिला बना है तब से वहां पर डी.सी. का औफिस और एस.पी. का औफिस तो बन गया है लेकिन वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का औफिस नहीं बना है? क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उसका क्या कारण है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वहां पर इसके लिए फण्डज सैंक्शन हो चुके हैं और जल्दी ही यह औफिस बन जाएगा।

श्रीमती कमला वर्मा: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट सैंक्शन हो चुकी हे?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हां, पोस्ट भी सैंक्शन हो चुकी है।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं यह तो कांग्रेस के जमाने की घिसी पिटी भाशा है। इनको तो स्पश्ट भाशा में जवाब देना चाहिए कि कब तक यह काम हो जाएगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब से मैंने मुख्यमंत्री का पद भार सम्भाला है तक से मैंने यह कोशिश की है कि मुझे कोई टयूटर मिल जाए और यह प्रयास अभी भी जारी है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यभार संभालते ही एक वाक्य कहा था कि मैं अपने आदेशों की पालना दिनों में नहीं, घण्टों में नहीं बल्कि मिन्टों में चाहता हूं और लोगों की सुविधाओं के हिसाब से भी उनकी यही राय है। स्पीकर साहब, जो तीन नये जिले बने हैं उनमें डी.सीज. व पुलिस एस.पीज. तो चले गये हैं परन्तु क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि इन जिलों में सी.एम.ओज., जिनका सम्बन्ध मैडिकल की सुविधाओं से है, भी चले गये हैं? अगर नहीं गये तो कब तक इन तीन जिलों में लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए सी.एम.ओज. पहुंच जाएंगे ताकि लोगों को मैडिकल की पूरी सहूलियतें प्रदान की जा सकें।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि मैं पोस्टस सैन्कशन हो चुकी हैं और इसके लिये फण्डज भी अवेलेबल हो चुके हैं लेकिन चूंकि ये नये जिले बने हैं, इसलिये मकानों की, दफतरों की काफी दिक्कतें हैं। ज्यूं–ज्यूं ये सुविधाएं हमें मिलती जाएगी, हम पोस्टस भरते रहेंगे।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने टयूटर की बड़ी खोज की है

और उसके लिये उनकी कोशिश अभी भी जारी है लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ टयूटर नहीं होते, बल्कि सहयोगी हुआ करते हैं। क्या ये बतायेंगे कि ये टयूटर किस किस्म का चाहते हैं और इनका इस बारे में क्या प्रयास है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: डाक्टर साहब, सहयोगी तो हम उम्र हुआ करते हैं। मुझे बुजुर्ग टयूटर भी चाहिये और तजुर्बेकार पालिटीशियन्ज की भी जरूरत है।

Mr. Speaker: Question list is over.

अतारांकित प्रश्न एंव उत्तर

Jindal Strips Ltd.

187. Sh. Ved Singh Malik: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Jindal Strips Ltd., Hisar filed an appeal before the arbitrator of Electricity Board in respect of claiming the tariff of its labour colonies; if not, the reasons therefor, togetherwith the legal action taken by the H.S.E.B. for violating the directions of the Court?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): मैसर्ज जिन्दल स्ट्रीप्स लिमिटिड हिसार द्वारा ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसे न दायर करने के कारण केवल फर्म को ही ज्ञात है। बोर्ड द्वारा कोर्ट के किन्हीं निर्देशों की उल्लंघना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss suffered by H.S.E.B.

188. Capt. Ajay Singh Yadar: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the profit earned or loss suffered by the Haryana State Electricity Board during the years 1988-89 and 1989-90;

(b) the total quantum of electricity supplied to Agriculture and Industrial sector and the tariff received from each sector, separately during the period as referred to in part (a) above; and

(c) the loss, if any, suffered togetherwith the steps, taken or proposed to be taken to eliminate/reduce the losses?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला):

(क) वर्श के दौरान बोर्ड द्वारा उठाई गई हानि निम्नलिखित थीः–

1988–89	54.4 करोड़ रूपये
1989–90	121.21 करोड़ रूपये (अनुमानित)

(ख) वर्श के दौरान कृशि सम्बन्धी तथा औद्योगिक क्षेत्रों को दी गई बिजली तथा प्राप्त किये गये प्रति यूनिट राजस्व की मात्रा निम्न प्रकार से थीः–

वर्श	कृशि सम्बन्धी क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र

	बेची गई यूनिटें (यूनिट मिलियल में)	प्राप्त की गई लागत/यूनिट (पैसों में)	बेची गई यूनिटों में हानि (पैसों में)	हानि (रूपये करोड़ में)
1988–89	2157.8	20.5	1535.3	115.3
1989–90 (12/89 तक)	2006.0	26.2	1080.5	125.9

(ग) कृशि को बिजली बेचने से बोर्ड को निम्न प्रकार से हानि हुई:–

वर्श	कृशि क्षेत्र की बेची गई बिजली (यूनिट मिलियन में)	प्राप्त की गई लागत/यूनिट (पैसों में)	प्रति यूनिट औसत लागत (पैसों में)	बेची गई यूनिटों में हानि (पैसों में)	हानि (रूपये करोड़ में)
1988–89	2157.8	20.5	84.5	63.55	137.12
1989–90 (12/89	2006.0	26.2	92.0	65.8	132.00

तक)					

हानि में कमी करने के लिए पग उठाए गए/उठाए जा रह है:–

(1) दिसम्बर, 1987 तथा सितम्बर, 1989 में बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ में संशोधन।

(2) राज्य सरकार के ऋणों में से 390 करोड़ रूपये के ऋण की वर्श 1988–89 के दौरान इक्वीटी पूंजी में परिवर्तित करना जिस से राज्य सरकार के ऋण पर प्रति वर्श 27 करोड़ के ब्याज दायित्व की कमी लाना है।

(3) राज्य सरकार के ऋण पर देय ब्याज को ग्रामीण विद्युतीकरण पर देय अनुदान के भाग से समंजित करना।

(4) प्रसार तथा विवरण हानि को निम्न माध्यम से कम करना –

(अ) नये ग्रिड उप केन्द्रों को जोड़कर।

(आ) प्रणाली सुधार।

(इ) एच.टी. कैपेसिटरों की स्थापना।

(5) नई भर्ती पर प्रतिबन्ध।

(6) बोर्ड के थर्मल प्लान्टों में कोयले तथा तेल के उपभोग में कमी करना तथा उनके बिजली उत्पादन में सुधार लाना।

(7) बिजली की चोरी को पकड़ना।

Upgradation of Schools in Rewari Constituency

189. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following schools from Primary to Middle, from Middle to High and from High to 10+2 system in Rewari constituency during the year 1990-91:-

Primary to Middle

(i) Bhatsana,

(ii) Jonawas,

(iii) Asiaki Panchor,

(iv) Rajpura Khalia,

(v) Kishangarh,

(vi) Malahera,

(vii) Phadni,

(viii) Dakiya,

Middle to High

(i) Tatarpur Istemurar,

(ii) Saharanwas,

(iii) Ramgarh Bhagwanpur,

(iv) Raliawas,

(v) Kapriwas,

High to 10+2 System

(i) Dharuhera,

(ii) Jadra,

(iii) Masani,

(iv) Jarthal,

(v) Padiawas,

(vi) Bikanar, and

(b) whether there is also a proposal under consideration of the Government to open primary school at Harinagar (near Dharuhear) in Rewari Constituency?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) भाग ''क'' में वर्णित विद्यालयों को स्तारोन्नत करने के लिए नौर्म के अनुसार वर्श 1990–91 के दौरान इस उदेश्य के लिए गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) अभी नहीं।

Construction of Booster Pumps in Rewari Constituency

190. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for P.W.D. (Public Health) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct separate Booster Pump in village Majra Sheoraj and in Ramgarh Bhagwanpur for the supply of water in the following villages in Rewari constituency –

(i) Kalaka,

(ii) Mandia Khalilpuri,

(iii) Bambad,

(iv) Phadni,

(v) Fedari,

(vi) Budana,

(vii) Budani, and

(b) if so, the time by which the Boosters as referred to in part (a) above are likely to be set up?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री महा सिंह):

(क) इन गांवों को मसानी समूह योजना के अधीन पहले ही जल वितरण हो रहा है। अतः अभी ऐसा कोई बस्टिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Vacancies in H.S.E.B.

191. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Irrigation and Power be to state –

(a) the category-wise number of posts filled by the Haryana State Electricity Board during the period from 1st July, 1987 to February, 1990; and

(b) the category-wise number of vacant posts lying in the Haryana State Electricity Board till February, 1990?

Interim reply

DOAQ 191/MIP

"OM PARKASH CHAUTALA

Chief Minister, Haryana,

Chandigarh.

March 16, 1990.

Subject: Unstarre Assembly Question No. 191 regarding category-wise number of posts filled and vacant posts.

Respected Speaker Sahib,

In the above mentioned Assembly Question Hon'ble Member has sought to know the number of posts filled by State Electricity Board, categorywise, during the period from

1st July, 1987 to February, 1990 and the number of posts lying vacant, categorywise,in February, 1990.

2. The categories involved and more than 300 comprising more than 40000 sanctioned posts. Besides, there are several appinting authorities from which the desired information is to be collected. According, it would take us quite some time before we are able to collect the desired information. In the cirucumstances, I would request you to allow the Government 3 months time to reply to this question.

With highest regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Om Parkash Chautata)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana, Vidhan Sabha,

Chandigarh."

विभिन्न विशयों का उठाना जाना

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को क्वैश्चन, आवर, में श्री योगेश शर्मा जी का एक क्वैश्चन आया था कि पंचायतों की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है और यह

सारा इलाका दिल्ली के आसपास फरीदाबाद व गुड़गांव से सम्बन्धित है जिस बारे में आज अखबारों में भी आया है। (शोर)

Mr. Speaker: I do not take notice of the newspapers.

श्री दुर्गादत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, उसके उत्तर में इन्होंने यह कहा था कि पंचायत ने कोई जमीनें बेची ही नहीं है। इसलिए मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि जो पंचायतों की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कर रही है?

Mr. Speaker: Please take your seat.

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वैश्चन डिजनी लैण्ड के बारे में था जिसको बाद में अम्यूजमेंट पार्क भी कहा गया था। उस पर आपने फरमाया था कि 10 तारीख तक के सारे क्वैश्चन आपने ऐडमिट कर लिये हैं। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि मेरा नाम फिर उस लिस्ट में से वंचित क्यों रहा गया?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आज तो हाफ एन आवर डिस्कशन वाली बात है। डिजनी लैण्ड वाली बात तो फ्राई डे को थी।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात क्वैश्चन आवर में तो पूछ नहीं सकता था। इसलिये मैं आज पूछ रहा हूं

जी कि क्या उस लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल कर लिया जाएगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, हाफ एन आवर डिस्कशन वाला प्रोसीजर तो अलग है। आप तो बड़े ही समझदार हैं। मैंने तो आपसे लर्न करना है। हाफ एन आवर डिस्कशन वाला प्रोसीजर डिफरैन्ट है और क्वैश्चन आवर वाला प्रोसीजर डिफरैन्ट है।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरी तो सबमिशन है कि (शोर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, मैं तो यह कह सकता हूं कि आप बहुत जागरूक हैं।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है जी कि मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है जब कि मैंने क्वैश्चन टेबल किया था। I have been deprived of my right, Sir, My name must have been included in the list.

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, यह लिस्ट पहले निकल चुकी थी परन्तु आपका क्वैश्चन बाद में आया। 6 मैम्बर्ज के सवाल आए थे और वे 6 के 6 एक ही लिस्ट में लग गये। आपके सप्लीमैंटरी भी की थी।

Dr. Mangal Sein: I was not allowed, Sir. Today I may be allowed, Sir. जब टाईम आए तो आप मुझे बोलने के लिए इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे कमिट मत करवाएं।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक शार्ट नोटिस क्वैश्चन दिया था। बिजली के कनैक्शन काटे जा रहे हैं जिससे पैदावार का बहुत नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने आर्डिनरी सवाल के रूप में ऐडमिट कर लिया है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, अगर वह 29 तारीख को लगा तो उसका क्या फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, वह तो नम्बर पर ही आएगा।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैंने दो बच्चों को उठाए जाने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष: बहिन जी, जब मैं फ्री हो जाऊं तो उस बारे में मेरे से मेरे चैम्बर में बात कर लें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी डा. साहब कुछ कह रहे थे तो आपने कहा कि मुझे आपसे लर्न करना है। मुख्य मंत्री जी टयूटर रखना चाहते हैं। तो यह कितनी बड़ी क्लास है, ताकि मैं भी इसमें भरती हो जाऊं। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यदि चौ. वीरेन्द्र सिंह उस क्लास में आ गए तो वह क्लास ही चली जाएगी। (हंसी)

श्री परमान्द: * * * *

Mr. Speaker: Thisis not to be recorded. Prof. Sahib, please take your seat. (Interruptions) I would request everybody to take his seat. (Interruptions) I am not going to allow everybody. Prof. Sahib, you give me in writing. I will consider it.

Sh. Parma Nand: * * * *

Mr. Speaker: Prof. Sahib, nothing will come on record. You please take your seat.

Sh. Parma Nand: * * * *

Mr. Speaker: Prof. Sahib, there is some way as well as procedure. What is being said by you without my permission, that is not coming on record. So you please take your seat.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

असन्ध उप–मण्डल के कुछ गांवों को करनाल जिले में सम्मिलित करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of calling attention motion No. 15 form Sh. Jai Singh Rana, M.L.A., regarding merger of some village of Assandh Sub-Division in Karnal District. I admit it. He may please read

his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि असंध उप मंडल के कुछ गांव जिला करनाल में शामिल होने के इच्छुक हैं जिसके बारे में सम्बन्धित गांवों की पंचायतों ने भी अपने प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। करनाल के प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सभी वर्गों में भारी असन्तोश हे जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। यह जन महत्व का विशय है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि लोगों की उक्त उचित मांग को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित मंत्री इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करके सदन में वक्यव्य देकर स्थिति स्पश्ट करें।

वक्तव्य –

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

Revenue Minister (Rao Ram Narain): Speaker Sir, for more effective administration, public convenience and accelerated development, the State Government reorganised the districts/Sub Division and other units of administration. The new unit of administration started functioning with effect from 1-11-1989 As a result of reorganisation two Revenue Divisions namtely, Gurgaon and Rohtak and four new districts namely Yamuna Nagar, Kaithal, Rewari and Panipat were created. District Panipat was created by upgrading Panipat

Sub-Division of Karnal District and merging Assandth Tehsil of Karnal District with it after upgrading it as a Sub Division.

2. As a result of constitution of Panipat as a separate district, the two districts of Panipat and Karnal comprised as follows:-

S.No.	Villages	Area (in hectares)	Population
Panipat	235	175729	493974
Karnal	395	195592	806707

3. Before reorganisation on 1.11.1989, there were 48 villages with a population of 132988 in Assandh Tehsil which was merged with the new Panipat District. However, one village namely Gullarpur was retained on Karnal and another village Rahra was transferred to newly created district of Kaithal one the ground of proximity to Tehsil headquarters. Out of teh remaining 46 villages the Deputy Commissioner, Karnal has sent resolutions from Panchayats of 29 villages which want remerger with Karnal on account of cultural affinity and availability of better communication facilities. However, Deputy Commissioner Panipat has intimated that 13 villages of Assandh Sub Division want remerger with Karnal. 12 out of these 13 villages are also included inthe list of Deputy Commissiner Karnal and Panipat is required regarding the villages which are not common in their list. The State Government is, therefore, examining this matter.

4. Representations have also been received from other Panchayats and some official and non-official bodies regarding inter-district and intra-district transfer of more villages. All these proposals are under active consideration of the State Government.

5. I would, however like to apprise this august House that the Government of India, in the Ministry of Home Affairs in their instructions dated 10-5-89 have desired that in view of the next decenial population census, the State Government may ensure that no changes whatsoever are made in the boundaries of administrative/revenue units during the period from 1.1.90 to 30.6.1991.

6. I would like to assure this august House that when the readjustment of boundaries of the administrative/revenue units becomes permissible, the aspirations and convenience of the people will be kept in view.

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में कहा है कि जिला पानीपत और जिला करनाल के डी. सीज. की सूचियों में अन्तर है। मुझे इस बारे में जो पता है उसके मुताबिक जिला करनाल के डी.सी. को 45 गांवों की पंचायतों के रैजोल्यूशंज मिले चुके हैं जोकि जिला करनाल में ही रहना चाहते हैं। इसके अलावा एक गांव राहड़ा है, जो जिला कैथल में मिलाया गया है, लेकिन उस गांव की पंचायत का रैजोल्यूशन आया है कि उसको करनाल जिले में ही रहने दिया जाए। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन गांवों के लोगों की

भावनाओं का आदर किया जाएगा और उनको उनके रैजोल्यूशन के मुताबिक उसी जिले में रखा जाएगा?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, हमने दोनों डी.सीज. की कलैरीफिकेशन मांगी हुई है, ज्यों ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उस पर असल किया जाएगा।

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन दोनों डी.सीज. से इस बारे में रिपोर्ट कब तक मिलेगी और उस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर साहब, मैं इस बात को थोड़ी सी स्पश्ट करना चाहूंगा कौन सा गांव किस जिले में रहना चाहता है, कौन से सब–डिवीजन में रहना चाहता है और कौन से ब्लौक में मिलना चाहता है इस बारे में सभी गांवों की पंचायतें से रैजोल्यूशन मांगे हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको उनकी इच्छाओं के मुताबिक ऐडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी।

वर्श 1990–91 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्श 1990–91 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर डिस्कशन होगी।

पहली प्रैक्टिस में मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज (सं. 1 से 25) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों। डिस्कशन के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जायेंगी।

That a sum not exceeding Rs. 14939000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 425891000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1041845000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 146948000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 92888000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 520772000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 1180519000 for revenue expenditure and Rs. 2630000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 635946000 for revenue expenditure and Rs. 489555000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 3067003000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 504355000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 58100000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 221458000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 169412000 for revenue expenditure and Rs. 15304000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 43332000 for revenue expenditure and Rs. 1332923000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 1996550000 for revenue expenditure and Rs. 673359000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 220601000 for revenue expenditure and Rs. 68716000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in

the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 762587000 for revenue expenditure and Rs. 6350000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 762587000 for revenue expenditure and Rs. 6350000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 291937000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 31641000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 489599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 659591000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 82277000 for revenue expenditure and Rs. 190266000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 1549445000 for revenue expenditure and Rs. 178100000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 15258000 for revenue expenditure and Rs. 19000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2182070000 for revenue expenditure expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

श्री टेक चन्द (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड न. 8 पर बोलनो चाहता हूं। इस डिमांड के तहत पी.डब्ल्यू. डी. के लिए धन राशि मांगी गई है। यह राशि 63 करोड़ 59 लाख

और 46 हजार के करीब बनती है। मैं चाहता हूं कि यह राशि मन्जूर होनी चाहिए। जो भाई ये कह रहे थे कि हरियाणा में कोई विकास कार्य आरमीा नहीं हो रहा उनकी जानकारी के लिए अभी सवालों के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 900 किलोमीटर लम्बी सड़कें मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जानी हैं और इसके अलावा करीब 250 किलोमीटर लम्बी सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इस साल के दौरान बनाई जाएंगी। पिछले वर्श भी पी.डब्ल्यू.डी. ने 400 कि.मी. लम्बी सड़कें बनाई थी। मेरे भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा, वह इस बात से जाहिर हो जाता है कि कितनी लम्बी सड़कें बनाई जा रही हैं और कितनी बन कर पूरी हो चुकी हैं। इन सारे आंकड़ों से उनकी बात निराधार हो जाती है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड ने सड़कों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपया पिछले वर्श खर्च किया ओर 6 करोड़ रूपया इस साल खर्च कर रहा है जिससे सड़कें बनाई जानी हैं, औफिसिज बनाये जाने हैं या रैस्ट हाउसिज आदि बनाये जाने हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न. 9 जो ऐजूकेशन से संबंधित है, बोलना चाहता हूं। पिछले साल भी हमारी सरकार ने काफी स्कूल अपग्रेड किए थे। 100 से करीब लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किये गए थे। इनमें से 50 लड़कियों के मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड किए गए थे। इसके अलावा करीब 100 प्राईमरी स्कूल भी अपग्रेड किए गए थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले

साल भी 25 हाई स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अपग्रेड किया गया था और जो 25 प्राईवेट स्कूल थे उनको 10+2 बनाया गया था। मेरे कहते का मतलब यह है कि हमारी सरकार शिक्षा की तरफ विशेश ध्यान दे रही है। मेरी सरकार से मांग है कि जो भी नए स्कूल बनाये जा रहे हैं या अपग्रेड किए जा रहे हैं उनकी बिल्डिंगज भी बनाने के लिए सरकार को ध्यान दनेा चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी ऐजूकेशन का स्तर इस समय काफी गिरता जा रहा है। आज के दिन टीचरों और बच्चों में अनुशासन कम होता जा रहा है। स्कूलों में न तो बच्चों को बैठने के लिए टाट मिल रहा है न बैंच ही उपलब्ध हो रहे हैं और न ही ब्लैक बोर्ड स्कूलों में हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि वे इस और विशेश ध्यान दें। पहले स्कूलों में काफी अधिक नकल होती थी। इस दिशा में जरूर कमी हुई है। फिर भी मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इन सब बातों की ओर विशेश ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी सरकार से मांग है कि जिन स्कूलों की बिल्डिगंज पी.डब्ल्यू.डी. ने अनसेफ डिक्लेयर कर दी हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी नई बिलिंडगे बनाई जानी चाहिए। मेरे हल्के के एक गांव खरड़वास की 3–4 साल पहले स्कूल की बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर की गई थी, उसके बनाये जाने की मन्जूरी भी हो चुकी है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। इस काम के लिए मेरे ख्याल में 14 लाख 40 हजार रूपया मन्जूर हो चुका है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न. 10 के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारी सरकार ने काफी मात्रा में हौस्पिटल बना रखें हैं। हमारे यहां पर डाक्टरों की भी कोई कमी नहीं है लेकिन मरीजों को जिस मात्रा में दवाई मिलती चाहिए वह नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के लिए जो मदद सरकार की ओर से देते हैं वह सफिशियंट नहीं है। एक रूपया पांच पैसे की मदद प्रति व्यक्ति को चिकित्सा के लिए दी जाती है जो कि बहुत ही कम है। गरीब आदमी दवाईयां खरीद नहीं सकते इसलिए गवर्नमैंट की ओर से दवाईयों के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कम से कम डबल किया जाए ताकि गरीब आदमी को अस्पतालों में फ्री ट्रीटमैंट मिल सके। बड़े–बड़े अस्पतालों में जो दवाईयां दी जाती हैं डाक्टर्ज उन दवाईयों को दुकानों पर बेच देते हैं और फिर गरीब मरीजों को दवाईयां उन दुकानों से खरीदनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अस्पताल की जो दवाईयां डाक्टरों द्वारा बाहर बाजार में बेची जाती हैं उस बारे चैकिंग की जानी चाहिए और दोशियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेना चाहिए। रोहतक मैडिकल कालेज में पहले मरीजों को प्रतिदिन दूध और दलिया मिलता था। दूध और दलिया हल्का खाना है जोकि मरीजों के लिए बढ़िया माना जाता है। पहले यह दूध और दलिया गरीब आदमियों को फ्री मिलता था और हर रोज मिलता था लेकिन आजकल कभी–कभी मिलता है, इस बारे में मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अर्बन एरियाज में मार्किटिंग बोर्ड की ओर से शहरों की सड़कों के लिए 2 करोड़ 32 लाख रूपये अतिरिक्त मांगे गये हैं। मार्किटिंग बोर्ड की ओर से शहरों की सड़कों की डिवैल्पमैंट के लिए मार्किट कमेटीज को पैसा देते हैं और जिनका डिमांड हमारे पास आई थी उनको हमने पैसा भेज दिया लेकिन जिनकी डिमांड नहीं आई उनको पैसा नहीं भेजा। जिस कमेटी ने जितना पैसा मांगा हमने उसे उतना पैसा दिया है 38–40 शहरों में से 20 के लगभग ऐसे शहर हैं जिनमें सड़कों की रिपेयर नहीं है लेकिन जो सड़कें मण्डी को देहात के साथ जोड़ती है उन सड़कों की स्पैशल रिपेयर के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्पैशल आदेश दिये हैं। स्पैशल रिपेयर में 50 या 60 हजार रूपये प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है जबकि रिपेयर का खर्चा 16 हजार रूपये प्रति किलोमीटर आता है। जो सड़कें बहुत ज्याद टूटी–फूटी हैं और साधारण रिपेयर से जिनका काम नहीं चला सकता उनकी स्पैशल रिपेयर के लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। मुख्यमंत्री जी की परपोजल पर हमने बोर्ड की मीटिंग में इसे पास कर दिया है कि जो सड़क मण्ड़ी को लिंक करती है उसके लिए पूरा धन दिया जाएगा और स्पैशल रिपेयर की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सोशल वैल्फेयर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि चौ. देवी लाल जब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए

और समाज के हर वर्ग के लिए अनेकों कार्य किए और उनकी मदद की है। गांवों में हरिजनों को अपनी बारात वगैरा ठहराने के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं थी। चौ. देवी लाल ने 1977–78 में 1200–1400 हरिजन चौपालेां का निम्रण करवाया ताकि हरिजनों को अपनी बारात के मेहमानों को ठहराने के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सकते। चौ. देवी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले उनके दिमांग में यह बात आई कि हरिजनों के लिए चौपालें बनवाई जाएं। चौ. देवी लाल की तत्कालीन सरकार ने उनके लिए पैसे का प्रबन्ध किया। अध्यक्ष महोदय, पैंशन दिये जाने के बारे में मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 65 साल की आयु या उसके अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 100 करोड़ रूपये सरकार की और से खर्च किये जा रहे हैं। चौ. देवी लाल ने बुजुर्गो को पैंशन देकर देश को एक नई दिया दी है। हमारी मौजूदा सरकार इस प्रकार के कई अन्य समाज भलाई के काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जब चौ. देवीलाल कर्जे माफ करने की बात किया करते थे तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि कर्ज माफ नहीं किये जा सकते। सत्ता में आने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद चौ. देवी लाल ने अपना वायदा पूरा किया। दूसरी स्टेअस वालों ने हमारी स्टेट की नकल कर कर्जे माफी की घोशणाएं की हैं। कई दूसरे राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, उन्होंने भी नकल करके कर्जे माफी की घोशणाएं की जब कि पहले यही लोग कहा करते थे कि कर्जे माफ नहीं हो सकते। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात ले लीजिए चाहे महाराश्ट्र की यहां की कांग्रेस सरकारों ने कर्जे माफी

का आश्वासन दिया है। गुजरात और मध्यप्रदेश में तो अब हमारी सरकारों है। हिमाचल प्रदेश, महाराश्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों ने हमारी सरकार की तरह इस और ध्यान दिया है।

अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह, ने इस बात का ऐलान किया है कि दस हजार तक के कर्जे छोटे किसानों, छोटे मजदूरों ओर मेहनत करके रोटी खाने वालों के माफ किय जायेंगे। ये कर्जे कब माफ किय जायेंगे, इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का वीकर सैक्शन की और विशेश ध्यान है।

श्री अध्यक्ष: अब आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं इसलिए आप खत्म करें।

श्री टेकचन्द: स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने हरिजन बच्चों के लिए और भी सुविधायें दी हैं। जो हरिजन बच्चे स्कूल और कालेज में पढ़ते हैं उन्हें लेखन सामग्री में विशेश रियायतें दी हैं। जहां उन बच्चों को लेखन सामग्री के लिए पहले 15 रूपये मिलते थे वहां 30 रूपये कर दिये हैं, जहां 30 रूपये मिलते थे वहां 60 रूपये कर दिये हैं। इसी प्रकार से वजीफे के मामले में किया है। जिन बच्चों को वजीफा 50 रूपये मिलता था उसे 50 से 100 रूपये कर दिया है और 100 रूपये वाले को 200 रूपये कर दिया है। इस प्रकार के सारे डबल कर दिये हैं ताकि गरीब और वीकर सैक्शन के बच्चों की इमददा की जा सके। स्पीकर साहब,

पहले हरिजन बच्चों को वजीफा लेने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि हमारी आमदन दस हजार रूपये साल से कम है लेकिन अब हमारी सरकार ने दा हजार की छूट दे दी है। पहले उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं। ऐसा करने से हरिजन बच्चों को जो असुविधा होती थी, डिफिकल्टी आती थी, अब उसे कोई ऐफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं। सरकार ने यह झंझट ही मिटा दिया है।

अब स्पीकर साहब मैं होम डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। होम डिपार्टमैंट के लिए 1041845000 रूपया मागां जा रहा है। होम डिपार्टमैंट को यह पैसा दिया जाए लेकिन हरियाणा के सिपाही को सन् 1965–66 में जो तन्खाह मिलती थी वही एक जे.बी.टी. को मिलती थी। दोनो का बराबर मिलती थी लेकिन अब जे.बी.टी. को सिपाही से बहुत ज्यादा मिलती है। सिपाही को 1100 रूपये मिलती है और जे.बी.टी. को 1500 रूपय मिलती है। पुलिस विभाग में पिछले दिनों बगावत किस कारण से हुई, यह दुखने वाली बात है। किसी की लड़ाई किस कारण से होती है उसकी गहराई में जाने की बात है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि उसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो वह बगावत करेगा! जिस आदमी का पेट भूखा है, वह बगावत करेगा। वह स्टेट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बगावत करेगा इसलिए मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता कि उनकी तन्खाह बढ़ायी जाये। वे 24 घन्टे डियूटी देते

हैं। ला एंड आड्र की पोजीशन हमारे पड़ोसी प्रदेश में बहुत खराब है इसलिए यहां सिपाहियों को ग्रेड ठीक दिये जांये, हाउस रैन्ट ठीक दिया जाये बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उन जवानों को हरियाणा में एक वक्त का खाना भी फ्री होना चाहिए दिल्ली में एक सिपाही को 1500 और 1700 रूपये मिलते हैं जब कि हरियाणा में 1100 रूपये मिलते हैं। वह इसलिए मिलते हैं कि वह एक डिस्पिलिन फोर्स है और वे शोर नहीं करते लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर उनके मुंह बन्द हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनका हाउस रैन्ट और पे बढ़नी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

श्री टेक चन्द: सर, अभी खत्म करता हूं। अब मैं ऐक्साइज एंड टैक्सेशन की डिमांड के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सरकार की पालिसी है कि शराब के ठेके बढ़ाये जायें क्योंकि शराब से आमदनी होती है। इस विशय में एक अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कौम को, नेशन को खत्म करके हम पैसे की आमदन करे तो मैं इस आमदन की जरूरत नहीं समझता। हमें ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जिससे कौम और नेशन खत्म हो। हमने फौज और पुलिस में जवानों को भेजना है। अगर वे शराब पीते हैं तो उनकी सेहत कमजोर होगी। स्कूल और कालेज के बच्चों में शराब पीने की आदत पड़ जायेगी तो वे अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों की पंचायत

से यह रैजोल्यूशन आये कि हमारे गांव में या गांव के पास शराब का ठेका न खोला जाये तो वहां शराब का ठेका नहीं खोला जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमान्ड नम्बर एक पर अर्ज करना चाहता हूं जो विधान सभा के बारे में है। * * * * अब मैं डिमांड नम्बर तीन के बारे में अर्ज करता हूं। यह मांग होम की है। यहां इस सैशन में मेहम की बड़ी चर्चा रही। हरियाणा प्रदेश पंजाब का पड़ौसी राज्य है। गृह मंत्री महोदय ने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब में जब आतंकवाद से निर्दोश लाशें जलती हैं तो उनकी अग्नि की लपट हरियाणा के हरियाली तक पहुचती हैं।

हरियाणा भी कई बार उसमें झुलस जाता है। उसका इंतजाम करने के लिये हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुछ जीपें बगैरा देकर हरियाणा पुलिस को सुसज्जित किया है। पिछली कांग्रेस की सरकार के जमाने में हमको हथियार नहीं दिये। घटनाएं होती रहीं परन्तु अध्यक्ष जी, जो कुछ मेहम में हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां पर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथी रहे हैं। डा. मंगल सैन और चौ. देवीलाल की रहनुमाई में हमने जब 5 दिसम्बर, 1986 को संघर्श शुरू किया, उस समय मुझे याद है कि चौ. देवी लाल और डा. मंगल सैन ने हिसार से पद यात्रा शुरू की थी। जब वद पद–यात्रा शुरू हुई, उसमें हम नारनौल से चले औ काफिला मेहम आया तो

यह वही बहादुर लोग थे जिनमें औरतों क्या, बच्चे क्या, बूढें क्या, उन्होंने अपने खून से आदरणीय चौ. देवी लाल को तिलक लगाया था। अध्यक्ष महोदय, जब आज वहां पर चुनाव हुआ, तो क्या हुआ कैसे हुआ वह एक मामला जेरे गौर है और चुनाव आयोग के अधिकारी यह कहें, मिस्टर रंजन और मिस्टर आर.पी. भल्ला यह कहें कि हमने एक डी.एस.पी. को ठप्पे लगाते हुए पकड़ा है, इससे हमारी हरियाणा पुलिस की गरिमा और हरियाणा की प्रतिश्ठा कम हुई है। हम चाहे अपनी जुबान से कुछ भी न कहें लेकिन प्रजातन्त्र मे लोग सही अदालत होते हैं। हर राजनीतिक गतिविधि का असर उनके मन में किसी न किसी कोने में रहता है। जब समय आता है वह उसको उगल देते हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि हमे ंसइ पर विचार करना चाहिये। उसके बाद पुलिस की बजावत की जो कहानी आई, पुलिस के जवानों ने कया किया। इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। पुलिस के कुछ जवान वहां पर मरे भी हैं। इस सारे सिलसिले पर हमें विचार करना चाहिए।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): आन ए प्वायंट औफ और्डर सर। 28 तारीख को तो जो कुछ वहां पर हुआ है वह तो सब–जुडिस मैटर है। ये अगर उसका जिक्र न करें तो बेहतर होगा।

Mr. Speaker: Please do not discuss that.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने तो न 27 तारीख की बात की है और न ही 28 तारीख की बात की है। मैं

किसी स्पैसिफिक घटना की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो जनरल सी बात की है। What is in the mind of the people of Haryana, I am representing that. अध्यक्ष जी, यह सारा सिलसिला ऐसा है कि जब आदमी सत्ता में आता है तो कई बार यह बहम हो जाता है कि मैं जो सोचता हूं वह सबसे ठीक है, मैं जो समझता हूं वह सबसे ठीक समझता हूं। राजनीति में जब हम लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कई गुणा ज्यादा बढ़ जाती है। हमको अपने ऊपर अंकुश रखना चाहिए। जनता की जो भावनाएं होती हैं हर मामले में वह हमार ऊपर अंकुश का काम करती है।

(इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य, श्री आत्मा राम गोदारा, पदासीन हुए।)

सभापति महोदय चाहे जनता दल हो, बी.जे.पी. हो या साम्यवादी दल हो सभी को यह बात लागू होती है।

आज सैन्टर में जनता दल की सरकार, बी.जे.पी. और साम्यवादी दलों के समर्थन से चल रही है। सभी लोगों ने, जो डिफरैंट पाटियों से सम्बन्ध रखते हैं, इस बात को कहा है कि जब चुनाव में हिंसा होती है और वह भी सतारूढ़ दल के उम्मीदवार के पक्ष में तब हमें उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोगौं में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिये। हम बेशक इसके लिये प्रैस पर आरोप लगायें परन्तु हम अपनी जिम्मेवीर से बन नहीं सकते। न्यूज ट्रैक वालों ने एक कैसेट बनायी है। उसको देखने के बाद

उस प्रैस के कैमरामैन की बहादुरीकी दाद देनी पड़ती है कि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक आम आदमी के लिये, जनता के सामने ऐसी जानकारी दी है। महात्मा गांधी के साथ हम अकसर अपनी बातों की जोड़ते हैं। महात्मा गांधी जी जन नेता थे। आजादी की लड़ाई की बागड़ोर हिन्दुस्तान की जनता से उनको सौंप रखी थी। उस वक्त भी जब लड़ाई की बीच में कई बार उनको ऐसा लगता था कि उनकी आन्दोलन हिसक होने जा रहा है, किसी का नुक्सान हो सकता है, तो वह अक्सर उसका विदड्रा कर लिया करते थे। मैं इस बात के लिये महात्मा गांधी जी की बहादुरी की दाद देता हूं। राजनीति में अगर बड़े लोग कोई मर्यादा स्थापित नहीं करेंगे तो आज जो हिन्दुस्तान के कोने–कोने में भगवान राम की चर्चा हो रही है, वह कैसे सार्थक होगी। उन्होंने भी एक मर्यादा स्थातित की थी। आदरणीय चौ. देवीलाल का परिवार आज हिन्दुस्तान की राजनीति शिखर पर है।

श्री सभापति: आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हो?

श्री राम बिलास शर्मा: मैं गृह विभाग की मांग पर बोल रहा हूं।

सभापति जी, उन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी। आज यदि किसी तरह से मेहम दुर्घटनाओं के बारे में कोई बात कही जाती है, लोगों का दर्द पूछा जाता है तो उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता। कोई किसी का दर्द पूछता है किसी से कोई

हमदर्दी जाहिर करता है तो आदमी इससे बड़ा हेाता है छोटा नहीं होता। आज मेहम की घटनाओं को दबाया जा रहा है। कभी प्रैस की निन्दा की जाती है सभापति जी, मैं गृहमंत्री से खासतौर से कहना चाहता हूं कि आपके पास पुलिस का महकमा बहुत दिन से है। पुलिस में एक बात खास तरह के लोग होते हैं। उन सब की एक खास तरह की जिम्मेदारी होती है। आफिसर्ज की जिम्मेदारी होती है। कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है और सिपाही की जिम्मेदारी होती है। इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस की प्रतिश्ठा को जितना ऊंचा रख सकें उतना ऊंचा रखें। इन लोगों में अच्छी योग्यता होनी चाहिए। राजनैतिक ढंग से कोई फैसला नहीं होना चाहिए। सभापति जी लक्षमण जी कम्बोज के खिलाफ अगर केस दर्ज होता है तो तीन घंटे के अन्दर उनकी गिरफतारी हो जाती है। यह ठीक है कि उनके साथ राजनैतिक मतभेद हैं लेकिन प्रताप सिंह जिसने लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश की जिसने एक खास तबके के खिलाफ जहरीला पोस्टर निकाला उसकी गिरफतारी आज तक नहीं हुई। इसका क्या कारण है, यह चिन्ता का विशय है। आखिर क्या बात है कि वह आदमी गिरफतार नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी आज पुलिस में बहुत सुधार की आवश्यकता है। यह नहीं होना चाहिए कि किसी को मधुबन लगा यिदा जाए चाहे उसकी कितनी ही रिपोर्ट अच्छी हों। सभापति जी, एक आदमी के खिलाफ उसके अफसर ने उसकी ए.सी.आर. में लिखा कि इस आदमी ने फलाने व्यापारी की जेब से पैसा निकाला, उसको तो प्रोमोशन दी जाती है और जो आदमी अपनी जान की

बाजी लगाकर काम करता है, परी ईमानदारी से काम करता है, अपनी डयूटी को ईमानदारी से निभाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है उसको मधुबन में लगा दिया जाता है। इन सब बातों के लिये प्रदर्शन भी हुए हैं। सभापति जी, इन सब चीजों के लिए हमें आत्म विश्लेशण करना चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 5 जो उत्पादन शुल्क तथा कर के बारे में है, पर अपने विचार रखना चाहता हूं। गुप्ता जी उसी तबके से ताल्लुक रखते हैं व्यापारियों की दिक्कतों को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे कई साथियों ने कहा है कि हमारा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश हैं हम चारों ओर से दूसरे प्रदेशों से घिरे हुए हैं। सभापति जी, दिल्ली में जो कर प्रणाली है वह दूसरी तरह की है। वहां पर टैक्स बहुत कम हैं और बहुत सी चीजों पर टैक्स नहीं हैं। सांपला और बहादुरगढ़ के जो किसान हैं वे अपनी फसल को दिल्ली बेचना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है। वे चोरी से वहां जाना चाहते हैं क्योंकि बैरियर से उनको गुजरने नहीं दिया जाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारी कर प्रणाली ऐसा होनी चाहिए कि मैक्सीमम टैक्स की रिएलाइजेशन हो। अधिक से अधिक रैवेन्यू राज्य को आए। ऐसी नीति हमारी सरकार की होनी चाहिए। अगर रेट औफ टैक्स ज्यादा होगा तो हमें टैक्स कम आएगा। मतलब यह है कि टैक्स की कम रिएलाईजेशन होगी। इसलिए रेट औफ टैकस कम होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक टैक्स की रिएलाईजेशन हो। इस तरह

की नीति हमारी सरकार की होनी चाहिए। इससे किसान और व्यापारी दोनों को फायदा मिलेगा।

सभापति जी, अब मैं डिमांड नम्बर छः जो वित्त से सम्बन्धित है, पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत सी कार्पोरेशंज हैं जैसे सीड कार्पोरेशन, डैरी डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन तथा दूसरी अनेक कार्पोरेशन हैं लेकिन कोई भी कार्पोरेशन, हमारे यहां फायदे में नहीं जा रही है जबकि दूसरी तरफ एक प्राईवेट आदमी कोई कार्पोरेशन बनाता है तो वह करोड़ों रूपए का मुनाफा कमाता है। सभापति जी, हमारे यहां डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन है उसमें करोड़ों रूपए का नुक्सान है और दूसरी तरफ पेहवा में एक प्राईवेट दूध का प्लांट है और वह मधु घी बनाता है वह करोड़ों रूपया कमाता है। सभापति जी, अगर अधिकारियों के माध्यम से हम अपनी कार्पोरेशंज फायदे में नहीं चला सकते तो हमें घाटा हरियाणा की जनता पर नहीं डालना चाहिए और घाटे की कार्पोरेशंज को हमें बन्द कर देना चाहिए।

सभापति जी, अब मैं डिमांड नम्बर 9 पर अपने विचार रखनाप चाहता हूं। यह डिमांड शिक्षा के बारे में है। इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर पिछली कुछ वर्शो से गिरता जा रहा है और इसके कई कारण हैं इस बारे में सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। सभापति जी, हरियाणा की तुलना कभी केरल प्रान्त से होती थी लेकिन आज हमारी शिक्षा का स्तर कहीं पर भी नहीं आता। सभापति जी, प्राईवेट स्कूलों के बारे

में शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि 36 ऐसे प्राईवेट स्कूल्ज हैं जिनके अध्यापकों को छः छः महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इसकी सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। इन बातों की ओर गौर करना चाहिए और इसका सुधार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 11, जोकि अर्बन डिवैल्पमैंट से सम्बन्धित है, पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से लोगों में यह गल्तफहमी आ गई थी कि यह सरकार शहरी विकास के खिलाफ है जबकि ऐसा नहीं है बल्कि सरकार ने शहरों की बहबूदी के लिए काफी काम किये हैं परन्तु उसका प्रचार नहीं हुआ है। सड़कें बनाने का काम मार्किट कमेटियों ने अपने हाथ में लिया परन्तु उसको गति नहीं मिली। सभापति महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लोग गांव से शहरों की ओर आना चाहते हैं, इसलिये नगरों के विकास की ओर सरकार को विशेश ध्यान देना चाहिए। सफाई व सड़कों का सरकार को विशेश तौर से ध्यान करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 14, जोकि फूड एंड सप्लाईज से सम्बन्धित है, पर यह कहना चाहता हूं कि यह मामला कई बार काफी विवादास्पद रहा है। बहन सुशमा जी के पास जब यह विभाग था तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकारा था कि यह विभाग छलनी छलनी हुआ पड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय कुछ उपभोक्ता समितियां बनीं थीं, पता नहीं उनको बादी में चालू रखा गया या नहीं रखा गया परन्तु आटा, चावल,

दाल, गेहूं, जो भी जरूरी वस्तुएं हैं, वे गरीब किसानों तक नहीं पहुंचतीं थीं। वैसे किसान गेहूं वगैरह तो कम ही लेते हैं लेकिन उन्हें बाजार से अन्य जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि वे लोग सभी चीजों की खेती नहीं करते। यह सब कुछ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थीं लेकिन दुर्भाग्यवश यह राशन उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। ढांडा साहब इसके मंत्री हैं इसलिए मेरी सभापति जी आपके द्वारा उनसे प्रार्थना है कि वे इस ओर विशेश ध्यान दें ताकि गरीब लोग जिनके लिए यह सरकारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए उनको इनसे वंचित न रहना पड़े।

सभापति जी, अब मैं डिमांड नम्बर 15 जोकि सिंचाई से सम्बन्धित है, के बारे में कहूंगा। स्वयं उप मुख्यमंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि महेन्द्रगढ़, सिवानी, लोहारू व कुछ दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर टेल तक न बिजली न पानी सही मात्रा में पहुंच पाता है जिस कारण से लोगों से लोगों में बड़ी परेशानी है। अगर एक 400 के.बी. की बिजली यहां से चलती है तो टेल तक पहुचते पहुचते वह केवल डेढ़ सौ के.वी. की मात्रा में ही रह जाती है जिस के कारण के किसानों के मीटर्ज जल जाते हैं और किसानों को जिसके कारण काफी नुक्सान भुगतना पड़ता है। सभापति महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी के पास जब यह विभाग था तो उन्होंने स्वयं दौरा किया था। यहां तो लोग सिंचाई के लिये पानी मांगते हैं लेकिन हमने उनको उस इलाके में ऐसे ऐसे गांव

दिखाऐ जहां के लोग पीने के लिये पानी मांगते हैं। इसलिये ऐसे इलाकों का खास ध्यान रखा जाए। जो योजनाएं हैं, उनको शीघ्र ही लागू किया जाए। जो पम्पस ऐनरजाइज नहीं हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली और पानी देने की व्यवस्था की जाए। सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पानीपत, फरीदाबाद और जगाधरी जैसे स्थानों पर थर्मल प्लांटस लगे हुए हैं परन्तु महेन्द्रगढ़ वगैरह के इलाके में कोई थर्मल प्लांट नहीं है। सभापति महोदय, भारत सरकार के सौ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने महेन्द्रगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वे किया था, वहां पर इस प्रकार का केन्द्र लग सकता है। इसलिये उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर सौर ऊर्जा केन्द्र लग सकता है। इसलिये उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर सौर ऊर्जा केन्द्र लगाया जाए ताकि उस इलाके के लोगों को बिजली मुहैया करवा के राहत दिलाई जा सके।

सभापति जी, मैं उद्योग के संबंध में मांग संख्या 16 पर अपनी बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों हरियाणा में फैक्ट्रीज एक दम ऊंचाई पर जा रही थीं। हमारे बहादुरगढ़, जगाधरी, फरीदाबाद और धारूहेड़ा के इलाकों में धीरे धीरे उद्योग बिछने शुरू हुए थे। परन्तु पिछले सालों से दुर्भाग्य से ये उद्योग हरियाणा से शिफ्ट होते जा रहे हैं। आज जगाधरी की मैटल इंडस्ट्री काला अम्ब और परवाणु में जा रही है। आज बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री बन्द होकर इधर उधर बिखर गई। आज फरीदाबाद की

ऐक्सकोर्ट नोयडा (यू.पी.) में जा रही है। धारू हेड़ा से सहगल पेपर वाले अपना मिल बन्द करके चले गए। सिलेंडर बनाने की पिछली गवर्नर साहब की फैक्टरी वहां थी वह भी बन्द करके चले गए। उद्योग के संबंध में हरियाणा सरकार को विशेश चिन्ता करनी चाहिए। किसी भी राज्य का मूल आधार कृशि और उद्योग होता है। उद्योग इतनी तेजी से शिफ्ट होने शुरू हो जाएं, इसके पीछे होने वाले कारण पर विशेश चिन्ता की जानी चाहिए और उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

मांग नम्बर 18 पशु पालन से संबंध रखती है। आज एक फशन हो गया है कि जो चीज विदेशों से आती है जिसका प्रचार रेडियो और टेलीविजन करता है, सारे देश का झुकाव उस तरफ हो जाता है। आज पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हरियाणा में जगह जगह लोगों ने सफेदे लगा दिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सफेदा 24 घंटे में 18 गैलन पानी लेता हैं। इस कारण से आज किसान का मुसीबत आ गई है। जिस कुरूक्षेत्र में पहले सेम होती थी आज वहां का जल स्तर भी नीचे जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पशु पालन के संबंध में पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। जरसी और हौलस्टन की नकल की गायों पर आज ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हरियाणवी नसल की गाय तो आज बिलकुल ही खत्म हो गई है। पहले हरियाणा नसल बहुत अच्छी थी। उसका दूध भी ज्यादा था और दूध में फैट भी ज्यादा थी। हमें मुर्रा नसल की भैंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए यह नहीं

कि बाहर के सोमन पर ही जोर दिया जाए। हमें अपनी नसल के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

सभापति जी, मांग संख्या 21 सामुदायिक विकास से सम्बन्धित है। पिछले दिनों से गांवों की आबादी बढ़ती जा रही है। वैसे तो आजादी के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश में यदि विकास करना है तो गांवों का शहरीकरण करना पड़ेगा और शहरों का ग्रामीणकरण करना पड़ेगा। परन्तु उल्आ हो रहा है। सारा विकास शहरों की तरफ हो रहा है। गांवों में विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। पहले गांवों में हमारी माताओं बहिनों की सुविधा के लिए कुछ जगह में जंगल होता था जहां पेड पौधे हुआ करते थे। आज गांवों में शौचालय की बहुत समस्या है। पिछले दिनों सुलभ शौचालय के नाम से एक योजना चली थी। मैं चाहता हूं कि इस योजना पर विशेश ध्यान देकर जिन गांवों की आबादी ज्यादा हो गई है वहां यह चालू की जाए।

मांग संख्या 22 सहकारिता से संबंध रखती है। सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया है और वह भी एक खास क्षेत्र में यानी शूगर मिल के क्षेत्र में हमने विकास का बहुत कम किया है। हमारे जो बैंक हैं चाहे लैंड डिवैल्पमैंट बैंक हैं ओर चाहे हरको बैंक हैं। पिछले दिनों के इनके आंकड़े इस प्रकार के हैं कि इनमें जो पूंजी आती है उसके कागजों में दिखा देते हैं। साल के अन्त में रिकवरी 90 प्रतिशत दिखा देते हैं। अगर रिकवरी इतनी है तो मुनाफा कम से कम क्यों दिखाते हैं? जिन

बैंकों को रिकवरी 90 परसैंट है, उनका मुनाफा कहां चला जाता है? इस संबंध में भाई धीरपाल जी को चिन्ता करनी चाहिए। जिन बैंकों की रिकवरी के आंकड़े 80 और 90 परसैन्ट हैं उनका मुनाफा कहां चला जाता है यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। कहीं आंकड़ों कोई हेराफेरी तो नहीं है।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर 23 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो परिवाहर से संबंधित है। परिवहन के सिलसिले में हरियाणा प्रदेश की बड़ी प्रतिश्ठा है। अगर जयपुर में राजस्थान रोडवेज की बस खड़ी हो और हरियाणा परिवहन की भी बस खड़ी हो तो लोग हरियाणा परिवहन को बस में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन परिवहन के बारे में में एक बात जरूर कहना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के परिवहन विभाग ने जो वीडियों कोचिंज चला रखी हैं इस बारे में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो उनमें वीडियों चलता है उसको बस चलाने से पहले अवश्य चैक कर लिया जाए आया वह ठीक भी चलता है या नहीं। उन वीडियों कोचिज में जो लोग सफर करते हैं वे इस बारे में चर्चा करते हैं कि यह वीडियों चलता ही नहीं है तो इसका क्या फायदा है?

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर 24 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि पर्यटन विभाग से संबंधित है। वैसे तो इस विशय में मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया है जो मन्जूर भी हो चुका है और डिटैल में

बातें मैं उसी समय करूंगा लेकिन ईशारतन अभी भी कुछ कहना चाहूंगा। पर्यटन के संबंध में हमारी सरकार ने पिछले दो अढ़ाई साल के अर्से में बहुत तेजी से काम किया है। यह भी खुशी की बात है कि पर्यटन निगम में अधिकारी और चेयरमैन सरकार की रूचि के लगें। उसमें अच्छी अधिकारी और चेयरमैन लगने के कारण ही आज उसका यह परिणाम है कि दूसरे देश हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कंसलटैंसी मांगते हैं।

श्री सभापति: शर्मा जी आप वाइंड अप करें। दूसरी मैम्बर्ज को भी बोलने के लिए टाईम देना है।

श्री राम बिलास शर्मा: सभापति महोदय, मैं दो तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि पर्यटन केन्द्रों पर जो दुकानें हैं उनमें आम आदमी नहीं जा सकता। उन दुकानों के रेट सुन कर हमारे खण्डके वाले वापिस हो लेते हैं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री महा सिंह): सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर हैं। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पर्यटन केन्द्रों पर हफ्ते में तीन दिन 7 रूपए थाली दी जाती है और दो दिन 5 रूपये थाली दी जाती है। इतना सस्ता खाना कहीं पर भी नहीं मिलता। आप किसी भी ढाबे पर चले जाएं आपको 10 रूपए से कम खाना नहीं मिलेगा।

श्री राम बिलास शर्मा: सभापति महोदय, मैं तो पर्यटन केन्द्रों पर जो दुकानें हैं उनके बारे में अपनी बात कह रहा था। (शोर)

समाज कल्याण मंत्री (श्री जगन नाथ): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। मैं तो शर्मा जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस समय मैं पहले मंत्री पद से हटा था तो मेरा दिमाग बदला हुआ था। अब हमारे साथी श्री राम बिलास जी चूंकि नए गए मंत्री पद से हटे हैं इसलिए इनका दिमांग भी बदल हुआ था। अब हमारे साथी श्री राम बिलास जी चूंकि नए नए मंत्री पद से हटे हैं इसलिए इनका दिमाग भी बदल गया है। चेयरमैन साहब, मंत्री बनने के बाद और पहले में बहुत फर्क है।

श्री राम बिकास शर्मा: सभापति महोदय, सौभाग्य और संयोग की बात है कि हम मंत्री रहें या न रहें इस बात का हमारे जहन पर कोई फर्क नहीं पढ़ता सभापति महोदय, भई जगन नाथ जी को मेरी आलोचना से या दूसरे लोगों की आलोचना से टची नहीं होना चाहिए। इनको दूसरों के बोलते समय बार बार टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री सभापति: शर्मा जी, आपने बहुत समय ले लिया है। दूसरे साथियों ने भी बोलना है। आप कृपा बैठ जाएं।

श्री राम बिकास शर्मा: सभापति महोदय, मैं अभी बैठ जाता हूं। केवल एक बात कहनी है। सभापति महोदय, मेरी सरकार

से प्रार्थना है कि सामुदायिक योजना के तहत स्लम कलियरैंस संचालन की योजना को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि हमारी ग्रामीण महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इतनी बात कह कर मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह (रोहट): चेयरमैन साहब, पिछले दिनों हमारे उप–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट विधान सभा में पेश हुआ उसी के तहत ये डिमांडज आज हाउस में आई हैं और इन्ही डिमांडज पर मैं अपनी बात सदन के सम्मुख रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, बजट के पहले पेज पर लिखा है कि सबसे पहले मैं केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर राजनैतिक ढांचे में हुए ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र करना चाहूंगा। आज के बदले हुए राजनैतिक हालत के मुताबिक इस सदन के भूतपूर्व नेता तथा हामरे राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल भारत के उप प्रधान मंत्री के रूप में शोभायमान हैं। उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन साहब, मैं सभी डिमांड पर तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन कुछ डिमांडज पर जरूर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

चेयरमैन साहब, हरियाणा का वर्श 1990–91 का बजट 700 करोड़ का रखा गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस बजट का 70 प्रतिशत हिससा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा। इससे पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि बजट का 70

प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास पर खर्च हो। यह काम हमारे मुख्यमंत्री चौ. औम प्रकाश चौटाला की सरकार ने किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

चेयरमैन साहब, अब मैं सिंचाई का जिक्र करूंगा। हमारे 80 प्रतिशत लोग कृशि पर निर्भर करते हैं। कृशि तभी हो सकती हैं जब सिंचाई के पूरे साधन लोगों को उपलब्ध हों। इसमें एस. वाई.एल. नहर बनाने का भी जिक्र आया है। इस संबंध में संबंधित मंत्री जी की तरफ से एक वक्तव्य भी सदन में आया है। उन्होंने बताया कि यह काम केन्द्र सरकार के माध्यम से पूरा होना है। यह भी बड़ी खुशी की बात है कि केन्द्र में भी हमारी सरकार आने के बाद इस काम में पहले की अपेक्षा तेजी आई है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि वर्श 1990–91 के अंतर्गत यह नहर कम्पलीट हो जाएगी और जो हमारे क्षेत्र सूखे पड़े हुए हैं उनको पानी मिल सकेगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं कृशि के बारे में कहना चाहूंगा। 1988–89 में खाद्यान्नों और तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 94.83 लाख टन और 4.81 लाख टन हुआ जोकि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। यह एक ऐसा उत्पादन था जिसकी सर्वत्र चर्चा हुई है। आज हर मामले में खुल कर विचार होता है लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग जनता तक खुलकर पहुंचे हैं।

चेयरमैन साहब, कई ऐसी बातें है जिसका जिक्र यहां पर बार–बार किया गया है। इनमें से एक जिक्र मार्किटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाए जाने का भी है। मैं समझता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड सड़कें बनाने के मामले में डिस्पैरिटी रखता है। मैं डिस्पैरिटी इसलिए कह रहा हूं कि रोहट क्षेत्र में एक भी ऐसी सड़क पर काम नहीं हुआ। रोहट तो क्या शायद सोनीपत जिले में भी कोई ही सड़क होगी जिस पर काम किया गया हो। भले ही अभी तक इन क्षेत्रों में इस बारे कोई काम नहीं हुआ है परन्तु फिर भी हमें आशा तो रखनी चाहिए कि कभी तो यहां पर भी कोई काम होगा।

चेयरमैन साहब, मांग संख्या 12 रोजगार से संबंधित है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त चौ. देवी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा सरकार ने मजदूर को कम से कम 800/– रूपये का वेतन निर्धारित किया जो सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्रतिदिन वेतन को बढ़ा कर पहले 30.80 रूपये और फिर 31.80 रूपये भी किया गया। हमारी सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। उसके बाद जून, 1989 में हरियाणा के बेरोजगार युवकों को जो दसवीं, ग्यारहवीं, बी.ए. या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं उन्हें 50–50 या 100–100 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला भी इसी सरकार ने किया और हमारी सरकार सब बेरोजगारों को यह भत्ता दे रही है।

इसके साथ ही मैं परिवहन का भी जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा राज्य परिवहन ने वर्श 1988–89 में काफी बसें रिपलेस की और 200 नई बसें खरीदी। वित्त वर्श 1990–91 में भी 214 नई बसें खरीदी जाएंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चेयरमेन साहब, कुछ जगहों पर ऐसी बसें हैं जिनका हार्न को छोड़कर बाकी सब कुछ बजता है। मैं समझता हूं कि ऐसी बसों को रिप्लेस करने की आवश्यकता है। चेयरमैन साहब, मैं यहां पर यह भी कहना उचित समझता हूं कि भारत सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन को ''आदर्श परिवहन'' का नाम दिया है। हरियाणा रोडवेज की बसें 2 हजार मार्गो पर चलती हैं और प्रतिदिन 10 लाख यात्री इनमें सफर करते हैं। मैं परिवहन मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो बसें खस्ता हालत में हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए उन्हें रिप्लेस करने के लिए कार्यवाही करें। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के विशय में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा। इस विशय पर प्रोफैसर साहब ने भी काफी कुछ कहा है। चेयरमैन साहब, आज शिक्षा का स्तर वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। शिक्षा का स्तर गिरने के कारण चाहे जो भी हो लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जहां तक शिक्षकों और प्राईवेट स्कूलों की बात है, हरियाणा गवर्नमैंट 75 प्रतिशत अनुदान प्राईवेट स्कूलों को देती है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस अुनदान को समाप्त कर शत–प्रतिशत खर्च सरकार स्वयं करे और सारे स्कूलों का नेशनेलाईजेशन कर देना चाहिए। जितने भी प्राईवेट स्कूल्ज हैं वे

सारे सरकार टेक ओवर कर ले। इसी प्रकार कालेजों को भी 95 प्रतिशत अनुदान मिलता है। सारे स्कूलों ओर कालेजों को टेक ओवर करके एक नई नीति बनाई जानी चाहिए। चेयरमैन साहब, हम देखते हैं कि 8वीं क्लास में जाकर बच्चे को मालूम होता है कि उसे इम्तहान में बैठना है। तीसरी, चौथी, पांचवीं, छटी और सातवीं तक के ऐग्जामज बोर्ड द्वारा नहीं लिये जाते हैं। इस बारे में मैं समझता हूं कि पांचवीं कक्षा का ऐग्जाम बोर्ड द्वारा लिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा ऐग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ने वाले बच्चे को अहसास नहीं होता कि उसे कोई परीक्षा भी देनी है। (घंटी) चेयरमैन साहब शिक्षा के विशय के साथ ही जुड़ी हुई एक और बात मैं कहना चाहता हूं। टीचर्ज के मन में यह खटकता रहता है कि यह रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो उनकी ए.सी.आर. में ऐडवर्स रिमार्कस दिए जाएंगे। अपनी ए.सी.आर. को अच्छा रखने के लिए तथा अचछा रिजल्ट देने के लिए टीचर्ज बच्चों को नकल करवाने की कोशिश करते हैं या नकल पर कण्ट्रोल नहीं करते जिस कारण बच्चों को नकल के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस बारे में विशेश रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

चेयरमैन साहब, समाज कल्याण द्वारा 100 रूपये मासिक पैंशन देकर चौधरी देवी लाल ने वृद्धों का सम्मान बढ़ाया है। सरकार के इस पग की भी सराहना की जानी चाहिए। चौ. देवी लाल जी जब बुजुर्गो से कहा करते थे कि यदि मेरी सरकार आई तो मैं बुजुर्गो को पैंशन दूंगा तेा कांग्रेस के लोग कहते थे कि

वृद्धावस्था पैंशन नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार जब चौ. देवी लाल यह कहा करते थे कि यदि मेरी सरकार आई तो में कर्जे माफ कर दूंगा तो भी कांग्रेस वाले कहा करते थे कि कर्जे माफ नहीं हो सकते। चौ. देवी लाल ने सारी दुनियां का दिखा दिया कि वे जो वायदा करते हैं उन्हें वे पूरा करते हैं। आज सम्मान पैन्शन हर 65 साल के व्यक्ति को मिलती है, हर नागरिक को सुविधा मिलती है। उन्होंने जो स्टेज पर अनाउन्स किया था उसे पूरा किया है।

अन्त में सभापति महोदय, कर्मचारियों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने सुविधायें दी हैं। हमारी सरकार ने फोर्थ पे कमीशन की सिफारशें लागू की। सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले फोर्थ पे कमीशन की सिफारशें लागू की। सारे हरियाणा में हरियाणा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले फोर्थ पे कमीशन की सिफारशें लागू की। इस सरकार के बनाने में ऐम्पलाईज का बड़ा योगदान रहा है। चौ. ओम प्रकाश चौटाला तो हमेशा ही ऐप्पलाइज के हक में रहे हैं और आगे भी जो उनकी डिमांडज हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

इन मांगों के अतिरिक्त मैं अपने हल्के की भी बात करूंगा क्योंकि मेरा हल्का उन हल्कों में से जहां से भारत आजाद होने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन कर नहीं आया। हमेशा से वह विपक्ष का हल्का रहा है। विपक्ष के नेताओं

के आहवान पर मेरा हल्का लड़ाई लड़ता रहा है। इसलिए मेरे हल्के के विकास की तरफ ध्यान दिना जाये। मेरे हल्के में खरखौदा कस्बा पड़ता है। वहां पर एक रैस्ट हाउस की जरूरत है। अगर वहां पर कोई सरकारी अफसर जाता है तो बैठने की जगह नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से खरखौदा के लिए रैस्ट हाउस की मांग करता हूं। यह रैस्टहाउस जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा गर्ल्ज कालेज की भी डिमांड है। ये ऐसी आधारभूत आवश्यकतायें हैं जिनका पूरा करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि चौ. औम प्रकाश चौटाला की सरकार आने के बाद मेरे हल्के की मांगें पूरी होंगी। बस इतीन बात कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): सभापति महोदय, मैं अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली मांग विधान सभा की है। मैं इस विशय में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरी बिल्डिंग के अन्दर दो हाउसिज हैं। पंजाब विधान सभा के सैशन का काम करने का जो प्रोसैंस है वही प्रोसैस हरियाणा विधान का भी है। दोनों विधान सभाओं के कर्मचारियों एक ही काम करते हैं लेकिन उनकी तन्खाह और हाउस रैन्ट में फर्क है। हरियाणा में पचास रूपये हाउस रैन्ट मिलता है तो पंजाब में दो सौ रूपये मिलता है। * * * * जो कर्मचारी चन्डीगढ़ में रह कर यहां काम करते हैं उनको सरकार की ओर से हाउस अलौट किया जाये या उनका हाउस रैन्ट बढ़ाया जाये। पचास रूपये

हाउस रैन्ट बहुत कम है। चण्डीगढ़ में पचास रूपये में तो कोई पिशाब करने के लिए जगह किराये पर देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उन्हें रैन्ट की ज्यादा राहत देने की जरूरत है।

अब मैं डिमांड नम्बर तीन पर बोलना चाहूंगा। यह डिमांड गृह विभाग से सम्बन्धित है। हमारी सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए काफी अच्छे उपाए किये हैं। जो आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनमें लोग पकड़े भी गये हैं लेकिन जो लोग इस सुरक्षा डियूटी के लिए जिम्मेदार हैं यानी खासतौर पर पर पुलिस कन्सटेबल्ज और हैडकन्सटेबल, उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एम.एल.ए. बनने के बाद सुरक्षा के लिए जब से ये कर्मचारी हमारे साथ रहते हैं तभी से हमें उनके बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिला है। तीन–तीन साल से उन्हें बूट और पी.टी. शू तक मुहैया नहीं किये गये हैं। उन्हें चार साल में दो ठंडी और दो गर्म वर्दियां दी जाती है। 24 घंटे डियूटी देने वाला आदमी एक वर्दी अगर 24 घंटे लगातार पहन ले तो वर्दी फट सकती है, दोबारा से यूज नहीं हो सकती। इसके अलावा जहां हाउस रैंट 20 परसैन्ट मिलता है उसे भी सात परसैन्ट करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री सभापति: कामरेड जी विधान सभा के बारे में जो आपने कहा है उसकी आवश्यकता नहीं है। यह विधान सभा वाला मामला रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिये।

कामरेड हरपाल सिंह: विधानसभा का इन मांगों में जिक्र है।

श्री सभापति: जो आपने पहले बोला है उसकी जरूरत नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: मैंने अनुदान मांगों पर ही बोला है।

श्री सभापति: उसके लिये आपका धन्यवाद लेकिन उसे कहने की जरूरत नहीं है। उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाये।

कामरेड हरपाल सिंह: सभापति जी अनुदान मांगों के अन्दर विधान सभा का जिक्र है।

श्री सभापति: यह मैं मानता हूं कि अनुदान मांगों में विधान सभा का जिक्र है लेकिन इस बात को यहां कहने की जरूरत नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: इसी सम्बन्ध में मेरे आदरणीय साथी श्री रामबिलास शर्मा जी भी बोल कर गये हैं उनका पोर्शन तो रिकार्ड से निकाला नहीं गया हालांकि उस समय स्पीकर साहब चेयर पर थे।

श्री सभापति: आपका धन्यवाद कि आपने इस बात को यहां उठाया है लेकिन मेरे विचारनुसार इसके रिकार्ड पर आने की

जरूरत नहीं है क्योंकि कंवैन्शन के मुताबिक विधान सभा सैक्रिटेरिएट के बारे में हाउस में डिसकशन नहीं हो सकती।

कामरेड हरपाल सिंह: जहां पर कर्मचारी 24–24 घंटे डियूटी देते हैं, वहां पर मैं खास तौर पर आदरणीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जो सैंसेटिव एरिया है, वहां पर डियूटी पर लगे हुए कांस्टेबल की जरूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहां उनसे डियूटी की उपेक्षा करते हैं, वहां उनको रैस्ट की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिये। जिस जवान की 24 घंटे डियूटी होती है, उसके खाने पीने का भी प्रबन्ध आपको करना चाहिये। उसको पानी मिल गया है, भोजन मिल पाया है, यह सब देखना आपका फर्ज है। मेहम के अन्दर जो कुछ हुआ है, वह इसी का तो नतीजा है।

श्री सभापति: कामरेड साहब, प्रत्येक मैम्बर को बोलने के लिये 10 मिनट का टाईम मुकर्रर है इसलिये आप अपनी बात जल्दी–जल्दी खत्म कर लें।

कामरेड हरपाल सिंह: अभी तो मैंने बहुत थोड़ा ही बोला है। आपने तो अभी से पाबन्दी लगानी शुरू की दी है।

श्री सभापति: आप बात को रिपीट न करें।

कामरेड हरपाल सिंह: मैं रिपीट नहीं करूंगा। वहां पर 20–25 हजार के करीब कांस्टेबल इलैक्शन डियूटी के लिये लगाये गये। तीन दिन तक उनको बरसात के अन्दर गांव में कही पर भी

रहने की जगह न मिले, यह देखने वाली बात है। उनकी खाने की जरूरत भी पूरी नहीं हुई। ग्रामीण जनता को यह पता था कि यह तो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आए हुए हैं इसलिये यह तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। जो आखिरी दिन घटना हुई उसमें हमारे पार्लियामैंट के एक सदस्य और एक मंत्री महोदय भी उसकी चपेट में आ गये। उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनकी ठुकाई कर दी। ऐसी घटना दोबारा न घटने पाये इसलिये हमारे पुलिस कांस्टेबल्ज की जो डियूटी है, उनको वहीं पर रखा जाये। विशेशकर कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको नम्बरी इलाके गिना जाता है। मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। रतिया का इलाका ऐसा है, सिरसा से लेकर अम्बाला, तक की बैल्ट जो पंजाब के साथ लगती है, टोहाना जाखल और रतियसा की यह जो बैल्ट है, यह बड़ा क्राइम प्रोन इलाका है। वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है कि कौन एस.एच.ओ. वहां पर आयेगा । हमारे इलैक्शन कमीशन की तरफ से एक आर्डर आया था। हमारे मेहम में जो डी.एस.पी. ठप्पे लगाता पकड़ा गया है, वह शायद टोहाना में अपनी पोस्टिंग करवाना चाहता था। इसलिये उसने यह काम किया। इलैक्शन कमीशन का एक एस.पी. के बारे में नोट आता है कि कि आप वहां पर इलैक्शन के समय नहीं होंगे लेकिन भिवानी का एस.पी. वहां पर मौजूद पाया जाता है। इलैक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंज के बावजूद उन्होंने जो मेहम के इलैक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, सरकार ने अभी तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जो लोग अपनी डियूटी ईमानदारी से देते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना

चाहिये और उनको प्रोमोशन मिलनी चाहिये। मेरा सवाल एक हरियाणा राज्य में वीकर सैक्शन्ज को रहने के लिये एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के बारे में था। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई मैंने यह सवाल रैवेन्यू से पूछना था कि हरियाणा के अन्दर भूमिहीन किसानों के लिये या वीकर सैक्शन्ज के लोगों के लिये या हरिजनों के लिये गांवों के अन्दर जो प्लौटस उनको दिये हैं या जो पहले दिये जा चुके हैं, वह उनको जनसंख्या से बाहर गांवों से बाहर जोहड़ों में प्लौट अलौट क्यों किये गये हैं। दो बार उनको वहां से उठाया गया, उजाड़ा गया और तीसरी बार फलड आया तो वह जमीन ही बह गयी। पंचायत के पास बेहतर जमीन होती है तो पंचायत वह बेहतर जमीन नीलाम करती है और पैसा इकट्ठा करती है। वह पैसा भी गांवों के सारे लोगों की भलाई के काम आता है। हम यह चाहते हैं कि ऐसी जमीन में से प्रायरिटी के आधार पर वीकर सैक्शन्ज में प्लौटस अगर दिये जायें तो बेहतर हो सकता हे। करनाल के अन्दर इसी मांग को लेकर खेत मजदूरों को परेशान भी किया जा रहा है। सटौंडी नाम के गांव के अन्दर लोगों को जो प्लौटस दिये गये हैं, उनके नाम रजिस्ट्री भी हो चुकी है, सब कुछ उनके पास है लेकिन फिर भी उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है।

चेयरमैन साहब, सरकार ने जो जमीन सरप्लस आइडैन्टीफाई की थी उसका बंटवारा होना चाहिए। उन जमीनों को भूमिहीन किसानों के अन्दर बांटा जाए। मैं इस सरकार से

पूछना चाहता हूं कि जो सरप्लस जमीन सम्बन्धी भूमिसुधार कानून थे क्या वे ठीक तरह से लागू हो गए हैं या उस जमीन को जिसे बचाने के लिए लोगों ने कुत्ते बिल्लियों के नाम कर रखा था, आइडैन्टीफाई किया है? मेरा सरकार को कहना है कि सरकार ऐसी जमीनों को आइडैन्टीफाईड करे। चेयरमैन साहब, कुछ गांवों के अन्दर हमारे सामने एक और समस्या आती है। जब चकबन्दी हुई तो जो चकबन्दी में फालतू जमीन निकली उसको मुश्तरका मालिकान बोलते हैं वह काफी कन्ट्रोवरशियल जमीन हे। उन जमीनों पर काफी विवाद है। मेरा कहना यह है कि ऐसी जमीनों को रैवेन्यू डिपार्टमैंट पंचायतों के साथ अटैच कर दे ताकि पंचायतों की इन्कम बढ़ जाए और विवादस्पद जमीनों को अटैच करने से आमदनी तो बढ़ ही जाएगी। लेकिन साथ ही साथ गांवों के अन्दर विवाह भी खत्म हो जाएगा और आपस में दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 5 के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा के अन्दर तो शराब के ठाठ हैं। कुछ साल पहले ठेके पर जाने के लिए व्हीकल्ज नहीं मिलते थे। लोग रात के अन्धेरे में शराब की बोतल लेने के लिए जाते थे लेकिन आज हालत यह है कि हर गांव में हर दुकान पर शराब की बोतलें थोक में भी और परचून में भी आप ले सकते हैं। अगर सरार रैवेन्यू इकटठा करने के लिए हमारे नौजवानों का भविश्य खराब करना चाहती है और उनका स्वास्थ्य खराब करना चाहती हे तो

जिस तरह से ठेकों पर लिखा होता है कि ड्राईवर्ज के लिए विशेश रियायत उसी तरह से हमारे जवानों के लिए और सवारियों के लिए लिखवा दिया जाए कि बीमा मुफत जिससे ज्यदा शराब बिके और सरकार की आमदनी बढ़ सके। मेरा सरकार ने निवेदन है कि अगर वह हमारे नौजवानों को बरबादी से बचाना चाहती है तो शराब को मंहगा किया जाए। अगर हमारी सरकार की शराब पर ही डिपैन्डैंसी है और इसी की आमदनी पर सरकार चलती है तो शराब को ज्यादा मंहगा किया जाए। ठेके कम किए जाएं। यह शराब जहां हमारे नौजवानों का स्वास्थ्य खराब कर रही है वहां उनको फाइनैंशियली भी कमजोर कर रही है। चेयरमैन साहब, हिसार में जो डिस्टीलरी है उसने कैन्ट के साथ लगते हुए सात गांवों की किसानों की जमीन को खराब कर दिया है। वहां पर पी. डब्ल्यू.डी. की काफी जमीन है। उस जमीन पर उस डिस्टीलरी का ऐफल्यूएंट वाअर जाता है। इस पानी से उस जमीन पर जो फौरेस्ट था फौरेस्ट्री डिपार्टमैंट का वह सूख गया है और लगभग तबाह हो चुका है। इसलिए हरियाणा में डिस्टीलरीज बन्द होनी चाहिए। डिस्टीलरी केवल दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल हों। शराब को महंगा करके उतना ही फायदा उठाया जा सकता है जितना कि ज्यादा ठेके खोलकर फायदा उठाया जाता हे। चेयरमैन साहब, मेरा कहना यही है कि ठेके कम किए जाएं और शराब मंहगी की जाए। (घंटी)

चेयरमैन साहब, अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय, शायद यहां बैठे नहीं हैं, चले गये हैं। चेयरमैन साहब, बौर्डर एरिया के कुछ गांवों में फलड आया था और इस कारण सड़कों को काफी नुक्सान हुआ था। मेरे इलाके में चिलेवाल एक गांव है जो सड़क से दूर है। सड़क से जुडा हुआ नहीं है। पिछले साल वहां डकैती हुई और कत्ल हो गया। कत्ल के बाद हमने कोशिश की कि वहां पर सड़क बना दी जाए और उस गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए। सूरेवाला गांव में, जो पंजाब बोर्डर पर आता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अमृतसर लुधियाना को वहां से काफी ट्रैफिक जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूरेवाला से लेकर टोहाना तक सड़क बनाई जाए क्योंकि वह सड़क टूटी हुई है। जो गांव सड़क से डिलिकड है उनको सड़क से लिंक किया जाए।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर नौ पर, जो शिक्षा के बारे में है, कुछ कहना चाहता हूं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस मद में और फण्डज अलौट किए जाएं। जहां पर और नए इंस्टीच्यूशंज बनाए जा रहे हैं वहां पर अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया की जाएं। चेयरमैन साहब, टोहाना के अन्दर जो कालेज है और जिनको दस साल पहले सरकार ने लिया था उसके अन्दर खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। वहां पर खेल का मैदान मुहैया कराया जाए।

श्री सभापतिः आपको बोलते हुए बारह मिन्ट हो गए है। आप जल्दी वाइंड अप करिए।

कामरेड हरपाल सिंहः चेयरमैन साहब, मेरी मांग है कि भूना के अन्दर कालेज खोला जाए। चेयरमैन साहब, भूना के एरिया में जहां शूगर मिल लगाई जा रही वहां पर आई.टी.आई. और पोलीटैक्नीक में ऐसे ट्रेड होने चाहिएं जिनमें शूगर मिल के बारे में टैक्नीकल ऐजूकेशन मिल सके। टोहाना में आई.टी.आई. की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है इसलिए उसको जल्दी शुरू करवाया जाए और इनमें ऐसी ट्रेंड शुरू होनी चाहिए जो उस एरिया की डिमांडज को पूरा कर सके। वहां पर हिन्दी टाईपिग, अंग्रेजी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी की ट्रेड है। मेरी प्रार्थना कि ऐसी ट्रेड शुरू की जाएं जो उस इलाके की रिक्वायरमैंट को मीट आउट कर सकें।

भूना कालेज और टोहाना आई.टी.आई. के काम की प्रायरिटी के बेसिंज पर शुरू किया जाएं।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 10 पर बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, टोहाना से हिसार और रोहतक बहुत दूर पड़ता है। टोहाना का हौस्पीटल बहुत छोटा है, बिस्तर काम हैं लेकिन आबादी ज्यादा है। वहां को जरूरत को ध्यान में रखते हुए भूना में नया हौस्पीटल बनाया जाए। इसके साथ–साथ मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि सभी हौस्पीटलज में दवाईयों का अभाव है।

विशेशकर जीवन रक्षक दवाओं का प्रबन्ध तो हौस्पीटलज के अन्दर ही होना चाहिये। इस ओर सरकार विशेश ध्यान दें। सभापति जी, पब्लिक हैल्थ का सिलसिला भी लगभग इसी से ही जुडा हुआ है। इसका जिक्र भी कई बार हाउस के अन्दर आया है। गांवों और शहरों का जिक्र भी हाउस के अन्दर होता रहा है। यह दिखाने के बहुत प्रयत्न किये जा रहे है कि जैसे शहरों में ही बिड़ला लोग बसते हैं और गांव के अन्दर सभी भूमिहीन लोग बसते हैं। गरीब लोग बसते हैं वास्ता में ऐसी परिस्थिति नहीं है। शहरों के अन्दर भी 60, 70 परसैन्ट आबादी वेतनभोगी, मजदूर, रेहड़ी वाले, रिक्शा चालकों और टांगा चलाने वालों आदि की है जोकि अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इन लोगों की आप गांव के बड़े जमींदार के साथ जिसके पर 1200 एकड़ भूमि हैं, तुलना नहीं कर सकते। जब शहर बसे थे सभापति महोदय, उस वक्त जो पानी के टैंक लगे थे, वे आज आबादी बढ़ जने के कारण कम पड़ रहे हैं और पानी की सप्लाई गरीब लोगों की बस्तियों के अन्दर नहीं पहुंच पा रही है।

श्री सभापति: हरपाल सिंह जी, आप वाइंड अप कीजिये। आप ऐक्सप्लेन करने में समय ज्यादा खराब करते हैं। आप अपनी असली बात कहिये।

कामरेड हरपाल सिंह: मेरा करने का मतलब यह है कि पहले जो शहरों में वाटर वर्कस बनाये गये थे, वे अब आबादी बढ़ जाने के कारण गरीब लोगों की बस्तियों तक पानी नही पहुंचा

पाते। उन गरीब लोगों की बस्तियों को ओर, विशेश ध्यान दिया जाए। वहां बस्तियों की सफाई करवायी जाए और पानी उपलब्ध करवाया जाए।

सभापति महोदय, अब मैं कर्मचारियों के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। कर्मचारियों के बारे में इस बजट स्पीच के अन्दर भी बताया गया है और वैसे भी कहा गया है कि कर्मचारियों के सहयोग से सरकार तरक्की कर रही है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार किस का ऐहसान तो माना पर इसके बावजूद भी सरकार ने अपनाप हार्ड रूख अपनाया हुआ है। सभापति महोदय, 240 दिनों वाले कर्मचारियों को पक्का करने में सरकार का कुछ भी नहीं जाता बल्कि लाखों रूपया सरकार हाई–कोर्टस के अन्दर इन्हीं केसिज पर खर्च करती है और फिर भी ऐसे लोगों को रोक नहीं पा रही है। वे लोग दोबारा कोर्टस से आ रहे हैं और पक्के हो रहे है। अगर सरकार ऐसे ऐम्पलाईज को पहले हो पक्का कर दे तो वह ऐहसान सारी सरकार मुफ्त में ले सकती है। साथ में जो फिजूल को खर्चा सरकार ऐसे केसिज पर कोर्टस में जाने पर करती है उसकी बचत हो सकती है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि स्टेट के अन्दर जितने भी ऐडहाक ऐम्पलाईज है, उसको पक्का किया जाए।

श्री सभापति: हरपाल सिंह जी, आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

कामरेड हरपाल सिंह: मांग वाईज बोल रहा हूं जी। यह सब कुछ जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही जाता है।

सभापति महोदय, अब मैं ऐस्मा के बारे में कुछ कहना चाहता है। ऐस्सा के तहत बहुत बड़ी विक्टेमाइजेशन शुरू हुई है। ऐसे काले कानूनों को खत्म किया जाए। सभापति महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार है और हम लोगों के सामने यह वायदा करके आए थे कि इस काले कानून को कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं करेंगे। (शोर) सभापति महोदय, लोगों ने मुझे यहां चुनकर भेजा है ताकि उनकी बातें असैम्बली के अन्दर रख सकूं। मैं तो जनता के प्रति जवाबदेह हूं, कृपया मुझे आप पूरी बातें यहां कहने का ज्यादा मौका दें।

सभापति जी, अब मैं डिमांड नम्बर 12, जोकि लेबर एण्ड ऐम्पलायमैंट से सम्बन्धित है, के बारे में बोलूंगा। सभापति जी, केन्द्र में हमारी सरकार ने यह वायदा किया है कि मैनेजमैंट के अन्दर मजदूरों की जिम्मेदारी होगी। इस बात को हमें हरियाणा के अन्दर भी लागू करना चाहिये। इसके साथ साथ सरकार का यह देखने का भी फर्ज बनता है कि जो मिनिमम वेजिज 800 रू. है, आया वे वेजिज की बात हर कारखाने में लागू है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवया जाए क्योंकि अभी पलवल के अन्दर मंगला उद्योग में गोली चली। वहां मजदूर तो अभी होस्पीटल में हैं लेकिन केस भी उन्हीं मजदूरों के ऊपर ही बनाये गये हैं, यह कितनी शर्म की बात है?

अन्त में मैं इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं कि जो जो सुझाव मैंने हाउस के अन्दर दिये हैं, सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करे। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद असलम खां (छछरौली): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहली बात मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मेहम में जो कुछ भी कुछ भी हुआ उसको बी. जे.पी. के आदमियों ने स्पश्ट कर दिया है कि वह कितना बड़ा कांड हुआ था। यह सिलसिला वहां पर सबसे पहले भी बनारसी दास गुप्ता जी के भाशण से शुरू हुआ था। (विघ्न) इस इशू के ऊपर इतना बोला जा चुका है कि और बोलने की गुंजायश नहीं है। इसलिए इस पर कुछ न कुछ कर मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। डिमांड न. 5 ऐक्साइज एंड टैक्सेशन की है। मेरे इलाके में एक किशनपुरा बैरियर लगा हुआ है। पहले जब राव साहब इस महकमें के मंत्री होते थे, मैंने उनसे भी दरखास्त की थी कि इसको वहां से उठाया जाए। इस बैरियर के आस पास के लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि बैरियर वाले ट्रोली और ट्रैक्टर वालेां से भी पैसे मांगते हैं। उस बैरियर को वहां से उठा कर कलेसर बैरियर पर लगाया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी इस मांग को जरूर मानेगी।

डिमांड न. 8 पर बोलते हुए मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता था लेकिन वे इस वक्त हाउस में

बैठे नहीं हैं लेकिन होम मिनिस्टर साहब नोट कर रहे हैं। हमारे यहां बोली नदी और सोम नही है। उस पर एक एक पुल बनना था जोकि 1988 में पूरे ही जाने थे लेकिन अभी तक वहां कुछ भी नहीं हुआ है। उनके लिए सारा पैसा वहां गया हुआ है। एक पुल से तो 23 टन लोहा उठा कर कहीं और ले गए हैं। उसके साथ एक अहम पुलिस डाक रोड से बलौनी की सड़क पर है। वह सड़क रायपुर रानी से डमौली को जाती है। मैं चाहता हूं कि उसको भी शीघ्र बना दिया जाए।

डिमांड न. 9 ऐजूकेशन के संबंध रखती है। खिजराबाद से यमुनानगर तकरीबन 30 किलोमीअर पड़ता है। खिजराबाद में हाई स्कूल है। दसवीं पास करने के बाद आगे पढ़ने के लिए बच्चों को 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस स्कूल को अपग्रेड करके दस जमा दो का बना दियसा जाए। क्योंकि बोली नदी पर पुल नहीं है इसलिए कोट के स्कूल को भी दस जमा दो का बना दिया जाए। अगर उस पुल पर काम की यही रफतार रही तो वह दस साल तक भी नहीं बना सकेगा। इसलिए उस पुल को शीघ्र बनाया जाए।

डिमांड न. 10 पब्लिक हैल्थ से संबंधित है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। सरकार ने वायदा किया है इस साल दिसम्बर तक सभी गांवों को पानी दे दिया जाएगा। लेकिन मेरे यहां तीन ढानियां हैं जिनके नाम है। – आमवाली, तिवडियो और रैडे, वहां की औरतें पीने के लिये जंगल से पानी लाती हैं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री महासिंह): चेयरमैन साहब, सरकार ने गांवों को पानी देने का वायदा किया हुआ है, ढानियों को नहीं। गांव उसको कहा जाता है जिसकी हदबस्त हो।

श्री मोहम्मद असलम खां: चेयरमैन साहब, पहले ये धानियां बेचिराग हुआ करती थीं। अब उनमें आबादी हो गई है और वहां चिराग जल गए हैं। अब मैं छछरौली के हस्पताल का जिक्र करूंगा। वह हस्पताल 1986 में मंजूर हुआ था, उसके फण्डज भी चले गए या नहीं पता नहीं क्या वजह है कि उसका काम शुरू नहीं हुआ है। पता नहीं कोई ठेकेदार उसका ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है या सरकार उसको बनवाने के लिए तैयार नहीं है। वह अस्पताल बहुत पुराना है और गिरने वाला है। उसकी बिल्डिंग इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि मरीजों को भी खतरा है। पता नहीं वे जिन्दा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसको बनवाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। इन अलफाज के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री देवी लाल (सोनीपत): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नम्बर 3, 9, 11 और 12 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मांग नम्बर 12 लेबर डिपार्टमैंट के बारे में है। सोपीपत एक इंडस्ट्रीयल एरिया है। वहां पर हजारौं की संख्या में मजदूर जिला सोनीपत की फैक्टरीज में काम करते हैं। हम उन मजदूरों को दो साल से यह कहते आ रहे हैं कि हमारी सरकार गरीब मजदूर और किसान की सरकार है। इस सरकार से आपको सब कुछ मिलेगा।

परन्तु सोनीपत जिले में यह देखने में आया है कि जिस भी फैक्टरी वाले ने मजदूरों को निकाल दिया है कि लेबर कोर्ट दे दरवाजे खटखटाने हैं और उन लेबरज को सालों साल लग जाते हैं उनका कोई फैसला नहीं हो पाता है। मजदूरों में इतनी ताकत नहीं है जोकि फैक्टरीज वालों का मुकाबला कर सकें। चेयरमैन साहब, लेबर मिनिस्टर साहब यहां हाउस में नहीं बैठे है, हमारे होम मिनिस्टर महोदय साहब बैठे हैं। मैं आपके द्वारा उनसे कहूंगा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लेबर कोर्ट में लेबरर्ज का फैसला एक महीने के अन्दर अन्दर हो जाए। यदि ऐसा कर दिया जाता है तभी हम उनसे यह कह पाएंगे कि यह गरीब मजदूर और किसान की सरकार है। चेयरमैन साहब, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिला सोपीपत में जो बी.एस.टी. फैक्टरी थी वह बंद हो गई। वह जिला सोनीपत की बहुत बड़ी फैक्टरी थी। वह फैक्टरी बन्द होने से सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है क्योंकि कोई आदमी कोई बात कहता है और कोई आदमी कोई बात कहता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार ने उस बी. एस.टी. फैक्टरी को खुलवाने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं? इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सोनीपत में जो मिलटन साईकल फैक्टरी है उसमें पिछले 6 महीने से मजदूर हडताल पर हैं। उसके मजदूर जगह जगह धक्के खा रहे हैं। हमारे मंत्री डाक्टर महा सिंह जी यहां हाउस में बैठे हैं। वह फैक्री इन्हीं के क्षेत्र में पड़ती है। वहां पर मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। मैं अपनी जनता दल की सरकार का ध्यान उन

मजदूरों की दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार उनके बारे में कोई न कोई विचार जरूर करें। इसके बाद मैं मांग संख्या 11 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह मांग म्युनिसिपल कमेटभ्ज के बारे में है। चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल यह प्रचार करते हैं कि शहरों के साथ ज्यादती हो रही है। इसके अलावा मैं एक बात कह बगैर नहीं रह सकता कि म्यूनिसिपल कमेटीज के पास फण्डज नहीं हैं। सरकार जो फण्डज देती है वे बहुत थोड़े हैं। शहरों की आबादी बढ़ रही है। जैसे कामरेड साहब ने कहा कि शहरों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शहरों के अन्दर भी 70 परसैंट गरीब और आम आदमी रहते हैं। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि 1990 में देहात और शहरों के लोगों को पीने का पानी मुहैय्या करवा दिया जाएगा। हमारी यह खुश किस्मती है कि हामरे जिले सोनीपत के ही पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर हैं। वह जानते हैं कि सोनीपत के अन्दर कालूपुर, गढ़ी ब्राहमण, झटपुर कालोनी, इन जगहों पर फैक्ट्रीज में काम करने वाले गरीब लोग कई कई सालों से रह रहे हैं उनके लिए वहां पर पीने के पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। उसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सोनीपत के अन्दर जो जटवाड़ा मोहल्ला है वह बहुत पुराना है। वहां पर जो नाला है उसकी प्रोपोजल बन कर डाक्टर महा सिंह जी के पास आई हुई हे। वह नाला वैसे म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर आता है परन्तु मैं अपने पब्लिक हैल्थ

मिनिस्टर महोदय साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी के पास फण्डल नहीं हैं इसलिए सरकार उसको जल्दी जल्दी बनवाने की कृपा करें। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सोनीपत के अन्दर एक लेबर कालोनी हे। उसके अन्दर कच्चे क्वार्टर्ज बने हुए है। वहां पर जो क्तार्टर्ज बन हुये हैं वे केवल 25–25 गज के है। जिस समय उन लोगों की हाउस टैक्स की असैसमैंट की जाती है तो उन पर हाउस टैक्स लगा दिया जाता है लेकिन जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके अन्दर 50–50 कमरे बने हुये हैं उनका हाउस टैक्स लगाने के लिए सर्वे करने वाले जाते हैं परन्तु उन पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगाते। दूसरी तरफ जो 25–25 गज के छोटे छोटे क्वार्टर्ज बने हुए हैं उन पर 100–100 रूपये हाउस टैक्स के लगा दिए जाते हैं। इस संबंध में मेरी सम्बन्धित मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि 25–25 गज के जो क्वाटर्ज हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब डाक्टर मंगल सैन जी उप–मुख्यमंत्री थे तो वे उन कच्चे क्वार्टरों में गए भी थे। वह बहुत बड़ा इलाका है। उस समय वे कह कर आये थे कि इन लोगों का हाउस टैक्स माफ कर दिया जायेगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं संख्या 9 जो शिक्षा से संबंध रखती है, पर अपनी बात कहना चाहूंगा। जब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो वे सोनीपत के जटवाड़ा मोहल्ले में गए थे। मैं उन्हें वहां लेकर गया था। वहां पर लड़कियों का जो स्कूल है

उको अपग्रेड करने का ऐलान वे करके आये थे। वहां के लोगों ने एक लाख रूपया इकट्ठा करके चौ. देवी लाल जी को दिया था और चौ. देवी लाल जी से उसे डबल करके वहीं लौटा दिया था। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्कूलों की अपग्रेडशन और डबल ग्रान्ट का मामला भी वहीं से शुरू हुआ था। वहां पर बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन वह स्कूल अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। वर्तमान सरकार ने भी कहा है कि चौ. देवी लाल जी द्वारा किए गए वायदों को पूरा किया जायेगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जटवाड़ा मोहल्ला में जो स्कूल है उसको अपग्रेड जल्दी से जल्दी किया जाये। मेरे हल्के के अन्दर बड़वासनी, मोहाना और जुआ स्कूलों की बहुत खस्ता हालत है। वहां के लिए शायद सैन्ट्रल सरकार से कोई ग्रान्ट आई होगी। (घंटी) चेयरमैन साहब, मैं न तो बजट पर ही बोला हूं और न ही किसी दूसरे विशय पर। हमें टोका–टोकी करने की भी आदत नहीं है। मुझे लोग कह रहे थे कि क्या आपने बोलना बन्द कर दिया है। मैंने कहा कि मुझे बोलना अच्छी तरह आता है। टोका–टोकी में मैं विश्वास नहीं करता। चेयरमैन साहब, मैं 5–7 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं और कोई इधर–उधर की बात नहीं कर रहा। मैंने बोलते हुए मजदूरों की समस्याओं का जिक्र किया है। इस तरफ किसी भी साथी ने सरकार का ध्यान नहीं दिलाया था। आज के दिन मजदूरों के साथ बहुत ज्यादती हो रही हैं। सरकार ऐसा कोई कानून बनाये कि यदि कोई फैक्टरी का मालिक किसी मजदूर को निकालता है तो उसे एक महीने का कम से कम नोटिस दे।

चेयरमैन साहब अब मैं डिमांड न. 2 जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखती है, पर अपने विचार रखना चाहूंगा। हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता जो सोपीपत म्यूनिसिपल कमेटी के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे हैं उनके बहनोई श्री रघुनाथ जी की मेहम में मौत हुई है। उनकी 27–28 फरवरी को शायद बूथ नं. 59–60 पर डयूटी थी, और ये जनता दल के कार्यकर्ता थे और हांसी के जनता दल दफतार में रहते थे। मेहम की घटना के 3–4 दिन बाद उनकी मौत हुई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इसकी इन्कवायरी कराई जाये और दोशियों का गिरफतार किया जाये।

चेयरमैन साहब, सोनीपत में एक ड्रेन न. 6 है। इस ड्रेन पर सैक्टर 14 और 15 तक जाने के लिए एक पुल बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाये ताकि लोगों को आने–जाने में आसानी हो सके। चौटाला साहब जब वहां पर गए थे तो उनको भी यह मौका दिखाया था। उन्होंने इस पुल के लिए हां कही थी। इस पुल के बनने से सारे शहर का सीधा संबंध हो जाएगा। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से रेलवे लाईन से लेकर शूगर मिल, सोनीपत तक लोगों की कुछ जमीन पड़ी हुई है अभी तक वहां पर सरकार की तरफ से या हुड्डा की तरफ से कोई प्लौट नहीं काटे गए हैं। बीच के दलाल लोग लोगों को कन्ट्रोल एरिया की जमीन बता कर लोगों से वह जमीन खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार

यहां पर प्लौट काट रही है। लोग डरते हुए अपनी जमीन ऐसे लोगों को दे रहे हैं। अगर सरकार को कोई सैक्टर बनाया है या कोई और योजना सरकार की हो तो सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और अपना पूरा कन्ट्रोल रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जमीदारों की जमीन के ऊपर सरकार कोई नियंत्रण नहीं रहेगी। चेयरमैन, साहब, आपने बोलने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौंद): चेयरमैन साहब, मैं सरकार की आलोचना करने करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं केवल अपनी बात ही कहूंगा। मैं श्री भागी राम जी का अग्रिम धन्यवाद करता हूं इस आशा के साथ कि वे बीच में टोका–टाकी नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं मांग नम्बर–3 पर अपनी बात कहूंगा। अगर यह कहें कि मेहम के मामले को बार–बार उछाला जा रहा है तो मेहम के मामले में मेरी कोई रूची नहीं है लेकिन जहां तक लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र की बात है मैं कहना चाहूंगा कि कि इन घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिए। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए। जिस हिसाब से जनता दल की सरकार में जो कुछ हुआ है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन लोकतन्त्र की मांग यह है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि सरकार लोकतन्त्र में विश्वास रखती है।

जिन लोगों को इन घटनाओं में क्षति पहुंची है सरकार को उन लोगों को हर प्रकार से कम्पनसेट करना चाहिए तथा इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी लापता हैं उन लोगों के परिवारों को भी इसी तरह से कम्पनसेट करना चाहिए ताकि उन लोगों को महसूस न हो कि उनके साथ नाइन्साफी हुई है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि किन कारणों से अपनी डियूटी के तहत उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि उनके परिवारों को यह महसूस न हो कि उनकी तरफ यह सरकार ध्यान नहीं दे रही। अपनी डियूटी के दौरान उन्होंने जैसा महसूस किया वैसा नहीं होना चाहिए, यह चिन्ता की बात है। चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं मांग संख्या–8 पर बात करूंगा यह पी.डब्ल्यू. डी. से सम्बन्धित है। मेरे हल्के में भी कुछ सड़कें मन्जूर हुई थी। डाका से खेड़ा, पेडा से अलेवा और बनिया से तेलो खेड़ी, ये छौटे–छोटे टुकड़े हैं। जब से इन लिंक रोडज का काम मार्किटिंग बोर्ड के पास गया है, इसमें कोई खात विकास की बात नहीं हुई पता नहीं इनके पास इन्जीनियर्ज नहीं हैं, या स्टाफ नहीं है या फण्डज की कमी है जो भी कारण हैं उनको दूर करके शीघ्र ही इन टुकड़ों का निर्माण करवाया जाए।

चेयरमैन साहब, यहां पर स्कूलों की बात भी आई है। आज तक जो स्कूल अपग्रेड किये गये हैं उनमें मेरे हल्के के स्कूल अपग्रेड नहीं किये गये। स्कूलों में पूरी तरह से स्टाफ उपलब्ध

नहीं करवाया गया है। कहीं मैथ मास्टर्ज की कमी है तो कहीं साईन्स मास्टर की। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने स्टाफ की जरूरत है उतना स्टाफ स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाए। मेरे हल्के में 2–3 गांव बड़े–बड़े हैं जो शहर तो नहीं है परन्तु शहर यहां से दूर पड़ता है और बच्चों को पढ़ने के लिए जाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 10 जमा 2 के स्कूल अलेवा और नगूरा गांवों में भी खोले जाएं।

चेयरमैन साहब, इसके बाद में चिकित्सा सुविधा की तरफ सरकार का थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस मद के लिए बजट में जितना प्रावधान है, आमतौर पर उसका ज्यादा हिस्सा शहरों में अस्पताल बनाने पर खर्च होता है। जहां तक देहात की बात है देहात के लोगों को उतनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है जितनी आवश्यक है। मेरे हल्के के गांव अलेवा को भी अभी ब्लौक बनाया गया है। 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल जी ने वहां पर 10 बैडज का हौस्पीटल बनाने की घोशणा की थी। मैंने इस बारे में सरकार को कई बार लिखा है और पिछले सैशन में भी इस मुददे को उठाया था, उसके बावजूद भी अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गांवों के लिए ट्रेन्ड दाई या ट्रेन्ड नर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में प्रसूति के समय कई बार दुर्घटनाएं घट सकतीं हैं और आमतौर पर ऐसी घटनाएं घटती भी रही हैं इसकी तरफ

सरकार गौर करे। प्रत्येक गांव के लिए या देहाती बस्तियों के लिए एक ट्रेन्ड दाई की सुविधा जरूर उपलब्ध करवाई जाए।

जहां तक शहरों के विकास की बात है, इस बारे में भी मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूं। मांग न. 11 नागरिक विकास के बारे में है। आप जानते हैं कि शहरों में लगातार आबादी बढ़ रही है जहां भी लोगों को सस्ती जमीन मिलती है, वहीं पर गांव से आने वाला नया आदमी प्लौट खरीद कर मकान बना लेता है वहां अन–प्लांड ढंग से हैपहैजर्ड वे में बस्तियां बसती जा रही हैं। उन बस्तियों में पानी के निकास, सीवरेज, नालियों, गलियों और स्ट्रीट लाईटों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए इन बस्तियों की ओर भी यदि सरकार गौर करे तो बहुत बढ़िया बात होगी।

अब मैं मांग नं. 15 पर जो इरीगेशन के बारे में है, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मेर हल्के में पूर्व–इरीगेशन मिनिस्टर चौ. वीरेन्द्र सिंह ने पेगा–माजरी तथा हसनपुर माइनर्ज बनाने का ऐलान किया था। यह ऐलान अप्रैल, 1989 में अलेवा गांव में किया था कि एक महीने में इस माईनर का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस तरफ गौर किया जाए क्योंकि वहां के लोगों को पानी की बहुत जरूरत है।

अब मैं मांग न. 16 के सम्बन्ध में, जो उद्योगों के बारे में है, कुछ जिक्र करना चाहता हूं। यमुनानगर, पानीपत में बड़े–बड़े उद्योग हैं, और धारूहेड़ा में भी इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स बन रहा है, लेकिन बड़ी चिन्ता की बात है कि बड़े–बड़े उद्योग बन्द होने जा रहे हैं। इनके बन्द होने का कारण क्या है, इसकी छानबीन की जाए और सरकार इस तरफ ध्यान दे कि क्या रूकावट पैदा हुई है जिसके कारण जगह–जगह कारखानों में हड़तालें हो रही हैं। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि उद्योग डिपार्टमैंट में दो विंग हैं – एक बड़े उद्योगों को डील करता है और दूसरा छोटे उद्योगों को डील करता है। आप जानते हैं कि दिन–प्रतिदिन नौजवान बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए बेरोजगार नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सैंटर खोलकर नये–नये उद्योग लगाने के बारे में बताया जए कि किस तरह से नये उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उन्हें क्या सुविधाएं सरकार देना चाहती है और क्या दी जा रही हैं उनकी जानकारी के लिए जगह–जगह पर ब्यूरो खोले जाए और उन नौजवानों को ट्रेनिंग देकर जिस उद्योग की वे काबलियत रखते हों, उसके लिए उन्हें तैयार किया जाए ताकि बेरोजगारी पर कंट्रोल हो सके।

इसके बाद मैं कृशि के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, तीन या सवा तीन महीने से हमारी सरकार केन्द्र में आई है। हमारी विपक्ष की मांग थी कि केन्द्र में हमारी सरकार

आए और उसके लिए हमें जनता से समर्थन मिला। जब से केन्द्र में हमारी सरकार आई है तक से 14–15 रूपये खाद के कट्टे का भाव बढ़ गया है। इसके बारे में किसानों में बड़ा भारी रोश है। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

मांग न. 18 पशु पालन विभाग के बारे में है, चेयरमैन साहब, आम तौर पर हम बाहर की नसल के पशु खरीद लेते हैं हमारे हरियाणा की भैसों में मुर्रा नस्ल की भैंसें बहुत अच्दी हैं। मेरा कहना यह है कि किसानों को सुधरी हुई किस्मों की भैंसे देने की व्यवस्था की जाये। उनकी इस बात की भी जानकारी दी जाये कि उनको आसानी से यह दुधारू पशु कहां से उपलब्ध किये जा सकते हैं।

चेयरमैन साहब, अब मैं मांग न. 23 के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यह परिवहन विभाग से ताल्लुक रखती है। बसों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। दो बसों की सवारियां एक बस में बैठ जाती हैं, छतों पर भी बैठ जाती हैं। कई बार तो इस वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और कई बार बसों में गड़बड़ भी पैदा हो जाती है। टायर फट जाए या पंक्चर हो जाए इससे सवारियों को बड़ी दिक्कत होती है। एक बात यह है कि बसों में आम तौर पर सफाई की तरफ ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार बसों के पतरे उखड़े रहते हैं। कीलें उखड़ी रहती हैं जिसकी वजह से यह होता है कि सवारियों के कपड़े फट जाते हैं। इन बातों की तरफ भी यदि ध्यान दिया जाये तो ठीक रहेगा। मेरी

कांस्टिचुऐन्सी में राजौंद गांव में एक अड्डे का निर्माण होना था। पिछले दिनों उसके लिए आश्वासन भी दिया गया था परन्तु अभी तक भी उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं इतनी बात कह कर ज्यादा छेड़–छाड़ न करते हुए, आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री मनी राम (डबवाली–अनुसूचित जाति): सभापति जी, आपने चूंकि मुझे डिमाडज पर बोलने के लिये टाईम दिया है, इसलिए सबसे पहले तो में इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं डिमांड न. 15, 9, 23, 20 और 16 पर अपने विचार रखना चाहूंगा और अपने इलाके की कुछेक मांग भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं इरीगेशन के बारे में अपने हल्के की जो समस्या है, वह बताना चाहता हूं। हमारे हरियाणा का किसान बड़ा मेहनती हे। किसानों को अगर बिजली और पानी पूरा मिले तो यहां ज्यादा प्रोडक्शन होगी। मेरे हल्के में एक मसीता माईनर है। उसकी लाइनिंग हो चुकी है लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से पक्की नहीं हुई है। जब भी सैशन होता है, मैं इस बारे में सवाल भी पूछता हूं। इस माईनर के पक्का न होने के कारण उस क्षेत्र के रकबे में आबपासी नहीं हो पाती और किसान ज्यादा फसल नहीं उगा सकता। इसी तरह से एक कस्सी न. 6 माईनर है। वह डबवाली डिस्ट्रिब्यूटरी से निकलती है। मेरे हल्के में एक गांव शेरगढ़ है। यह माईनर उस गांव के रकबे को पानी देती है। आपको पता ही है कि जो रकबा टेल पर पड़ता है, वहां पर पानी

नहीं पहुंचता। मेरा सारा हल्का रजबाही है। वहां पर जब तक उनको पक्का नहीं किया जाता तब तक पानी आसानी से नहीं पहुंचता है। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन मसीता माईनर और कस्सी न. 6 माईनर को जल्दी से जल्दी पक्का करवाये।

ऐजूकेशन के बारे में सदन के सदस्यों ने काफी चर्चा की है। इस चालू वित्त वर्श में हमारी सरकार ने प्राईमरी स्कूल 100 के नजदीक खोले हैं और कई स्कूलों को प्राईमरी से मिडल, मिडल से हाई और हाई 10 प्लस 2 के दर्जे दिये गये हैं लेकिन इन स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है। सरकार ने स्कूल तो खोल दिये या उनका दर्जा तो बढ़ा दिया लेकिन उनके अन्दर स्टाफ पूरा नहीं होता। इनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुक्सान होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो स्टाफ की कमी है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान न हो।

डिमांड न. 23 जो ट्रांसपोर्ट के बारे में है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा की बसिज सबसे बढ़िया हैं। राम बिलास शर्मा जी ने भी कहा कि जब हमारी बस खड़ी होती है, तब पंजाब की राजस्थान की या किसी दूसरी स्टेट की बसों में लोग बैठना पसन्द नहीं करते। हमारी बसें 10 लाख किलोमीटर के करीब दूरी रोजाना तय करती हैं। इनमें लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं। इस हिसाब से हरियाणा की

बसें नम्बर वन पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे डबवाली हल्के में जो लोकल बसिज चलती हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। वहां पर बसें बहुत टूटी–फूटी हुई हैं। इससे वहां की सवारियों को बड़ी तकलीफ होती है। इस साल सरकार मिनी बसिज खरीदने जा रही है। मैं वजीर साहब से यह कहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिनी बसिज दी जायें। दूसरी बात यह भी है कि लम्बे रूटस की बसिज वहां पर रूकती नहीं है। जो स्कूलों का स्टाफ है, उनको भी वह नहीं उठाती।

अब मैं सामान्य प्रशासन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, मेहम कांड को जितना उछाला गया है इतना नहीं उछाला जाना चाहिए था। इस बारे में मैं चर्चा तो नहीं करना चाहता था लेकिन सदन के सदस्यों ने जिस ढंग से इसको उछाला है वह ठीक नहीं है। मेरी वहां पर 27 तारीख की डियूटी थी। इस मामले में प्रैस वालों का कोई कसूर नहीं है। डांगी की जेली ब्रिगेड ने और उसके दूसरे समर्थकों ने तथा कार्यकर्ताओं न चौ. देवी लाल के खिलाफ बहुत ही भद्दे नारे लगाए थे। कुछ लोग कहते थे कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला को वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और उनको कुरूक्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए था। असली बात यह है कि प्रैस वालों हमारे साथ सम्पर्क न होने के कारण उनको जो रिपोर्ट मिली उन्होंने उस रिपोर्ट को छाप दिया। प्रैस में जो कुछ आया उसको पढ़ने के बाद लोग भावुक हो गए। चेयरमैन साहब, 27 तारीख तक वहां कोई बात नहीं हुई।

सब कुछ शांति पूर्ण रहा। जो पोंलिग एजेन्ट थे उनके दस्तखत और अंगूठे हैं और उन्होंने कोई शिकातय नहीं की। प्रिजइडिंग औफिसर्ज को कोई रिपोर्ट नहीं आई। वहां पर लोगों ने जानबूझ कर प्लान बनाया था। प्रैंस वाले मोखरा की बात करते हैं लेकिन इसमें सच्चाई नही है।

श्री सभापति: यह मैटर सब–जुडिस है अच्छा यह रहेगा कि आप इस पर न बोलें।

श्री मनी राम: सभापति जी, मैं 27 तारीख की बात कर रहा था कि उस दिन इलैक्शन में धांधली के बारे में कोई कम्पलेंट नहीं आई।

सभापति जी, अब मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। आपको पात है कि मेरे इलाके में कपास बहुत होती है। वहां पर स्पिनिंग मिल या जिनिंग मिल नहीं है। वहां स्पिनिंग मिल न होने के कारण हमारी कपास पंजाब में अबोहर और मलौट को चली जाती है जिससे किसाना को भी नुक्सान होता है और सरकार को भी नुक्सान होता है। मैंने इस बारे में सवाल भी किया था लेकिन उसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कोई जिनिंग लि या स्पिनिंग मिल लगनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

सभापति जी, अब मैं अपने यहां की सड़कों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। गोरी वाला से फूटी गांव की सड़क

दो तीन किलोमीटर लम्बी है। उसकी प्रोग्रेस ढीली है। यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. ने बनानी थी। जब हम पी.डब्ल्यू.डी. महकमें के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि मार्किटिंग बोर्ड बनाएगा और जब मार्किटिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो वे कहते है कि पी.डब्ल्यू.डी. वाले बनाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। दूसरी सड़क भारू खेड़ा से चौटाला की है। इसका फासला चार या साढ़े चार किलोमीटर है। इसको मार्किटिंग बोर्ड ने बनाना है। इसकी बनाने की गति बड़ी धीमी है। मेरी प्रार्थना है कि इसकी बनाने की गति को बढ़ाया जाए। एक चौटाला गांव से चेतक रोड़ हैं। यह सवा किलोमीटर का फासला है। सभापति जी इस सड़क पर बड़ी बजरी नहीं डाली गई है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर जल्दी काम होना चाहिए। सभापति जी, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इलाके के जितने भी काम हैं उनको जल्दी करवाया जाए। इतना ही कहकर मैं खत्म करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।

***श्री आत्मा सिंह गिल** (रतिया–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपकी आज्ञा नाल श्री गुप्ता जी ने जो बजट पेश कीता है उदा समर्थन करदा हां। कांग्रेस सरकार जेहड़ी 38 साल तक रही ओहने इस देश के अन्दर कोई कम नहीं कीता पर जनता सरकार ने, जेहड़ी पहले तीन साल रही ते हुण जिनू बने अढ़ाई साल हो गए ने, इस साढ़े पंज साल विज इतने कम कीते ने जो कांग्रेस ने चालीस साल विच वी नहीं कीते। चौ. देवी लाल

ने जो वायदे कीतेसी, सारे पूरे कर दिते गये ने। कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करके वोट लैदी सी पर चौ. देवी लाल ने जो वायदे कीते ओर तमाम पूरे कर दिते। जो बेरोजगार मुण्डे थे। उन्हा नूं रोजगार का मौका दिता गया और जिनां मुंडियां नूं इन्टरव्यु ते जान वास्ते मुशकलातां दा सामना करना पैदा सी और ओहनां दे कोल पैसे वगैरह नहीं होदें सन, ओहनां नूं फ्री बसिज ते तान जान दी छूट दे के इस सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कम कीते हन जेहड़ें कि शलाघा दे योग्य हन। यह सारी चौ. देवीलाल जी दी ही देने है। जिन किसानां दी जमीन दे नाल नाल दरख्त होंदे सन चौ. देवी लाल जी दी सरकार ने ओहनां दरख्तों नू बेचन तों बाद अध ओहनां किसानों नूं वी दित्ता जिसदे नाल किसान भाईयां नू काफी लाभ पहुंचया। इस तरह नाल चौ. देवीलाल जी ने जिन्ने वी वायदे लोगों दे नाल किते सन ओह सब पूरे कीते लेकिन कांग्रेस सरकार दे अन्दर ऐह गल्लां नहीं सन। ओहनां लोगों दो हिसाब किताब ही कुछ और होंदा सी। जो 60–65 लोग इत्थे चुनकर आए हन, वे सब चौ. देवीलाल जी दे गुण गांदे हन और जिन लोगों ने ओहनां दे नाल गददारी कीती है, वे बिल्कुल मेरी नजर दे सामने बैठे हन लेकिन मैं ओहनां दा नाम नहीं लेना चाहदां। वे भाई पार्लियान्मैंट के इलैक्शन में मेरे हल्के रतिया के अन्दर रात 8 बजे पहुंचे और चौ. भजन लाल दा ओहदां नूं इन टेलीफोन आया और ओहनां ने फोरन ही इस्तीफा दे दिता। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुआ) मैं इतना ही कह सकदां हां असी सारे ऐथे अज चौ. देवीलाल जी दी ही बदौलत बैठे हां ओर हमें यह पता ही है

कि किस तरह से वोट लिते जांदे हन। जितने वी.एम.एल.एज. ऐथे बैठे हन ओ सारे चौ. देवीलाल जी दी छत्र छाया नाल ही बैठे हन। ओहनां दे आर्शीवादां नाल ही ओह सारे ऐथे चुनके आ गये हन। मैं इतना जरूर कहांगा कि जेहड़े लोग चौ. देवीलाल जी नूं धोखा देकर चले गये हन ओहनां नूं कल नूं पिण्डां विच कोई वी घुसन नहीं देगा। ओ मेरी ऐ गल्ल पल्ले बन लैन कि जो जो चौ. साहब नाल गद्दारी करके गया है, ओ कदी वी इस हाउस विच दोबारा चुनके नहीं आ सकदा। जिन्नां ने चौ. देवीलाल जी की पगड़ी दी लाज रखी है, ओह लोग ही दोबारा ऐथे चुनके आवनगे। मेरा पक्का विश्वास है कि चौ. देवीलाल जी व चौ. औम प्रकाश चौटाला जी जो कम करन दी ठान लैनगे, उस कम नूं ओह दिनों में ही कर देन गे लेकिन ओहनां दी टंग्गा खिचन वाले वी बड़े लोग ऐथे बैठे हन जिन्ना नू हरियाणा दी जनता कदी वी माफ नहीं करेगी। मैं औहनां नूं ऐह गल्ल कहना चाहदां हां कि कुर्सी कदी वी किसे दे नाल नहीं रहदीं और कुर्सी ओहनां दे नाल रहेगी जिन्नां ने कुछ त्याग कीता होवेगा। (इस समय श्री किरपा राम पुनिया उठकर कुछ कहने लगे।) पुनिया साहब ने तुहानूं ऐह गल्ल दस देवां कि कुर्सी हमेशा ओहनां दे नाल रहेगी और रही है जिन्नां लोकां ने त्याग कीता होवे। तुसी तां आई ए.एस. अफसर रहे हो, तुहानूं की पता कि राजनीति की होदी है। राजनीति दे बारे साडे कोलों पुछो जिन्नां ने साईकिलां ते गांव–गांव चलके लोगां दी सेवा कीती है। आप लोक तां चौ. देवीलाल जी नूं धोखा देने वालों में से हो। आप ओहनां दी बदौलत ही ऐथे आए हो।

(शोर) चौ. देवीलाल जी ने लोगां नूं हर लिहाज दी सहूलियतें प्रदान कीतियां हन। जितनी पुलिस की भर्ती चौ. देवी लाल जी दे समय विच होई ओनि भर्ती अज तक किसे दे राज विच नहीं होई। स्पीकर साहब, तुहानूं पता ही होवेगा कि अज पंजाब विच, बिहार विच या मेहम विच जो कुछ होदया ऐह सब कुछ ऐहनां कांग्रेसियां ते विरोधी पार्टियां दा ही कम है। ऐह लोग ही सब कुछ ऐहनां कांग्रेसियां ते विरोधी पार्टियां दा ही कम है। ऐह लोग ही सब कुछ करवा रहे हन और चौ. देवीलाल जी दा नाम बदनाम करदे हन। मेहम दे विच चौ. बंसी लाल दे मुन्डे दा हथ सी, चौ. भजन लाल दा हथ सी। ओहनां ने ही इह सब कुछ करवाया है। मैं इक गल होर दसनी चाहंदा हां।

17.00 बजे

अज तक किसी सरकार ने इस तरां नहीं कीता जिस तरां भजन लाल दी सरकार ने कीता। टोहाना अते फतेहाबाद बिच बाई इलैक्शन होए। ओथे डकैतियां मारियां गईयां पर किसी ने उसदी इन्क्वायरी नहीं करवाई। जदों मेहम दे अन्दर इलैक्शन होए तां साडे सी.एम. साहब ने ओथे होइयां वारदाता दे बारे झट इन्क्वायरी बिठा दिती। जेहड़े लोग गुनाहगार होनगे ओह सजा भुगतनगे। मेरे भरावों ते साथियों क्यों डरदे हो जिस आदमी ने टिकट दिता है उस दे नाल रहो। साडे दो साल हाले बाकी रहंदे हन। सानू सारे साथियां नूं चाहीदा है कि असीं इकट्ठे रहके राज चलाइये नहीं तां गहां वास्ते किसी नूं एम.एल.ए. नहीं बनना, सारे

देश दे अन्दर बदनामी हो जाऊगी। इसी तरां पंजाब बिच साडे अकाली भाइयां ने भी आपसी लड़ाई दी वजा नाल अपना राज खोया सी। इस करके मैं जनता दल दे साथियां नूं कहंदा हों कि कुर्सियां वल न देखो अते राज नूं संभालो। जिस तरां असीं अतकी कांग्रेस दी सफाई की ती है उसी तरां अगे वी करनी है, किते ओह फेर न आ जाए।

Capt. Ajay Singh Yadav: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: Please take your seat, take it lightly.

श्री आत्मा सिंह गिल: स्पीकर साहब, ऐह जो साडी सरकार बनी हे ऐह चौ. देवी लाल जी दी देन है। जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान बिच घुम के अपोजीशन दियां सरकारां बनवाइयां हन। सारे हिन्दुस्तान बिच इन हरियाणा ही ऐसा सूबा होगा जित्थे सब तो ज्यादा लोगां दे कम होनगे। इस लई मैं बेनती करदा हां कि जो साथी सानूं छड के ओधर चले गए हन ओह वापस आ जान। जे ओहनां नूं कुर्सियां चाहिहियां हन तां मैं इक छोटा जिहा चेयरमैन हां मैं अपनी कुर्सी छड्डन नूं तैयार हां। मैं इनां दी तरां गद्दारी नहीं करदा।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने कहा था कि हम कुर्सी छोड़ कर भाग गए। दूसरी तरफ ये कह रहे है कि सारे कुर्सी छोड़ दो यानी कुर्सियां की तरफ न देखो। क्या ये कुर्सी छोड़ने के लिए अपने साथियों को कह रहे हैं क्योंकि हमने तो कुर्सी छोड़ दी है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वांयट औफ और्डर नहीं है। गिल साहब आप बोलिए।

श्री आत्मा सिंह गिल: स्पीकर साहब, जेहड़े साथियों ने पार्टी नहीं छड्डी ओहना दी सीट पक्की रहेगी। जो पार्टी छडड गए हैं वे अज वी माफी मंग के एधर आ जाएं। हुन मैं अपने हलके दियां गल्लां करना चाहंदा हां। मेरे हल्के बिच कालेज, हस्पताल और सड़कां बनौनियां चाहीदियां ने। मेरे हल्के बिच इन रंगोई नाला है। अगर ओह न बनया तां लोगां दियां फसलां तबाह हो जानगियां। मैं मंत्री जी नूं बेनती करदां हां उस वल ध्यान दित्ता जावे। बस मैंने अैना ही कहना सी। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं होम डिपार्टमैंट की मांग पर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि इस सरकार के बनने से पहले हरियाणा प्रदेश की हालत बहुत ही खराब थी। जब मैंने फतेहाबाद हल्के से 1983 में एक बाई इलैक्शन में चुनाव लड़ा था उस बाई इलैक्शन में सैंकड़ों आदमी जख्मी हुए थे। किसी का हाथ टूट गया और किसी का पांव टूट गया। सैंकड़ों ही आदमियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे। मोहम्मदपुर–रोही चौ. भजन लाल का गांव है उसमें इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की गई थी कि वहां सैट परसैंट वोट डाले गए थे। उस गांव में 2200 वोट में से केवल 3 वोट छोड़ कर बाकी सारे वोट पोल हुए थे। इस प्रकार से उस गांव में लोकतन्त्र की हत्या की गई थी। उस समय चौ. भजन लाल ने जोर

जबरदस्ती से अपना उम्मीदवार 1300 वोटों से जिताया था। उसका सारे हरियाणा में असर पड़ने लगा। उसके बाद 1985 में टोहाना हल्के को बाई इलैक्शन हुआ। उस बाई इलैक्शन के दिन चौ. सम्पत सिंह जो भूना में थे। इस समय पांडेचेरी की उप राज्यपाल श्रीमती चन्द्रावती जी भी उस समय भूना में थीं। मैं उस दिन चौ. सम्पत सिंह के साथ टोहाना में था। उस दिन चौ. भजन लाल सैंकड़ों आदमियों के साथ मार्किट कमेटी के बूथ पर गये और वहां पर चौ. भजन लाल और चौ. सम्पत सिंह का आमाना सामना हो गयां उस समय हम भा चौधरी साहब के साथ थे। वहां पर लड़ाई होते होते बची थी। वहां पर इस प्रकार से धांधली की गई कि किसी भी पंजाबी भाई को वोट नहीं डालने दिया गया। टोहाना से श्री श्याम लाल सरदाना ने जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह टोहाना का पंजाबी भाई है। इसलिये लोगों का यह विचार था कि सभी पंजाबी भाई सरदाना साहब को वोट देंगे लेकिन वहां पर एक भी पंजाबी भाई को वोट नहीं डालने दिया गया। उससे और ज्यादा हालात बिगड़ने लगे। उसके बाद 1986 में तोशाम हल्के का बाई इलैक्शन हुआ उसमें चौ. बंसी लाल को 86 हजार वोटों से जीता हुआ दिखाया गया जिस प्रकार से बंसी लाल ने उस बाई इलैक्शन में धांधली की उसके बारे में। सभी को पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के नोटिस में यह बात लाना चाहता था कि किस प्रकार से उन लोगों ने चुनावों में धांधलियां की।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है माननीय सदस्य ने 1986 में तोशाम के बाई इलैक्शन को चर्चा करते हुए कहा कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद 1987 के इलैक्शनज हुए क्या उनमें बूथ कैप्चरिंग नहीं की गई? (शोर)

Mr. Speaker: This is not point of order. Please take your seat. Balbir Singh Ji, please go ahead.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस सरकार के बनने से पहले हरियाणा के अन्दर जितने भी चुनाव हुए उनमें मिसयूज औफ पावर हुआं इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, भ्रश्टाचार इस हद तक पहुंच गया था कि फतेहाबाद के बस अड्डे पर एक स्वीपर लगना था उससे भी चार हजार रूपए रिश्वत के लिए गए। उस समय यदि किसी को सिपाही को नौकरी के लिये जाना होता था तो जैसे भेड़ बकरियों के गले में पर्ची लगा दी जाती है उसी तरह से भजन लाल का भतीजा जिसकी फतेहाबाद में एक दुकान है, टैम्पों में 20–30 आदमी बैठाता था उनके हाथ में पर्ची पकड़ा देता था और उनसे 20–20 हजार रूपए ले लेता था और उनको भर्ती करवा देता था। उस समय किसी भी महकमें में नौकरी लगना होता था तो बगैर रिश्वत लिए नौकरी नहीं मिलती थी। उसका सबूत है। हर महकमे में हर नौकरी नहीं मिलती थी। उसका सबूत है। हर महकमें में हर नौकरी बेची जाती थी। भजन लाल के समय में भ्रश्टाचार चर्म

सीमा पर था। अध्यक्ष महोदय, 1985 में सब पार्टियां ने मिलकर चौ. देवी लाल जी और डा. मंगल सैन जी की अगवाई में भजन लाल के खिलाफ एक मैमोरैंडम दिया। उसके बाद जब हरियाणा पंजाब का समझौता सामने आया तो उसने हरियाणा के हितों को बलि चढ़ाया और उस समझौते ने आग में घी डालने का काम किया। इस प्रकार से चौधरी साहब की अगुवाई में लोकदल और बी.जे.पी.पाटी ने मिलकर लोकतन्त्र की रक्षा के लिए और लोगों के अधिकारों के लिये एक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई से सारा हरियाणा जाग कर खड़ा हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय लोगों के जनतांत्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं थे। लोगों को किसी भी महकमें में न्याय नहीं मिल पाता था, और हर बात का मोल पड़ चुका था। इसी बात को सामने रखते हुए चौ. साहब ने 'भ्रश्टाचार बंद और बिजली और पानी का प्रबन्ध' करने का नारा लगाया। यहां तक पंजाब से पानी लाने के लिए भी चौ. साहब ने नारा लगाया। उनके दिल में लोगों की भावनाएं थी। लोग उस समय के हालात से दुखी आ चुके थे। वे तबदीली चाहते थे। इसलिए वे उस समय सारे लोग एक साथ चौधरी साहब के साथ खड़े हो गए। उस समय चौधरी साहब ने जो संघर्श किया उस संघर्श के दौरान हमारे तीन साथी भी शहीद हो गए थे।

Mr. Speaker: Only 5 minutes are left. I am not going to allow you more than 5 minutes.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही बैठ जाता हूं। उस समय सारी लड़ाई न्याय के लिए लड़ी जा रही थी। जब बाद में चुनाव का उदघोश हुआ तो उस समय चौधरी साहब ने लोगों से कुछ वायदे किए थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वे सभी वायदे पूरे किए। चाहे बुढ़ापा पैन्शन थी, कर्जा माफी की घोशणा थी या कमजोर वर्गो के लिये और कोई सुविधा देने की बात थी। चाहे हमारे बच्चों को इन्ट्रव्यू पर जाने के लिए बगैर टिकट की सुविधा देने की बात थी, चाहे हरिजन महिलाओं को दो या तीन बच्चों तक पैदा करने पर 300 रूपया खुराक के देने की बात थी वे सभी बातें लागू की और चुनाव में किए गए सभी वायदों को पूरा किया। इसी प्रकार से सारे प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए व गांव में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए बागवानी का एक अलग से निदेशालय बनाया। दिल्ली के आस पास के एरिया से रहने वाले लोगों को सब्जी की अधिक पैदावार दिलाने की स्कीम बनाई। इसी प्रकार से कैथल, भूना और मेहम में शूगर मिलों की स्थापना की। इन मिलों के बारे में कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन चौधरी साहब ने आते ही इसे पूरा किया। इसी प्रकार से वन निगम भी अलग से बनाया गया। इसी तरह से उद्योग विभाग में तीन अलग से विभाग बनाये गए। ये तीन विभाग छोटे और कुटीर उद्योग, बड़े और मध्यम वर्ग के लिए बनाये गए। खनिज और भू विज्ञज्ञन का अलग से विभाग बनाया गया इस बजट में भी और उत्थान के लिए बहुत पैसा रखा गया है। अब यह सरकार नारनौल, फरीदाबाद और हिसा में तीन नए

तकनीकी संस्थान खोलने जा रही है। सोनीपत में कैमिकल इन्जीनियरिंग संस्था, मूरथल में कम्पयूटर विभाग की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है। हमारी वर्तमान सरकार ने हरियाणा के समुचित विकास के लिए पूरा प्रावधान रख है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कन्स्ट्रक्टिव बात कहना चाहूंगा। पहले हरियाणा में नौकरियां बेची जाती थीं और क्रप्शन बहुत अधिक था। वर्तमान सरकार पर कोई भी नौकरियां बेचने का लांछन नहीं लगा सकता। जो नौकरियां पहले बेची जाती थी वह सिलसिला अब बंद हो गया है। लोकदल की मिली जुली सरकार का लोगों को समान अधिकार देने का नारा था।

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, you please wind up.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा सैशन है मुझे बोलने का समय नहीं मिला इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय और दिया जाए।

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, I am very sorry. You please wind up. I have to accommoduate five more persons.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की आलोचना तो नहीं करता लेकिन नौकरियां के मामले में सरकार को अपनी वर्तमान नीति में कुछ सुधार करना चाहिए। हरियाणा की जनता कहती है कि जो नौकरियां दी जाती हैं वे मैरिट क आधार पर कतई नहीं दी जाती इसलिये सरकार को चाहिए कि इन नौकरियों के लिए मैरिट तय करने के लिये कोई प्रोसीजर

प्रैस्क्राईब किया जाए जिससे जनता को लगे कि नौकरियां वाकई ही मैरिट के आधार पर दी जा रही हैं। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी नौकरियों में बराबर का भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत पद ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रखें जाएं जिन्होंने दसवीं को कक्षा किसी गांव के स्कूल से पास की हो। इस बारे में मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था। यदि हमारी सरकार इस प्रकार का पग उठाएगी तो उससे गांव के लड़कों को भी नौकरियों में स्थान मिलेगां हमारी सरकार कहती है कि नौकरियां आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिएं। गांवों और शहरों के स्कूलों में जमीन आसमान का अन्रत है। गांवों के लोगों की मदद करने के लिए 50 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित कर देने चाहिए जिन्हौंने मैट्रिक गांव से पास की हो जिस प्रकार से एच.सी.एस. और आई.ए.एस. में भी किय जाता है कि जितनी मांग हो उससे 3 गुधा से ज्यादा उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए न बुलाया जाए और जो सिलैक्शन हो वह स्ट्रिक्टली मैरिट के आधार पर होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार चौ. बंसी लाल ने और चौ. भजन लाल ने मैरिट को इग्नोर करके लोगों को नौकरी पर लगा दिया। (विघ्न)

Mr. Speaker: Ch. Sri Krishan Hooda, Ch. Balbir Singh, you please take your seat. I have called upon another person to speak.

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरीयह प्रार्थना है कि नौकरियां स्ट्रिक्टली मैरिट के आधार पा दी जानी चाहिए। इसके साथ जी साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार दिनों दिन शराब की खपत को बढ़ा रही हैं पिछले साल इससे 127 करोड़ रूपये की आमदनी हुई, उससे पिछले साल 109 करोड़ रूपये की और इस साल 176 करोड़ रूपये की आमदनी सरकार को हुई है। इस तरह की बात पहले कभी भी गावों में नहीं थी कि हर दुकान पर शराब मिले। (व्यवधान)

Mr. Speaker: No, no, you please take your seat. (Interruption). This is unfair on your part. I will not allow you now. Nothing more is to be recorded.

Sh. Balbir Singh Chaudhri: * * * *

चौ. श्री कृश्ण हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, जो मांगे सदन के सामने रखी गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं मांग नम्बर 2 पर बोलना चाहूंगा। इस महान सदन में मेहम के बारे में काफी चर्चा हुई है। मेरा गांव मेहम के साथ लगता हुआ गांव है और मेरा हल्का भी मेहम के साथ लगता हुआ है इसलिये मेहम में जो कुछ हुआ उसके बारे में असलियत को इस महान सदन के सामने रखना मेरा फर्ज बन जाता है। मेहम के अन्दर जेली बिग्रेड ने भददे नारे लगाए, हामरे झंडे बैनर और पोस्टर फाड़ डाले, हमारे चुनाव निशान जलाए गए और हमारे दफतरों में आग लगाई गई। 15 से 20 साल की आयु के लड़कों

को सुबह ही शराब पिला दी जाती थी और सारे दिन वे शराब के नशे में गन्दे नारे लगाते रहते थे, हमारे बैनर्ज और इश्तिहार फाड़ते रहते थे। हमारे नेता की तरफ से हमारे सभी वर्कर्ज को इस प्रकार की हिदायतें दी हुई थीं कि सिर्फ सुनना है और कोई गलत बात नहीं कहनी है। वे लोग इलैक्शन हार चुके थे। हमारे किसी भी नेता या वर्कर ने कोई गलत काम नहीं किया। यह सारे का सारा मामला जेली ब्रिगेड वालों ने बढ़ाया। 27 तारीख को आराम से इलैक्शन हो रहा था। गांवों की लुगाईयां चौ. देवी लाल के गीत गाते हुए वोट डालने के लिये जा रही थी। शान्तिपूर्वक ढंग से सारा काम हुआ और ठीक ठाक ढंग से सारी वोटिंग हुई और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। हरेक बूथ पर सभी उम्मीदवारों के पोलिस एजैटस ने जब बक्से बन्द हुए तो अपने–अपने हस्ताक्षर किए और अपनी अपनी मोहर भी लगाई। वहां पर कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। यह सारा काम जेली ब्रिगेड ने खराब किया। मुझे और भाई धीर पाल सिंह को भी जेली ब्रिगेड ने घेर लिया था। चांदी गांव के लोगों ने हमें बचाया। कुछ लोगों ने अखबार वालों को गलत रिपोर्ट दी है उसी कारण से कुछ लोग गुमराह हुए हैं। इसलिये मेरा यह फर्ज बन जाता है कि मैं सदन को अवगत कराऊं क्योंकि मैं उस हल्के के पास का रहने वाला हूं। स्पीकर साहब, अब हमारी सरकार ने इन्कवायरी के लिये जज बैठा दिया है। यह हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। जो असली मुजरिम हैं, वे सामने आ जायेंगे और जज इसका फैसला कर देगा।

अब मैं अपने हल्के के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मेरा किलोई हल्का हमेशा से ही अपोजीशन का हल्का रहा है। उसमें विकास के कार्य बहुत कम हुए हैं। मेरे हल्के में दो–तीन सड़कें हैं, जो बननी बहुत जरूरी हैं। एक तो गुमाना से किलोई है क्योंकि किलोई में परचेज सब सैन्टर भी है। दूसरी सड़क किलोई से रूखी है, उसे भी जोड़ा जाये। किलोई पी.एच.सी. की भी हालत खराब है। वहां पर कोई भी डाक्टर नहीं रहना चाहता है। इसलिए उसकी बिल्डिंग की रिपेयर करवायी जाये।

अब मैं डिमांड नम्बर 15 पर अर्ज करना चाहता हूं। यह डिमांड सिंचाई के बारे में है। आप जानते है कि हमारा प्रदेश ज्यादातर ऐग्रीकल्चरिस्टस का प्रदेश है। अच्छी कृशि के लिए अच्छे बीजों की जरूरत है। अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल भी होगी और अच्छा पानी होगा तो फसल भी अच्छी होगी। इसलिए सरकार को सिंचाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कच्चे खाल हैं, उन्हें भी पक्का कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पैदावार के लिए मिल सके। मेरे हल्के किलोई में रूखी माइनर है। इस माइनर की गलत लाईनिंग हुई है इसलिए उसका लैवल ठीक कराया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रोफैसर साहब, टाईम की कमी है इसलिए आप टाईम का ध्यान रखते हुए बोलें।

श्री परमानन्द (जींद): स्पीकर साहब, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं सभी मांगों पर नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने दो दिन की छुटिटयों में बजट की डिमांडज पढ़ी हैं। डिमांड नम्बर 8 जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस सरकार ने कितना महान काम किया है। इन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रान्त में 6745 गांव हैं जिनमें 6663 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। लेकिन जब मैंने इनका खुलासा किया तो खुद हरियाणा सरकार के इकोनोमिक सर्वे ओर 1988–89 के पेज 12 पर विकास की बहुत सुन्दर मिसाल मिली, जिस को सुनकर मेरे साथी बहुत खुश होंगे। उसमें लिखा हुआ है कि 1989–90 में 31.1.1990 तक कुछ एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया। इस बजट में जहां 270 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रावधान था वे सड़कें कहां पर बनाई हैं? क्या वे सड़कें आसमान पर बनाई हैं या समुद्र में बनाई हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सड़कें कहां पर बनी हैं? मैं यह देख कर हैरान रह गया कि कितने गलत आंकड़े दिए गए हैं। अगर इसी रफतार से विकास होता रहा तो बाकी बचे हुए गांवों में कितने समय में सड़कें बनाएंगे। अगर एक साल में एक गांव तक सड़क बनने लगे तो हजारों साल गुजर जाएंगे।

अब मैं डिमांड नम्बर 10 पर बोलना चाहता हूं। इस डिमांड में समस्या ग्रस्त गांवों केा पीने का पानी देने की बात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नए वर्श की पूर्व संध्या पर अपने भाशण में यह वायदा किया था कि इस साल 31 दिसम्बर

तक सभी गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। लेकिन बजट प्रावधान को देखकर यह सम्भव नहीं लगता। वर्श 1989–90 में 320 समस्याग्रस्त और पांच साधारण गांव हैं जिन्हें पानी देने के लिए 33.12 करोड़ रूपया खर्च हुआ। वहां 1990–91 में बजट में 34 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। तो मैं इस पैसे को देखकर हैरान हूं कि 1990–91 में इतने ही पैसा का प्रावधान करके किस प्रकार से 900 गांवों को पीने दे पाएंगे। गुप्ता जी, फिग्गर्ज को देखकर ऐसा लगता है कि यह पैसा काफी नहीं होगा। बजअ में अधिक पैसे का प्रावधान कर दें या फिर सच्चाई को व्यक्त कर दें कि सरकार इतने पैसे कितने गांवों को पीने का पानी दे सकेगी।

अब मैं डिमांड नम्बर 13 के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। पिछले बजट सैशन के दौरान गुप्ता जी ने फरीदाबाद कम्पलैक्स के अन्दर पिछड़े वर्ग और हरिजनों के लिए नौकरियों में जो बैकलाग रह गया था, यानी जो खाली सीटें थीं उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भरने का वायदा किया था लेकिन वे पद आज तक नहीं भरे गए हैं। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गरीब लोगों को रोजगार के साधन नहीं दिये जाते। डिमांड नम्बर 21 पंचायत और डिवैल्पमैंट के बारे में है। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर पंजाब विलेज कौमन लैंड ऐक्ट, 1961 लागू है और उसकी धारा 2 उप–धारा 'जी' (5) के अन्दर एक प्रोवीजन है जिसके अनुसार जिस गांव का 25 प्रतिशत

से ज्यादा रकबा शामलात का है, वहां के जो मुश्तरका मालिकान हैं, वे उस जमीन को बेच सकते हैं। इस मामले में उनको रोकने के लिये हमारे अधिकारीगण ने इस सरकार को बहुत पहले सचेत किया है। मुझे याद है और आज के अखबार में भी यह बात आयी है। हमने एक प्रोपोजल भेजी थी कि इस नियम के अन्दर संशोधन कर दिया जाये नहीं तो इस नियम की आड़ में मुश्तरका मालिकान सस्ते भाव पर दिल्ली के कौलोनाईजर्ज से मिलकर पंचायत की जमीन खुर्द–बुर्द कर रहे हैं। इस तरह की करोड़ों रूपये की जमीन प्राईवेट डीलर्ज को या कौलोनाईजर्ज को बेच दी गयी है। आज की इस खबर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको हमें सीरियसली लेना चाहिये। इस प्रान्त के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और राजनेता हैं, उसके बारे में उसके अन्दर कटाक्ष किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं यह कटाक्ष की सूई हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौ. औम प्रकाश चौटाला जी की ओर न मुड़े। इसलिये सरकार इस मामले को बड़ी गम्भीरता से ले और इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करे क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 15 जनवरी के सैशन से पहले भी सरकार ने अधिकारियों ने प्रार्थना की थी कि इस बारे में अमैंडमैंट इस सैशन में लायी जाये लेकिन पता नहीं किस वजह से सरकार उसको टालती रही है। 26 दिसम्बर, 1989 को जब इस विभाग का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिव्यू किय था उस समय भी हमारे अधिकारियों ने यह कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गुड़गांव की जमीन बड़े–बड़े कौलोनाईजर्ज के पास चली जायेगी।

इस स्कैंडल को राका जाये। लेकिन हैरानी होती है कि इस सैशन में भी जो अब खत्म होने जा रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई अमैंडमैंट का नोटिस हमें नहीं मिला है। इसलिये मेरा यह कहना है कि पंचायतों की शामलात जमीन को अगर बचाना है तो सरकार इस तरफ शीघ्र ध्यान दे।

अब मैं एक बात इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। यह डिमांड न. 16 है। इंडस्ट्रीज के बारे में सरकार ने कुछ आंकड़े दिये हैं। कई जगह पर ये आंकड़े रिपीट हुए हैं। 1988–89 के बजट में भी ''वायरल वैक्सीन'' प्लांट लगाने का वायदा किया गया था और यही वायदा 1989–90 के बजट में भी कर दिया गया है। एक ही वायदा सरकार दो बजटों में करके वाह–वाह लूअ रही है। इसी तरह से डबवाली की इंडस्ट्रियल ऐस्टेट का वायदा 1988–89 के बजट में भी है और 1989–90 के बजट में भी है। लेकिन आज तक वहां बनाने का काम भुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार से रैपीटीशन करके यह सरकार इस सदन को गुमराह करती रही है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के मैटर्ज को यह सदन सीरियसली ले और सरकार को अपनी नीति स्पश्ट भाशा में और स्पश्ट तौर पर कहने के लिये कहे। इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा में चौ. देवी लाल के नेतृत्व में बिजली की प्रोडक्शन में बहुत सुधार हुआ था। बिजली की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गयी थी लेकिन इसके साथ–साथ सरकार ने उद्योगों को इन्सैंटिब्ज देने की धोशणा भी की थी कि

हम लिबरल इन्सैटिव्ज देंगे। इस सब के बावजूद आज बड़े–बड़े उद्योग फरीदाबाद से उठकर ''नोयडा'' में जा रहे हैं। कहीं सोनीपत से उजड़ कर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। पानीपत से उजड़ कर यू.पी. में चले गये हैं या फिर राजस्थान में चले गये हैं। हमारा कृशि प्रधान प्रान्त है। कुशि पर ही सारे प्रदेश की तरक्की निर्भर करती है। लेकिन कृशि सैचुरेशन प्वायंट पर पहुंच गयी है। जब तक हमें एस.वाई.एल. का पानी नहीं आएगा तब तक बारानी भूमि को पानी नहीं मिलेगा और कृशि की अधिक उपज होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। उद्योगों के द्वारा विकास हो सकता है इसलिए ठीक प्रकार से इस तरफ ध्यान दिया जाए।

अब मैं पब्लिक हैल्थ की मांग के बारे में कहना चाहता हूं। शहरों में जल निकास तथा मल निकास के लिए साढ़े पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, शहरों में तीस प्रतिशत से भी ज्यादा लोग रहते हैं। साढ़े पांच करोड़ की इस थोड़ी सी राशि से जल और मल निकास का प्रबन्ध नहीं हो सकता। मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मद में ज्यादा फण्डज बढ़ाए जाएं जिससे कि सुचारू रूप से यह काम हो सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पुलिस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे साथी श्री आत्मा सिंह और श्री कृश्ण हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने बहुत अचीवमैटस की हैं और 27 तारीख को मेहम के अन्दर कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में अपने होम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता

हूं कि इतना कुशल प्रबन्ध पहली बार किया गया कि एक डी.एस. पी. खुद बैलट पेपर पर मोहर लगाता हुआ इक्लैशन कमीशन के अधिकारी ने पकड़ा। मैं बधाई देना चाहता हूं इनके प्रबन्ध को कि इन्होंने पहली बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा बूथों पर कब्जा करके बैलेट पेपर्ज पर मोहर लगवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब अपना बजट बढ़वाएं ताकि ये जिन लोगों के द्वारा बूथ कैपचरिंग करवाएंगे और जिस पुलिस वालों के द्वारा बैलेट पेपर्ज पर मोहर लगवाएंगे उनको इनाम भी देना पड़ेगा ताकि वे और अधिक बूथ कैपचरिंग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरी हल्के की दो तीन सड़कें हैं, जो मन्जूर हो चुकी हैं, मेरी प्रार्थना है कि उनको जल्दी बनवाया जाए। उन सड़कों की डिमाण्ड इसलिए भी जरूरी है कि ये सड़कें शुगर मिल से कनैक्टिड हैं। इन सड़कों के बनने से बीस–बीस किलोमीटर का फासला किसानों के लिए कम हो जाएगा और मार्किटिंग बोर्ड को फीस भी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रान्त में मुख्यमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर ने जिस सिस्टम को जन्म दिया है और जिस संस्कृति को जन्म दिया है, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं –

तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी,

जो शाखे नाजुक पर आशयाना बनेगा नापायदार होगा।

प्रो. सम्पत सिंह: आपने तो सुसाइड कर ली है।

श्री परमानन्द: जहां तक सुसाइड करने का सवाल है अगर मैं सुसाइड कर लेता तो यहां न होता। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस सिस्टम को बदल दिया जाये। यहां पर मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं –

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है

मेरी फितरत है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अगर ये सूरत नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में हरियाणा के किसी भी इलाके के अन्दर खड़े हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय मैं इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं।

चौ. सतबीर सिंह कदियान (नौलथा): अध्यक्ष महोदय, मैं बजअ अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं मांग नम्बर 2 जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हैं, पर कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हरियाणा सरकार के अधिकारी चाहे वे आई.ए.एस. है या एच.सी.एस. हैं जब वे किसी दूसरे प्रदेश में या विदेश में कोई विशेश ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कई बार देखा गया है कि जब वे ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो उनको उस विभाग में नहीं रखा

जाता। किसी दूसी विभाग में लगा दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो भी अधिकारी जब ट्रेनिंग लेकर आए तो उसको अधिक से अधिक समय के लिए उसी विभाग में रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारी पुलिस, जो गृह विभाग के अन्डर आती हे, ने बड़ी सफलता से सीाी उग्रवादियों को या तो पकड़ा है अथवा उनका सफाया कर दिया है। ऐसा करके हमारी पुलिस ने जनता के जान और माल की हिफाजल की है। हरियाणा में जितने भी कांड उग्रवाद क हुए हैं उन सबमें हमारी पुलिस को सफलता मिली है। पंजाब के साथ लगता हुआ जितना हमारा इलाका है वहां पर हमारी पुलिस बड़ी सतर्कता के साथ जनता की हिफाजत कर रही है। मैं इसके लिए अपने होम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मेहम का जिक्र किया गया। पता नहीं किस वजह से चौटाला साहब के खिलाफ जैली ब्रिगेड की गूंज मेहम के अन्दर थी। वहां पर बहुत ही भड़काने वाले भाशण दिए गए। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इलैक्शन में हुआ, उसका सबूत आज भी है। 27 तारीख को चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक हुआ। किसी भी भाई ने पांच बजे तक इलैक्शन कमीशन के सामने कोई शिकायत नहीं की लेकिन शाम को जब कुछ पत्रकारों ने यह देखा कि चौटाला साहब जीत गए हैं तो कुछ विद्रोही और कांग्रेस के दूसर भाई इक्ट्ठे हुए और उन्होंने प्लान बनायी कि किस तरह से इस इलैक्शन को रद्द कराया जाए। इस तरह की धिनौनी साजिश की गई जिसे

सारे हरियाणा की जनता और सारे देश की जनता भली भांति जानती है। इन कांग्रेसी भाईयों ने व दूसरी विरोधी पार्टियों ने मेहम के अन्दर 28 तारीख को जानबूझ कर इस तरह का वातावरण पैदा किया जिस कारण वे वहां पर लड़ाई झगड़े की घटनाएं हुई। यह कितनी शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी का तो इस चुनाव के अन्दर जनाजा निकलने वाला था, पर वे डिब्बे नहीं खुल पाए। मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि इनकी 500 से ऊपर वोटस उन डिब्बों में से नहीं निकल सकतीं थीं। दूसरी तरफ जो जनहित पार्टी है, जो जनता के सामने प्रजातन्त्र की दहाई देती है, उनका तो उम्मीदवार ही उस चुनाव क्षेत्र में नहीं था। उन भाईयों में से तो कोई वोट लैने वहां नहीं गया। मेहम में जो कुछ इन विरोधी भाईयों ने करवाया है, यह केवल चौ. देवी लाल जी को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है।

अब मैं बी.एंड आर. विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत के लिये व सड़कों को आपस में मिलाने के लिये अपने बजट में काफी पैसे का प्रोवीजन किया है परन्तु पानीपत के अन्दर एक फलाई ओवर ब्रिज का जिक्र किये बगैर मैं नहीं रह सकता। पानीपत के अन्दर एक फलाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिये क्योंकि जींद व गोहाना जाते वक्त असन्ध रोड पर लोगों को रास्ते में रेलवे फाटक क्रौस करना पड़ता है जिस कारण से लोगों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिस कारण से

लोगों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर वहां फलाई ओवर ब्रिज का निर्माण हो जाएगा तो लोगों को इससे काफी सहूलियत हो सकेगी और लोगों का आने जाने का समय भी बच सकेगा। इसी तरह से मूरथल से पानीपत के बीच जो फोर लेनिंग हैं, उसके अन्दर से आज भी जब किसान भाई अपने पशुओं को लेकर सड़क पार करते हैं तो उन्हें बड़ी ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता हे। अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा आयेगा जबकि बहुत ज्यादा रश हो जाएगा, बड़े–बड़े व्हीकल्ज होंगे, यातायात बढ़ेगा और वहां से लोगों को क्रौस करने की बड़ी भारी समस्या पैदा होगी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लोगों की इस आने वाली दिक्कत को दूर कियाजाए और सिवाह गांव के साथ, पूर्व की तरफ जो सड़क है तथा पिछवा गांव में जमीन है, उस सड़क के नीचे से पुल निकाला जाए ताकि वहां से छोटे मोटे गड्डे, झोटा बुग्गी, पशु मवेशी, बाल बच्चे वगैरह सड़क के नीचे से आसानी से गुजर सकें। यह पुल बनाया जाना बड़ा ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मुताल्लिक हरियाणा सरकार ने बड़े ही सराहनीय कदम उठाये है जिसकी वजह से सारे देश के अन्दर एक मिसाल सी पैदा हुई है। घुमन्तू बच्चों को एक एक रूपया रोज देकर शिक्षा जगत में सुधार करके सरकार ने बड़े ही अच्छे कार्य किये हैं। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ–साथ सरकार ने 9 जिलों के लिये नवोदय विद्यालयों

को मन्जूर किया है और शेश जिलों को चरणबद्ध रूप में इस स्कीम के अन्तर्गत लोने का प्रस्ताव है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के के सिवाह गांव में भी जो एक नवोदय विद्यालय खोलना था उसकी ओर सरकार अवश्य ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पानीपत और करनाल के अन्दर ''डाइट'' की कोई संस्था नहीं है। इसके लिये लोगों ने नौलथा गांव में जमीन दे रखी है और गांव वालों ने इसके लिये एक रैजोल्यूशन भी पास कर रखा है।

सभापति महोदय, इससे आगे मैं सरकार से एक और प्रार्थना करूंगा कि जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार काफी कुछ कर रही है, वहां सरकार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिये कि जिन इलाकों में बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देने का कोई इन्तजाम नहीं हैं, वहां पर कालेज एंव स्कूलों का प्रबन्ध किया जाए। पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां पर कोई गवर्नमैंट कालेज भी नहीं है। ईसराना के आस–पास गांवों में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। यह शहर से भी काफी दूर पड़ता है। इसलिये ईसराना में एक सरकारी कालेज की स्थापना की जाए ताकि लोगों को इससे लाभ हो सके और वे अपने बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा दिलवा सकें।

अध्यक्ष महोदय, नहर विभाग ने हरियाणा के अन्दर काफी भूमि को सिंचित किया है लेकिन मेरे हल्का नौलथा में एक ''बनारा'' माईनर का काम 1977 में चौ. देवी लाल जी के

शासनकाल में आरम्भ हुआ था लेकिन वहां आज तक टेल तक लोगों के पास पानी नहीं जाता क्योंकि उसकी अभी तक पक्का नहीं किया गया है। यह काम अभी तक अधूरा पड़ा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सइ काम में तेजी लाई जाए। इसी तरह से दूसरी वलाना माईनर है। वहां पर एक नया रजवाहा बनना है, जिसका पिछली सरकार ने नींव पत्थर भी रखा था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस काम के लिये भी बजट के अन्दर कोई न कोई प्रोवीजन रखा जाए।

इसके बाद मैं मांग नम्बर 16 जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखूंगा। उद्योग विभाग ने चौ. देवी लाल जी के नेतृत्व में व चौ. ओम प्रकाश चौटाला साहब ने नेतृत्व में काफी सराहनीय कार्य किये हैं जिससे कि बिजली की खपत में काफी वृद्धि होगी। अब इस सरकार ने जनरेटर लगाने के लिये सब–सिडी की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 15 लाख रूपया कर दिया है। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को सरकार ने इस तरह की काफी सहूंलियतें दी हैं लेकिन जो मजदूर, किसान और बेरोजगार भाई हैं और जो गरीब लोग अपना पोल्टरी फार्म वगैरह खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये ताकि वे लोग भी पनप सकें और अपना निजी धन्धा करके अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सकें। पोल्टरी और फिशरीज के काम काम उद्योग घोशित

करके बड़े उद्योगों में शामिल किया जाए यह मेरी सरकार से प्रार्थना है।

ऐग्रीकल्चर महकमें के तहत हरियाणा सरकार ने किसानों को खाद के लिए और बीजों के लिए काफी सहूलियत और सबसिडी दी। पानीपत में अनाज मण्डी में 1986 में व्यापारियों को प्लौट देने के लिए कहा गया था और उनसे पांच पांच सौ रूपए जमा करवाए गए थे लेकिन जुलाई, 1987 में वे प्लौट रद् कर दिए गए और उनके पैसे वापिस कर दिए गए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी व्यापारियों को मंडी में प्लौट दें ताकि मंडी सही ढंग से आबाद हो सके।

हरियाणा के परिवहन विभाग ने सारे हिन्दुस्ताान में एक मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूं कि ईसराना के अन्दर एक नया बस अड्डा बना कर वहां के लोगों की तकलीफ को दूर किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बार–बार प्रयास करने के बाद और बजट पर अवसर न देने के बाद मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया। आज सर्व प्रथम मैं यह भी अपना नैतिक कर्त्तव्य समझता हुआ बजट सत्र के प्रारम्भ में कहना चाहूंगा कि जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ है देश में, उसका

श्रेय भारत की जनता को जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जो विश्वास रखने वाले थे, उनकी आज केन्द्र में सरकार स्थापित हुई है। 1947 में देश आजाद हुआ था। सचमुच, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सुभाश चन्द्र बोस जैसे नेताओं के साये में चला हुआ वह आन्दोलन का रास्ता राम राज्य की तलाश में था। चालीस साल के कांग्रेस के कुशासन ने इस देश की परम्पराओं व व्यवस्था को चकनाचूर करके रखा दिया था। देश के लोगों के दिमाग से इस व्यवस्था से विश्वास उठ गया था। आज उस विश्वास की देश में पुनः स्थापना हुई है। इसके लिए इस देश की महान जनता बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, इसका श्रेय केन्द्र में हमारा नेतृत्व करने वालों को भी जाता है। वे हैं श्री वी.पी. सिंह और उनके सहयोगी आदरणीय चौ. देवी लाल जी और दूसरी जिन राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से यह सरकार चल रही है, निश्चित रूप से वे लोग भी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को बड़ी साधारण सी बुद्धि का नागरिक समझते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि चालीस साल की प्रतीक्षा के बाद जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए व्यवस्था ही हर कड़ी परस्पर जुड़ी हुई है। चाहे उसमें हमारी सरकार आती है, चाहे राजनीतिक पार्टी आती हो, चाहे हमारे प्रैस के लोग आते हों और चाहे हमारे मंत्री और विधायक आते हो। मैं समझता हूं कि जनता तो हमेशा हर परीक्षा में पूरी उतरी है। उसने 1977 में हमें समय दिया था और अब 12 वर्श के बाद फिर समय दिया है। देहात में कहावत है कि 12 वर्श के बाद तो धूरे की भी वापिस

होती है। उसके बाद में पुनः हमें मौका मिला है। हमें निश्चित रूप से उसके विश्वास को बरकरार रखना होगा। कांग्रेस राज में एक पांचजन्य नामक पत्र निकलता था। उस वक्त हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे कि क्या हमारी यही व्यवस्था है। मुझे दो पंक्तियां याद हैं जो मैं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं –

केशव क्यों सुप्त सुदर्शन है, क्यों मौन तुम्हारा पांचजन्य।

दुःशासन बढ़ता ही जाता, हो रहे कृत्य सब तो जघन्य।

पिछले चालीस साल में कांग्रेस के शासन के विरूद्ध एक तरीके से प्रैस का यह इम्प्रैशन था। यह जनता की आवाज थी कि किस किस तरीके से जघन्य कृत बढ़ते जा रहे है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 1990 के अन्दर भी क्या ऐसा हो रहा है। यह हमारे दोस्त रूपी लोगों के द्वारा हो गया है जो समझते हैं कि शायद यह जनता सर्वोपरि नहीं है और हम ही केवल इस बात के भाग्य विधाता हैं। मैंने एक साधारण सी कविता पढ़ी है उसकी पंक्तियां कहीं न कहीं इससे रिलेट करती है। अध्यक्ष महोदय, उन पंक्तियों का जो साराश है मैं कविता द्वारा इस माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा।

हर मर्यादा टूट रही है,

छोटा मुहं है बात बड़ी है।

मक्कारों की मौज लगी है,

हर सज्जत की खाट खड़ी है।

कहीं गबन है, कहीं घोटाला,

कहीं कमीशन का चक्कर है।

मियां छोड़ के साथ आज कल,

पुलिस हमारी घी खिचड़ी है।

सच्च कहता हूं आज गर्द के

जगह जगह अम्बार लगे हैं।

इस चुनाव में कांग्रेस की,

बड़े प्यार से धूल झड़ी है।

सोच अलग है, बात अलग है,

नेताओं का काम अलग है।

सिंहासन के नीचे देखो,

लोक राम की लाश पड़ी है

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से अपने आपको पाप का भागी नहीं बनाना चाहता। इस स्तम्भ पर भी लिखा हुआ है कि मौन रह कर पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। अध्यक्ष

महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके द्वारा सदन के नेता से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज हमारी पार्टी की और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि हम यहां पर शासन कर रहे हैं, हमें मेहम में जो सिंहात्मक घटनाएं हुई हैं जिनकी निन्दा करनी चाहिए और निन्दा का एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। वह जांच का विशय है लेकिन फिर भी सभी सदस्य मेहम के चुनाव के बारे में बोले हैं। आपकी उस बारे में रूलिंग भीा है कि वह मामला सब जुडिस है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि चौ. देवी लाल जी ने नेतृत्व वाली हमारी पूर्ववर्ती राज्य सरकार और श्री वी.पी. सिंह की केन्द्रीय सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उन पर चल कर हमारी आज की सरकार ने जनहित के बहुत कार्य किए हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वे लोग देश के लोगों की उन आकांक्षााओं को पूरा करने के लिये प्रयासरत हैं जो आकाक्षाएं हमने देश की आजादी से पहले संजोई थी। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें उन बातों की पुनरावर्ती नहीं करनी चाहिये क्योंकि हम विकास के कार्यो में बहुत आगे बढ़े हैं।

Mr. Speaker: Rawat Ji, your four minutes are left. You please wind up.

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, अब मैं शेश समय में डिमांडज के बारे में ही विचार प्रकट करूंगा क्योंकि मुझे बजट पर बोलने के लिये समय नहीं मिला था।

श्री अध्यक्षः रावत साहब, आज बोलने के लिए टाईम ही उन माननीय सदस्यों को मिल रहा है जो बजट पर नहीं बोले हैं। जो माननीय सदस्य बजट पर बोल चुके हैं, वे नहीं बोलेंगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। विकास की सारी बातों पर मैं मांगों का तीन बातों में वर्गीकरण करना चाहूंगा। मैं मांग संख्या 3, 8, 13, 14, 15, 16, और 23 पर एक–एक करके अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इन मांगों पर बोलते हुए मैं अपने क्षेत्र के विशय में आदरणीय उप मुख्य मंत्री और संबंधित मन्त्री जी को जानकारी देना चाहूंगा। जहां तक मांग संख्या 3 का संबंध है, हमारी हरियाणा पुलिस बधाई की पात्र रही है। हमारा हरियाणा बहुत सैंसटिव ईलाका है। पंजाब प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। देश की राजधानी से सटता हुआ इलाका है। हमारे प्रदेश में भी बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। हम अपनी पुलिस बल के आधार पर, अपनी पुलिस के मनोबल के आधार पर उनकी जांच पड़ताल करके किसी परिणाम तक पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। मैं आपने द्वारा उनके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा और मैं नहीं समझता कि किसी मननीय सदस्य के नोटिस में यह बात नहीं आई होगी कि करनाल जिले में इन्द्री के समीप इस्लाम नगर कस्बे में महिलाओं को नंगा घूमा करके उनके साथ बलात्कार किया गया। यह बात समाचार पत्रों में भी छपी थी। इसके अलावा नारायणगढ़ में दो महिला पुलिस कांस्टेबल्ज के साथ अभद्र

व्यवहार की नई घटना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाश में आई थी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पहले भी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे ंऔर दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं हो चुकीं हैं। पुलिस विभाग की सबसे पहले यह जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी यह जिम्मेदारी बननती है कि महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार होने से रोके जाएं वरना सारी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग कर रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे उस समय जब हम लोग कहीं पर जाते थे तो हरियाणा की पुलिस को बड़े आदर और सम्मान के साथ देखा जाता था। आज भी मैं समझता हूं कि हरियाणा की पुलिस में वह चीज मिटी नहीं है। आज भी हरियाणा की पुलिस अपने मनोबल पर कायम है। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि कि हमें पुलिस व्यवस्था को कामयाब रखना होगा और उसमें जो योग्यतम आदमी हैं, उनके साथा यथायोग्य बर्ताव करके उनको परमोशन और सारी सुविधाएं दे कर, उनके अन्दर जो अच्छाई के बीच छिपे हुए हैं, उनको डिवैल्प करना होगा तभी हम सारी कानून व्यवस्था को सफल कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिले फरीदाबाद और हथीन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली बातों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। प्रारम्भ से ही मैं और मेरे साथी तीन बातों का सरकार से आग्रह करते आ रहे हैं और आज भी मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर एस.वाई.एल. पूरी हो जाए तो भी मैं समझता हूं कि फरीदाबाद और मेवाल के लोगों को कोई भला नहीं होगा। मेरी समझ में एस.वाई.एल. के पूरा होने से

भी उन क्षेत्र के लोगों को कोई भला नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हरियाणा के इन्ट्रैस्ट में यह नहर पूरी हो लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमें आज जो दुगना व तिगुना आबियाना देना पड़ रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिलने वलाा है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय चौ. देवी लाल जी घोशणा करके आए थे और आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी भी 40 किलोमीटर पैदल चल करके नहर को देखकर आज थे और इन्होंने भी उस समय यह कहा था कि मेवात कैनाल निकाली जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वहां पर मेवात कैनाल निकाल दी जाए और उसके साथ साथ आगरा कैनाल की मैनेजमैंट अपने हाथ में ले ली जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को दुगुना और तीनगुणा आबियाना देने से छुटकारा मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं समझते कि हमें किसी विकास में से कोई हिस्सा मिल रहा है। मैं कहता हूं कि आज भी अगर हरियाणा प्रदेश के किसी क्षेत्र का किसान दोगुणा और तीन गुना आबियाना के रेट देता है तो वह आज भी हरियाणा में मिली सुविधाओं के वंचित है। हमारे तत्कालीन सिंचाई तथा बिजली मंत्री और आज के मंत्री त्यागी साहब ने हमारे उस क्षेत्र के लिये एक वायदा किया था कि हम उस क्षेत्र के आबियाना के रेट के अन्तर को दूर करेंगे।

Mr. Speaker: Rawat Ji, please take your seat now.

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहानी है इसलिये आप मुझे थोड़ा टाईप और दे दें।

Mr. Speaker: No question of more time now. Please take your seat.

श्री भगवान सहाय रावत: अगर आप बैठने के लिये ही कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

18.00 बजे

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए मैंने बड़े विस्तार के साथ सभी बातें सदन के सामने प्रस्तुत की थीं। उन सब बातों को आज दोहराते की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आम बहस में उठायें गए। यद्यपि बजट के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, उनके बारे में भी मैंने सकरार का जो पक्ष था यानी सरकार का जो वर्शन था वह बहुत अच्छी प्रकार से सदन के सामने प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज भी जब इन डिमांडज के ऊपर मेरे साथी सदस्य बोल रहे थे तो इन डिमांडज की चर्चा कम से कम हुई है और बातें ज्यादा कही गई हैं। एक दो साथियों ने जो थोड़ा बहुत जिक्र किया है, मेरे विचार में आज उन बातों को करने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, हर आदमी के अपने उद्‌गार हैं चाहे किसी बात की चर्चा हो ये बार–बार अपनी बात करते हैं। यह उनकी मर्जी है। इसके बावजूद

भी अगर किसी साथी ने कुछ कहा है, हमारी आलोचना की है, हम आलोचना से घबराते नहीं, उसको सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं बल्कि हम यह महसूस करते हैं कि अगर कहीं गलती हुई है या कमी रही है तो उस कमी को दूर करने का पूरा–पूरा प्रयास किया जाए। आपके सामने व सदन के सामने सन् 1990–91 का जो बजट मैंने प्रस्तुत किया था उसी से सम्बन्धित ये 25 डिमांडज प्रस्तुत की हैं। मैं समझता हूं कि एक–एक मांग का विवरण देना कोई जरूरी नहीं होगा। सभी विधायक साथियों ने बजट देखा होगा और इन मांगों को भी देखा होगा। मैं एक–एक मांग का जिक्र करूं तो उससे सदन का समय नश्ट होगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा लेकिन इन 25 मांगों में जो टोटल रकम की स्वीकृति, मैं हाउस से, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से लेना चाहता हूं वह है 2190 करोड़ 58 लाख और 75 हजार रूपये की। इन 25 मांगों में ही सभी विभाग और उनके सभी खर्चे चाहे वह प्रशासनिक हैं या दूसरे हैं, शामिल हैं। इसमें योजनागत खर्चा और नान योजनागत खर्च दोनों शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन डिमांडज पर मेरे साथी आज बोले हैं, मैं समझता हूं कि कोई विशेश बात ऐसी नहीं कही गई, जिसके बारे में मैं कोई जवाब दूं। यह ठीक है कि कुछ साथियों ने शहरों के लिए जल सप्लाई, बिजली की उचित व्यवस्था और मल निकासी की बातें की हैं और कहा हे कि इस काम के लिए साढ़े पांच करोड़ रूपये बहुत कम हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि काम को देखते हुए या साढ़े पांच करोड़ रूपये की राशि कम है लेकिन अपनी वित्तीय

स्थिति को देखते हुए प्रत्येक विभाग के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है। हम भी यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान किया जाए और जल्दी से जल्दी हम अपनी जनता को कठिनाइयों को दूर कर सकें। अध्यक्ष जी जितनी चादर होती है उतना ही पैर पसारा जाता है। हम इस बात की आशा करते हैं कि जिस प्रकार आज हरियाणा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है भविश्य में भी इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह कोशिश है कि चाहे कृशि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो या दूसरे विकास के कार्य हों हमारी यह गति ऐसी ही बनी रहे या इससे भी तेज हो और हमें आशा है कि ऐसा होगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि समुचित विकास के लिये बिजली और पारनी दो साधन उपलब्ध होने निहायत जरूरी हैं। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, आज इसका बड़ा भारी महत्व हैं हरेक क्षेत्र में बिजली की जितनी आवश्यकता आज है, इतनी किसी और चीज की नहीं है। उसके बाद पानी का नम्बर आता है। बिजली के बिना मैकेनाइज्ड फार्मिन्ग नहीं हो सकती। हल चलाने वाले किसान को बिजली बिजली की आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज गांव–गांव में खेत–खेत में टयूबवैल्ज लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा किसान इतना मेहनती और समझदार है कि वह पानी के एक–एक कतरे का पूरी तरह से प्रयोग करता है। आज उसको जितना भी पानी मिल सकता है चाहे वह नहर के जरिये से प्राप्त हो या अण्डर ग्राउन्ड पानी मिले, वह उसका उपयोग करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का ताल्लुक है, मुझे

यह कहते हुए अफसोस होता है कि इस ओर हमारी केन्द्र की पिछली सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 1976 में जब मैं हरियाणा का मुख्य मंत्री था और हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल जी थे, हमने नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट का ऐग्रीमैन्ट किया था। सारी टर्म्ज सैटल की जा चुकी थी, ऐग्रीमैन्ट तैयार हो गया था, मेरे और ठाकुर राम लाल जी के हस्ताक्षर भी हो गये थे। इस प्रोजैक्ट से एक हजार मैगा वाआ बिजली का उत्पादन होना था, 400 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान था और यह प्रोजैक्ट सन् 1984 तक कम्पलीट होना था। अध्यक्ष महोदय, अगर उस वक्त यह प्रोजैक्ट शुरू हो जाता और 1984 तक बनकर कम्पलीट हो जाता तो अब तक कितनी बिजली हरियाणा को और अधिक प्राप्त हो चुकी होती। हरियाणा के जो अधिकारी, इन्जीनियर्ज और कर्मचारी हैं वे बहुत ही निश्ठावान हैं। हमने जब भी कोई नया टारगेट सैट किया, चाहे वह नहरों के निर्माण का हो या बिजली के लिए समयबद्ध कार्य हो, तो हमारे इन्जीनियर्ज अधिकारी और कर्मचारियों ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही काम को पूरा कर दिखाया। अध्यक्ष महोदय, यदि नाथपा झाखड़ी से 1984 में ही हमें बिजली मिल गई होती तो आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि हरियाणा प्रदेश को कितने हजार करोड़ रूपये का फायदा होता। तब से यह नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद यमुनानगर के स्थान पर सुपर थर्मल प्लांट बनाने के

लिये सैंट्रल एजैन्सी को काम दिया, जमीन ऐक्वायर की लेकिन सैंट्रल गवर्नमैंट से उसकी परमिशन मिलने में सालों लग गये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एस.वाई.एल. का मामला है जिसका यहां पर भी बार–बार जिक्र आया हैं इस कार्य में भी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने रूचि नहीं ली। अगर इस नहर से हमें पानी मिल गया होता तो इससे हरियाणा का कितना विकास हो गया होता। हम फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के अन्दर गैस–बेस्ड थर्मल प्लांट लगाना चाहते हैं। हम पानीपत में भी इसी साल एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये सारी स्कीमें शुरू हो जायेंगी तो पानी और बिजली का प्रबन्ध हो जायेगा। पानी और बिजली होगी तो अनाज ज्यादा होगा और स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, स्टेट की माली हालत भी अच्छी होगी। स्टेट की माली हालत अच्छी होगी तो विकास के कार्य भी तेजी से बढ़ेगें। आज भी हरियाणा प्रदेश पर–कैपिटा इन्कम के हिसाब से नम्बर दो पर है। हरियाणा और पंजाब के अन्दर पर–कैपिटा इन्कम में केवल सौ रूपये का अन्तर है। हमारी कोशिश है कि जल्दी ही इस अन्तर को पूरा कर पायें। हमारी कई साथियों ने कहा कि दो अढ़ाई साल के अर्से में विकास की गति धीमी पड़ी है। यह बात बिल्कुल निराधार और गलत है। आंकड़े और फैक्टस मेरे पास हैं। पिछले दिनों बहस का जवाब देते हुए मैंने बताया था कि किस–किस क्षेत्र में हम पहले से आगे बढ़े हैं। आज प्रोफैसर परमानन्द और एक दो अन्य साथियों ने कहा कि उद्योग हमारी स्टेट से प्लायन कर रहे हैं। मैं अपने माननीय साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वे यह बतायें कि कौन–कौन से

बड़े या लघु उद्योग ''नोयडा'' मे ंया कहीं और चले गये हैं। वे उनकी मुझे लिस्ट तो दें। हां ऐसा तो हुआ है कि जैसे हमारे प्रदेश में ऐस्कोर्टस या आइसर के प्रोजैक्ट हैं, वे ऐसे ही प्रोजैक्ट दूसरे प्रदेश में लगाना चाहते हों तो वे वहां उन्होंने लगा दिए हो। आप जानते हैं कि जब उद्योगपति आगे बढ़ना चाहता है तो वह एक प्रदेश पर डिपैन्ड नहीं करता। वह दूसरे प्रदेशों में अपना फैलाव करना चाहता है। जैसे बिड़ला है, उसका हर प्रदेश में उद्योग है। कोई ऐसा प्रदेश भारतवर्श में नहीं है जहां उसके उद्योग न हों। मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगा कि एक भी उद्योग किसी दूसरे प्रदेश में नहीं गया है। कम से कम मेरे नोटिस में नहीं है, अगर उनके नोटिस में है तो वे बता दें। हमारे यहां उद्योगों की संख्या बढ़ी है। मैंने अभी पिछले दिनों आंकड़े दिए। जहां तक लार्ज और मीडियम स्केल के उद्योगों का सवाल है उस बारे में मैंने बताया था कि सन् 1986–87 में 366 उद्योग थे और सन् 1988–89 में 393 हो गये। उनकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। हमारे यहां कुछ और उद्योग भी आ रहे हैं, बड़े प्रैस्टीजिएस उद्योग हमारी स्टेट में आज रहे हैं। अभी चार दिन पहले एक प्रोजैक्ट ऐप्रूवल कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसका में चेयरमैन हूं। उसमें यह बात आयी थी कि एच.एस.आई.डी.सी. एसिस्टिड सैक्टर में बड़े अच्छे–अच्छे प्रोजैक्ट लगाने जा रही हैं। हिन्दुस्तान में ऐसे प्रोजैक्टों की कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। मैं उन प्रोजैक्टस का नाम तो नहीं बतला सकता क्योंकि मैं टैक्नीकल आदमी नहीं हूं। लेकिन ऐसे उद्योग हिन्दोस्तान में कहीं नहीं हैं। शायद एक प्रोजैक्ट

बावल में या किसी पिछड़े क्षेत्र में लगने जा रहा है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है सन् 1986–87 में 222300 थे लेकिन सन् 1988–89 में 259014 हो गए। इस प्रकार हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं गये। मैं आपके जरिए इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि विकास के कार्यों में किसी से पीछे नहीं है। वैसे राजनैतिक स्वार्थ पूरा करने के लिये चढ़े तबे पर कोई भी आदमी दो रोटियां सेंक लेता है लेकिन जहां तक प्रदेश के विकास का सवाल है किसी प्रकार की उपेक्षा या लापरवाही नहीं बरती गई है। इस बात की ओर सरकार का पूरा ध्यान है। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने घोशणा की और टारगेट फिक्स किया कि हरियाणा के अन्दर चाहे कोई प्रौब्लम विलेज है या नौन–प्रोब्लम विलेज है, उन्हें 31.12.1990 तक पीने का स्वच्छ जल पहुंचायेंगे। जो वायदा किया है, उसे पूरा किया जायेगा। अभी परमानन्द जी ने कहा कि पैसा नहीं है तो इन गांवों में पानी कैसे पहुंचायेंगें? अगर इस रूपये में जो हमने बजट में रखा है, काम नहीं चलेगा और पानी नहीं पहुंचेगा तो और रूपये का प्रबन्ध करेंगे लेकिन लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथी बोले। श्री टेक चन्द जी नैन हमारे बहुत सम्मानित विधायक हैं। ये मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने कहा कि हौस्पिटल्ज की संख्या तो बढ़ी है लेकिन औशधियां बहुत कम हैं। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि दवाइयों पर जितना रूपया खर्च किया जा रहा है, वह बहुत कम

है। बहुत ज्यादा पैसा चाहिये। लेकिन इवाईयां आजकल इतनी कौस्टली हो गयी हैं, इतनी कीमती हो गयी हैं कि सरकार प्रत्येक रोगी के लिये उन्हें मुफ्त नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी जहां हमारा 1989–90 के अन्दर 41 करोड़ रूपये का औशधियों के लिये प्रोवीजन था, वहां हमने इस वर्श दवाइयों के लिये 49 करोड़ रूपया रखा है। यानी 8 करोड़ रूपया हमने बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह दहिया पढ़े–लिखे हैं, शिक्षा शास्त्री हैं और ऐजुकेशन बोर्ड के अभी अभी अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। ग्रामीण विकास के बारे में बातें की कि यह लक्ष्य पूरा होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से सदन में सामने यह बात रखना चाहता हूं कि यही वह सरकार है जिसने केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात सबसे पहले यह निश्चय किया है कि अपनी योजना का 50 फीसदी देहाती क्षेत्र पर खर्च किया जायेगा। अब तक, अध्यक्ष महोदय, क्या होता रहा है। आपको पता है कि योजना का कुल 17 परसैन्ट कांग्रेस के 40 साल के राज में गांवों पर खर्च होता रहा है। गांवों में जहां पर जनता 80 फीसदी बसती है, वहां पर योजना का केवल 17 फीसदी खर्च होता रहा है और 20 फीसदी जनता पर 83 फीसदी खर्च होता रहा है। यह पहली ऐसी सरकार आयी है जिसने यह आदेश दिया है कि 50 फीसदी देहाती क्षेत्र पर खर्च किया जाये। मुख्यमंत्री जी को यह याद होगा जब हम अगले साल की योजना के लिये डिस्कशन करने के लिये योजना आयोग के पास गये तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री हेगड़े जी ने छूटते ही हमसे पहला प्रश्न यह यिका कि योजना में

क्या देहाती क्षेत्र के लिए 50 फीसदी का प्रोवीजन है। हमने कहा हमारा तो 70 फीसदी है। हमने तो जब चौ. देवी लाल जी ने इस प्रशासन की बागडोर संभाली थी तभी से देहाती क्षेत्र की तरफ ज्यादा खर्च करना प्रारम्भ कर दिया था। अब इस साल तो 70 फभ्सदी तक देहात पर खर्च किया जायेगा। ग्रामीण जनता के ऊपर यह पैसा अवश्य खर्च किया जायेगा। सड़कों के बारे में भी यहां पर बात आयी अभी हमारे प्रोफैसर परमानन्द जी ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ एक गांव को सड़क से जोड़ा गया है। यह शायद जीरो पढ़ना भूल गये। मैं आप की मार्फत इनको यह बताना चाहता हूं कि यह गौर से देखें।

श्री परमानन्द: आप पेज 12 पर देख लें। उसमें ओ.एन. ई. वन लिखा हुआ है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: 1989–90 में 225 किलोमीटर की लम्बाई की नयी सड़कें फरवरी, 1990 तक बनी थीं और 10 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। एक गांव अम्बाला का, तीन करनाल में, 4 फरीदाबाद में और 2 गुड़गांवा जिले के सड़कों से जोड़े गये हैं।

श्री परमानन्द: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर सर, मैंने बाकायदा कोट किया है। बाकयदा यह गवर्नमैंट डौकुमैन्ट है। यह डौकुमैन्ट मेरा अपना नहीं है। इसके पेज 12 पर रोडज का हैंडिंग है, इसमें यह लिखा है:– Only one village was

connected with pucca road. यहां पर ओनली वन का शब्द लिखा है। टैन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये यह क्लैरीफाई होना चाहिये whether this document is wrong or the statement of the Deputy Chief Minister is wrong?

बनारसी दास गुप्ता: ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जो फिगर्ज हैं मैं उनको वैरिफाई कराऊंगा कि किस प्रकार वहां ऐसा प्रिन्ट हुआ है। अगर गल्ती से प्रिन्ट हुआ है तो उसका सुधार करेंगे लेकिन जो फिगर्ज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही फिगर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर लगभग सभी गांव पक्की सड़क के साथ जोड़ दिए गए हैं। प्रोफैसर परमानन्द ने कहा कि पता नहीं कि ये सड़कें कहां बनी हैं, आसमान में बनी हैं या कहीं ओर बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह संभव हो सकता है कि कुछ गांव दो तरफ से सड़क से जोड़े गए हों। जहां बहुत आवश्यक था, वहां दो तरफ से जोड़े गए हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी दृश्टि से जहां बहुत आवश्यक था वे गांव दो तरफ से जोड़ दिए गए। इस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है। लेकिन इसका पूरा ब्यौरा मालूम करके मैं प्रोफैसर परमानन्द को चिट्ठी लिखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कारमरेड हरपाल सिंह ने पंजबा के कर्मचारियों के बराबर हरियाणा के कर्मचारियों को एच.आर.ए. देने की बात कही और कुछ पुलिस के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे जूते तथा वर्दी प्रदान करने के बारे में जिक्र किया और कहा कि उनके

अन्दर असन्तोश की भावना ने जन्म ले लिया है। इस तरह की बातें उन्होंने कहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के सिपाही तथा दूसरे अधिकारियों को वही वेतनमान दिए जाते हैं जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दिए जाते हैं और ये सारे देश में सभी से ज्यादा हैं। इसलिये यह कहना बिल्कुल गल्त है कि यहां पर पुलिस जवानों को कम तनखाह दी जाती है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम कुछ और सुविधाएं देने जा रहे हैं। अब तक परेड के लिए ही जूते दिए जाते हैं अब हम आम यूज के लिये जूते देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले जो जरसी दी जाती थी, वह बहुत रद्दी ऊन की दी जाती थी। अब हम बढ़िया ऊन की जरसियां बनवा रहे हैं। हमें अपने पुलिस के सिपाहियों पर गर्व है। वे डियूटी के पक्के हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने मेहम के मामलें को लेकर पुलिस की नुक्ताचीनी की लेकिन उन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि किस प्रकार हमारी पुलिस ने आतंकवाद का मुकाबला करके बहादुरी का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जब भी पंजाब के किसी आतंकवादी ने हरियाणा में कोई शरारत करने की हिमाकत की तो या तो उसको पकड़ लिया गया अथवा उसको सफायश कर दिया। हरियाणा के अन्दर अगर कोई आतंकवादी घुस आया तो वह यहां से बच कर नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस ने दरियापुर बस हत्याकांड के मुजरिमों को पंजाब में जाकर बड़ी बहादुरी के साथ गिरफतार किया।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेहम का सम्बन्ध है, मै इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस डी.एस.पी. की बार–बार चर्चा की गई है कि वह अपने हाथ से मोहर लगा रहा था, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब सैन्ट्रल औबजरवर ने चीफ मिनिस्टर के सामने यह बात रखी कि मैंने खुद अपनी आंख से डी.एस.पी. को मुहर लगाते हुए देखा था तो उन्होंने एक मिनट के अन्दर उसको सस्पैन्ड कर दिया और उसके खिलाफ इंक्वायरी इंस्टिच्यूट कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मिनट की भी देर नहीं लगाई। सैन्ट्रल औबजरवर सब जगह घूमा है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी और अधिकारी ने गल्ती की होगी तो उसको भी सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस काबिले तारीफ है। कामरेड हरपाल सिंह ने अपने यहां कालेज की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं कि टोहाना में तो पहले ही कालेज है।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, औन ए प्वायंट औफ आर्डर। I have got these documents of this government with me partaining to last three years. These are budget speeches of worthy B.D. Gupta. On Page 12 of this year's speech mention of industries has been repected. Whether the Deputy Chief Minister will clear the position? अध्यक्ष महोदय, मैं इसको हिन्दी में भी कह दता हूं। वर्श 1988–89, 1989–90 तथा 1990–91 के बजट स्पीचों में जो प्रोजैक्ट दिए हैं, जो इंडस्ट्री लगाने का वायदा

किया है वही बारबार रिपीट हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह रैपिटीशन गल्ती से हुई है या उस साल में ये लगी नहीं हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वे प्रोजैक्टस लगने शुरू हो गये होंगे, काम हो रहा होगा। एक एक प्रोजैक्ट 10–10 सालों में जाकर पूरा होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं औफ हैन्ड कोई जवाब नहीं दे सकता। वे लिखकर दें, मैं पूरी तरह से क्लीयर करके उनको उत्तर दूंगा जिससे उनकी पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी। पूरी तरह से फैक्टस के साथ मैं उनको जवाब दूंगा।

श्री देवीदास जी ने अपने इलाके की बात की और म्यूनिसिपल कमेटियों के साधनों की बात कही। इसमें कोई शक नहीं है कि नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। श्री देवीदास जी ने काह कि म्यूनिसिपल कमेटियों को और साधन जुटाने जाने चाहिये जिससे उनकी हालत अच्छी हो, उनमें सुधार आए। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इसके लिये एक कमीशन बनाया हुआ है जिसके पूर्व चेयरमैन श्री राम लाल वधवा थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थीं दूसरे चेयरमैन जो हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी है। हम चाहते हैं कि ऐसे पूरे प्रयास किये जाएं ताकि म्यूनिसिपल कमेटियों का पूरे साधन उपलब्ध हों और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

श्री दुर्गा दत्त अत्री जी ने बोलते हुए कहा कि अलेवा के अन्दर एक 10+2 विद्यालय की स्थापना की जाए। साथ में माजरी–पेगा और हसनपुर माइनर्ज की भी मांग की गई। इन सब बातों पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा।

श्री मनीराम जी ने अपने हल्के की समस्या यहां हाउस में रखी है। उन्होंने कहा कि कपास के उत्पादन को देखते हुए डबवाली में एक स्पिनिंग मिल लगाई जाए और साथ में कहा कि मसीता माईनर को भी पक्का किया जाए। उनको सुझावों को नोट कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, श्री आत्मा सिंह गिल जी ने इस हाउस में पहला भाशण दिया है और बड़े अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों को हंसाया है और जो इस हाउस का गम्भीर वातावरण बना हुआ था, उसको हंसी और खुशी में बदल दिया है। उसके लिये मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चौ. बलबीर सिंह जी ने बोलते हुए बजट की काफी सराहना की है। सरकार के सभी कामों की उन्होंने खूब सराहना की है और कांग्रेस शासन के साथ इसका मुकाबला भी किया। हमारी कमियों को भी उन्होंने यहां पर बताया है। जो सुझाव उन्होंने दिये, हम उन पर पूरी तरह से विचार करेंगे।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। मैंने एक स्पैसिफिक बात कही है कि पिछले साल में ऐक्साईज से सरकार की आमदनी में 16 करोड़, पिछले से पिछले साल 9 करोड़ रूपये और इस साल लगभग 49 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। मतलब यह है कि इस साल सरकार की इस हैड से आमदनी 127 से एकदम 176 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरी तरफ 30 अक्तूबर को चौधरी साहब ने एक स्टेटमैंट दी थी कि हम गांधीवादी नीतियां लागू करेंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, यह कोई प्वायंट औफ आर्डर नहीं है। You wanted to waste one minute of the House and that you have done.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और अधिक समय न लेते हुए आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि अगले वर्श के बजट की जो मांगे, जो अमांउट हमने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है, उसको पास किया जाए और हमें इसकी इजाजत दी जाए कि इस पैसे को खर्च कर सकें और प्रान्त को आगे विकास की ओर ले जा सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब मैं वेरियस डिमांडज को वोटिंग के लिये पेश करता हूं।

आवाजें: स्पीकर साहब, सभी डिमांडज को एक साथ ही पुट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

Question is –

That a sum not exceeding Rs. 14939000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 425891000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1041845000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 146948000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 92888000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 520772000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 1180519000 for revenue expenditure and Rs. 2630000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 635946000 for revenue expenditure and Rs. 489555000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 3067003000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 504355000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 58100000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 221458000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 169412000 for revenue expenditure and Rs. 15304000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 43332000 for revenue expenditure and Rs. 1332923000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 1996550000 for revenue expenditure and Rs. 673359000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 220601000 for revenue expenditure and Rs. 68716000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 762587000 for revenue expenditure and Rs. 6350000 for capital expenditure

be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 762587000 for revenue expenditure and Rs. 6350000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 291937000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 31641000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 489599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 659591000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 82277000 for revenue expenditure and Rs. 190266000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 1549445000 for revenue expenditure and Rs. 178100000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 15258000 for revenue expenditure and Rs. 19000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2182070000 for revenue expenditure expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1990-91 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

तारांकित प्रश्न संख्या 1100 *पर आधे घंटे की चर्चा –

डिजनी लैंड सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न संख्या 1100 पर श्री राम बिलास शर्मा हाफ एन आवर डिस्कशन शुरू करेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1100 से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको मद्दे नजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुले दिन से इस पर आधे घंटे की डिस्कशन स्वीकार की है। सरकार का जवाब था कि 28342 एकड़ जमीन सोहना हल्के की गवालपाडी की पहाड़ी, दमदमा गांव और उसके आस पास के गांवों के एरिया की होगी। यहां पर चर्चा की गयी कि वहां पर एक ऐम्यूजमेंट पार्क बनाने जा रहे हैं और इस योजना के लिए प्रेरणा के रूप में, उदाहरण के रूप में अमेरिका के ओसलों और लौस ऐंजलज के पार्कस को लिया गया है। में कहना चाहता हूं कि we cannot compare India with America. अमेरिका हमारे लिए कभी प्रेरणा नहीं हो सकता। अमेरिका की आबादी हमारे से एक चौथाई है और अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, वह हमारे से तीन गुना ज्यादा है। अमेरिका विकास की उन ऊंचाइयों को छू चुका है कि वहां हर कर्मचारी चाहे वह सफाई कर्मचारी है, चाहे गजटिड अफसर है और चाहे किसान है, वह अपने काम पर अपनी कार में जाता है। हमारे यहां पर आबादी के 52 प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिनको खाने के लिए मोटे अनाज की, पहनने के लिए मोटे कपड़े की और सिर पर छत की गारन्टी हम आज तक नहीं दे सके हैं। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बनने से पहले चौ. देवी लाल, आदरणीय डा. मंगल सैन तथा हम गांव–गांव में चर्चा किया करते थे कि हम अपनी सरकार के समय में ग्राम की प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता देंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि 283242 एकड़ में से

9320 एकड़ जमीन पहाड़ी है, 574 एकड़ झील की धरती है और 554 एकड़ जमीन शामलात और पंचायत की है। इसके आस पास के जो गांव हैं वहां के किसानों का पशु पालन का भी धंधा है। वे बेचारे भेड़ बकरी और गाय भैंस वहां चराते हैं। यह जो 10448 एकड़ जमीन है इनको अन–उपयोगी जमीन न समझें बल्कि यह बहुत उपयोगी है। गांवों में बहुत बड़ी आबादी रहती है जो बकरी भेड़ और गाय भैंस पालकर और आस–पास के इलाकों में अपना दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इसलिए इस जमीन को बहुत उपयोगी समझा जाए। बाकी 18000 एकड़ जो जमीन है, पिछले दिनों जब चौ. देवी लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने इस बारे में बैठ कर हमारे साथ चर्चा की थी कि इस इलाके में, दिल्ली में बसने वाले पूंजीपतियों ने अपने आराम के लिए इस इलाके के किसानों को जमीन की अच्छी कीमत का लालच देकर उजाड़ दिया है और वहां पर फार्म हाउसिज के नाम से जमीन हथिया ली। वे मार्जिनल किसान थे और दूसरी जगह जमीन नहीं खरीद पाए। उन्होंने उस पैसे की मारूति कारें ले लीं। उसके बाद जब उनके पास पूंजी खत्म हो गई तो उनमें से अब कोई शहर में रिक्शा चला रहा है या कोई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। यह कहा गया कि क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक है इसलिए लोग इस पार्क को देखने आएंगे। इस पर तीन सौ करोड़ रूपया लगेगा। जो हिन्दुस्तान में आने वाले पर्यटक हैं, वे डिजनीलैंड ऐम्यूजमैंट पार्क देखने के लिए आने वाली कई

सदियों मे ंतो नहीं आएंगे। वे ऐसा पार्क देखने के लिए ओसलों और लौस ऐजल्ज में जाएंगे। हिन्दुस्तान में जो आएंगे, वे जो हिन्दुस्तानके दार्शीनिक स्थान देखने आएंगे, हिन्दुस्तान के छोटे किसान को देखने आएंगे और हिन्दुस्तान की कुछ मान मर्यादाओं को देखने आएंगे। इसलिए हरियाणा जैसे छोटे प्रान्त में और जिस इलाके की यह चर्चा है, जिस इलाके को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं क्योंकि लोक सीाा के चुनावों में यह क्षेत्र मेरे पास था, वहां पर छोटे–छोटे गांव हैं। कोई 100 घरों का, कोई 200 घरों का और कोई 300 घरों का गांव है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में पुनर्विचार करें और उसको कोई प्राथमिकता न दें क्योंकि न इसमें हरियाणा का कोई हित है और न ही इसमें वहां की जनता का कोई हित है। पता नहीं कब वह पार्क बनेगा। जब तक वह पार्क बनेगा तब तक तो वहां के लोग उजड़ जाएंगे, उनकी पीढ़ियां ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताएं नहीं देखनी चाहिएं। चुनावों से पहले आदरणीय चौ. देवी लाल जो ने जो घोशणाएं की थीं उनके बारे में चौ. औम प्रकाश चौटाला जी ने शपथ लेते हो यह वायदा यिका था कि हरियाणा के लोगों के लिए आदरणीय चौ. देवी लाल जी ने जो योजनाएं शुरू की थीं, उनको जारी रखा जाएगा और उन कार्यो को पूरा यिका जाएगा। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बारे में पुनर्विचार करें। चौ. देवी लाल जी ने इस योजना को अपने हाथ में नहीं लिया था जबकि चौ. भजन लाल इस योजना को शुरू करना चाहते थे। इसलिए

आप आदरणीय चौ. देवी लाल जी की बात को ध्यान में रख कर इस योजना पर काम शुरू न करें यह हरियाणा के हित में होगा।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker: Hon'ble Chief Minister will reply.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं भी इस बारे में क्वैश्चन पूछना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker: No, this is not the procedure. Now Chief Minister will reply. (Interruption & Noise).

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं प्रोसीजर की ही बात कर रहा हूं कि पहले आप मेरी सबमिशन सुन लें। (शोर)

Mr. Speaker: Mahender Pratap Ji, please do not raise hue and cry. Let us go according to the Rules. I will act strictly according to the provisions of the Rules laid down by this august House. I can not go this way or that way. If you have nto read these, please listen to me. The proceedure is that पहले नोटिस देने वाला बोलेगा और कंसर्ड मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। उसके बाद सिर्फ उन्हीं माननीय सदस्यों को क्वैश्चन पुट करने की इजाजत दी जा सकती है जिनकी तरफ से मुझे ऐसा करने की प्रिवियस इंटिमेशन मिली है। No one else can put any question. This is the procedure laid down in this book of Rules procedure.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, आप मेरी सबमिशन तो सुन लें उसके बाद अपना फैसला दे दें।

Mr. Speaker: I am talking of the Rules. मैं फैसले की बात नहीं करता। यह मेरे बस की बात नहीं है। जो हाउस के रूल्ज हैं, मैं उन्हीं के मुताबिक चलूंगा।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में काल अटैंशन मोशन के नोटिसिज दिए थे वे आपने किसी कारण से रिजैक्ट कर दिये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वे इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मान गए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है जिन माननीय सदस्यों ने इस विशय में काल अटैंशन मोशन के नोटिसिज दिए थे और जो किसी कारण से आपसे रिजैक्ट कर दिए उनको आप दो–दो या तीन–तीन मिनट बोलने का समय दे दें और मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे दैंगे।

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर साहब, मैं इनके बोले बगैर ही इनकी तसल्ली करवा दूंगा। (शोर)

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, पहले आप मेरी सबमिशन तो सुन लें। (शोर)

Mr. Speaker: Mahender Partap Ji, this is not the way. This is not the procedure. I am veyr sorry. I am not above the procedure.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: महेन्द्र प्रताप सिंह जी, मैं वैसे ही आपकी तसल्ली करवा दूंगा। (शोर)

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी के इस बारे में इस तरह से जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। इस बारे में जवाब तो इन्होंने कल ही दे दिया था फिर आज इस बारे में डिस्कशन की क्या जरूरत है?(शोर)

Mr. Speaker: Mahender Partap Ji, this is not the procedure. आपको पता है इस पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी है और यह फैसला शुक्रवार हो ही हो गया था। जब आपको यहा पता था कि इस पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी है तो क्या आपने मेरे पास चिट भेजने की तकलीफ की कि आप भी इस बारे में सवाल पुट करना चाहते हैं? आप केवल शोर करना चाहते हैं। I will not allow it. Please take your seat क्योंकि यह समय भी हाफ एन आवर टाईम में काउन्ट होगा।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में जिन माननीय सदस्यों का क्वैश्चन था उनको तो इस बारे में सवाल पुट करने की इजाजत मिलती चाहिए। मेरा इस बारे में क्वैश्चन भी था और मैंने इस बारे में काल अटैन्शन मोशन का नोटिस भी दिया था। (शोर)

Mr. Speaker: No, no. This is not the way. इस बसरे में यदि आपका क्वैश्चन था तो आपने उस सयम सप्लीमैंटरी पूछी हैं। Please take your seat.

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, आपने इनको क्वैश्चन आवर में पर्याप्त टाईम दिया है। क्वैश्चन आवर में इस बारे में सप्लीमैटरीज पूछने के लिए आपने इनको आधा घंटा दिया है। क्वैश्चन आवर में इस इशू को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर आधे घंटे की चर्चा करने के लिए माना है और वह आपने अलाउ कर रखी है। स्पीकर साहब, इस बारे में सप्लीमैटरीज पूछने के लिए माननीय सदस्यो को लगभग आधा घंटा क्वैश्चन आवर में समय मिला और आधा घंटा अब मिल रहा है। यह जो जानना चाहते हैं उस बारे में मुख्यमंत्री जी इनके बोले बगैर ही तसल्ली करवा देंगे। (शोर)

Mr. Speaker: Please listen. This is not the way. (Interruptions) Mahender Partap Ji, you cannot be allowed to say whatever you want. You have not read the Rules. I will not go out of the Rules.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो बात हम कहना चाहते हैं उसमें से कुछ सवालात निकल सकते हैं। अगर हमें बोलने के लिये 5 मिनट का समय दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। चूंकि यहां पर हमारी सरकार की बात आई है इसलिये यदि

आप हमें बोलने के लिये समय दे दें तो ठीक रहेगी। (शोर एवं विघ्न)

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, आपके पास तो रूल्ज हैं। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Gupta ji, I have got a copy of the Rules but he has not read the Rules.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: रूल्ज तो मैं भी जानता हूं। जब हमारी काल अटैन्शन मोशन डिससलाऊ कर दी गई तो अब हमें इस पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Mahender Pratap ji, this is not the way. (Interruptions)

Ch. Mahender Pratap Singh: * * * *

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. Hon. Members, I would like to read one para of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Though I am not boudn to read and explain the Rules yet for the satisfaction of my Hon'ble friend, I am reading the relevant provision which says –

"There shall be not formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any Member who has previously intimated to the

Speaker may be permitted to put a question for the purpose of further elucidating any matter of fact ....."

Now what else he wants? I am very sorry to say that he is not understanding the Rules.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: आपकी बात तो ठीक है और मैं उसको मानता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं ..... (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात कहां मानते हो? I will not permit you to speak against the Rules. मेरे पास केवल तीन मैम्बर्ज की सवाल पूछने के लिए इंटिमेशन आई है। मैं उनको ही सवाल पूछने की इजाजत दूंगा बाकी किसी को नहीं दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: औन ए प्वायंट औफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विशय है। आप इस पर डिस्कशन के लिए और समय ऐक्सटैंड कर दें। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: No, I cannot extend it and it is my final decision that I will not permit any member to put a question, who has not given previous intimation.

श्री हीरा नन्द आर्य: अगर ऐसी बात है तो फिर ये शोर शाराबा क्यों! कर रहे है?

श्री अध्यक्ष: ये इसलिए कर रहे हैं कि टाईम निकल जाए। आप बैठिए! अब सी.एम. साहब जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इस ऐम्यूजमैंट पार्क को लेकर न सिर्फ सदन में बल्कि बाहर भी अखबारों में बहुत लम्बी चर्चा रही है और इसीलिए जब इससे संबंधित प्रश्न आया था तो मैंने बहुत खुले दिल से हाउस के सभी सदस्यों को उस पर सवाल पूछने का आपसे अनुरोध करके मौका दिलाया था। मुझे भी महेन्द्र प्रताप जी की तरफ चूंकि पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए मैंने अपने रिक्वैस्ट की थी कि इसका समय बढ़ा यिदा जाये लेकिन क्वैश्चन आवर का सयम नहीं बढ़ सकता था। मुझे इस बात का ज्ञान जरूर था कि कालिंग अटैंशन मोशन ऐडमिट होने पर उस पर केवल दो सवाल और पूछे जा सकते थे ओर उसमें मुझे आसानी हो सकती थी। सरकार अगर कोई तथ्य छिपाने की बात करती तो इसमें ज्यादा फायदे की बात होती। उस दिन लगभग 25 मिनट तक यह प्रश्न चला और सभी सदस्यों ने खुले दिल से प्रश्न किए। उसक बाद भी मैंने आपसे अनुरोध किया कि इस बात पर खुले दिल से डिस्कशन हो जाये। मैंने यह भी कहा कि आप असके लिए आधा घंटे की डिस्कशन के लिए अलग से समय निर्धारित कर दें। मैं आपको कृतज्ञ हूं कि आपने समय देकर इस हाउस के सभी सदस्यों को पूरी जानकारी हासिल करने का मौका दिया। यह पार्क बनाने की जो सोच थी उसके पीछे श्री राम बिलास शर्मा जी के कहने के मुताबिक अमेरिका से प्रेरणा लेने की सोच नहीं है। अमेरिका से प्रेरणा लेने का और मौका आ सकता है। हरियाणा सरकार की केवल एक सोच थी कि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से अगर इस प्रकार का मनोरंजन पार्क

हमारे प्रदेश की धरती पर बन जाये तो उससे सरकार को आर्थिक लाभ पहुंच सकता है और सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि जब मैं अमेरिका में इस पार्क में गया था तो उस वक्त 25 डौलर प्रति व्यक्ति इस पार्क की ऐंटरी फीस थी। इस पार्क में तीन किस्म की बातें देखने की हैं।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री साहब, मेरे पास केवल 10 मिनट का समय है and I can not extend it.

आवाजें: हमने ऐल्यूसिडेशन के लिए सवाल भी करने हैं।

Mr. Speaker: I have kept five minutes for that.

आवाजें: समय और बढ़ा दीजिए।

Mr. Speaker: I am sorry, I cannot extend it.

चौ. औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि वहां पर ऐफकोर्ट सैन्टर्ज, मैजिक किंगडम ओर एम.जी.एम. स्टूडियोज देखने योग्य हैं। इस सारे मामले को देखने के लिए 100 डालर की टिकट है। एक दिन में वहां पर जाने वाला आदमी पूरी तरह से अपनी तसल्ली नहीं कर सकता। जब से सृश्टि की रचना हुई है तब से लेकर चन्द्र लोक तक की यात्रा का वर्णन वहां दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर शोर है कि भूमि बहुत ज्यादा अधिग्रहण की गई। 28342 एकड़ भूमि

अधिग्रहण करने के लिए हरियाणा सरकार ने नोटस दिया है। स्पीकर साहब, 14381 एकड़ काश्त योग्य भूमि में से 6960 एकड़ भूमि बम्बई, जयपुर, कलकता और दिल्ली के बड़े–बड़े प्रौपर्टी डीलर्ज ने खरीदी हुई है। इन प्रौपर्टी डीलर्ज ने कम कीमत की रजिस्ट्रियां करवा कर हरियाणा सरकार की स्टाम्प डयूटी भी चुराई है। दफा 4 का नोटिस होने के बाद जब उन्हें अपने खर्चे हुए पैसे से कम पैसा मिलने की आशंका हुई तो उन्होंने अखबरों के माध्यम से शोर मचाना शुरू कर दिया। अखबारों के कुछ साथी, मालिक और पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां पर जमीन खरीदी हुई है, उनको भी इसी बात की तकलीफ है कि उन्हें कीमत कम मिलेगी। इस मामले में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले स्वामी अग्निवेश कीभी वहां जमीन है। उन्होंने और जमीन लेने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल जी को पत्र भी लिखा हुआ है जो मेरे पास है। इस पत्र में लिखा है ''जमीन लेने के लिए–धर्म प्रतिश्ठान''। और इस पत्र में जो पता दिया है वह 24–सी, एम. आई.जी, फलैटस, शेख सराय, नई दिल्ली। स्वामी अग्निवेश के पास गांव बैल्पा की जो जमीन है, वह मैसर्ज मुक्ति प्रतिश्ठान के नाम से है और मैसर्ज मुक्ति प्रतिश्ठान वाले भी 24–सी, एम.आई. जी. फलैटस, शेख सराय, नई दिल्ली में ही रहते हैं और मैसर्ज मुक्ति प्रतिश्ठान के एिल जमीन मांग रहे हैं। पहले धर्म प्रतिश्ठान के लिए जमीन ली और अब मुक्ति प्रतिश्ठान के लिए और जमीन मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन की बात श्री राम बिलास शर्मा जी ने की कि वहां पर पशुधन भी चराया जा सकता है, आज

उस जमीन के दाम लाखों मे हैं और उसी जमीन को लेने की कोशिश में यह धर्म प्रतिश्ठान और मुक्ति प्रतिश्ठान वाले लगे हुए हैं। सरकार की यह मन्शा नहीं है कि किसी किसान की जमीन उससे ले ली जाए। जिस किसान के पास थोड़ी सी धरती है जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोशण कर रहा है, उस जमीन को लेने की सरकार की कोई मन्शा नहीं है। सरकार की मन्शा तो उस जमीन को लेने की है जो गरीब किसान से पहले ही लूटी जा चुकी है और वह 6960 एकड़ भूमि जिन बड़े–बड़े प्रौपर्टी डीलर्ज रे खरीदी है उनकी लिस्ट भी मेरे पास है। यह लिस्ट यदि हाउस चाहे तो हर माननीय सदस्य को मिल सकती है। (व्यवधान) इस जमीन का खरीदने वाले कौन–कौन महानुभाव हैं उनकी लिस्ट माननीय सदस्यों को भिजवा दी जाएगी। स्पीकर साहब, इस बात को कई सदस्यों ने और विशेश तौर से पुनिया साहब ने उठाया तथा सबसे बड़ा धनी राजनीतिज्ञ होने का इल्जाम मुझ पर लगाया था। स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं हाउस में आज यह बात करने जा रहा हूं कि मेरे नाम से या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक मरला या एक इंच भूमि भी अगर इस योजनाबद्ध प्रोग्राम के तहत मिल जाए, तो उसमें से पुनिया साहब के साथ मैं हिस्सेदारी भी कर सकता हूं। इस हिस्सेदारी से मुझे बहुत खुशी होगी। इस हिस्सेदारी में से मुझे आधी मिल जाए, चौथाई मिल जाए मैं इससे बहुत राजी, हूं। दूसरी बात री राम बिलास शर्मा जी ने कही कि यहां पर आने वाले लोग इसे नहीं देख पाएंगे। मैं यह मान कर चलता हूं कि

भारतवर्श के लोग आर्थिक तौर पर शायद इतना पैसा खर्च न कर सकें, लेकिन 25 किलोमीटर के फासले पर दिल्ली है, जो एक इन्टरनेशनल सिटी है, वहां पर हर हिस्से के आदमी आते हैं। जो ीाा दिल्ली आएगा वह इसे जरू देखेगा। हमारे माननीय साथी, पुनिया साहब, ने कहा कि वहां पर यह पार्क दो सौ एकड़ में बनी हुई है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वह 27 हजार एकड़ में बनी हुई है। दूसरे, ज्यादा जमीन हमने इसलिए ली है कि जहां लोगों को जब यह दिखाई दे जाएगा कि वहां ऐसी अच्छी चीज बनने जा रही है तो वहां के आस–पड़ौस के लोगों की जमीन सस्ते भाव पर खरीद लेंगे और बाद में महंगे भाव पर बेचेंगे। सरकार की मन्शा है कि ऐसी साजिश करने वालों को

फायदा न उठाने दिया जाए। जहां सरकार ने 28342 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का नोटिस दिया है, उसके साथ लगती हुई जमीन की रजिस्ट्री न हो, ऐसा भी सरकार ने आदेश दिया है ताकि और ज्यादा फायदा चालाक लोग न उइा सकें। सरकार की मन्शा केवल एक है कि आपके प्रदेश के विकास कार्य ज्यादा हो सकें और प्रदेश की आमदन बढ़ सके। इस बारे में यह भी चिन्ता व्यक्त की गई है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। मैंने प्रश्नकाल में एक प्रश्न के उतर में बताया था कि इसके लिए बाकायदगी से टूरिज्म डिपार्टमैंट की तरफ से एक अथौरिटी बने, जिए प्रकार से दिल्ली डिवैल्पमैंट अथौरिटी बनी हुई है, उसी प्रकार से यहां भी बने ताकि उसको जितनी धनराशि की जरूरत होती है, वह लोन से

मिल जाया करती है। यह सारा कुछ सरकार अपनी तरफ से नहीं बनाने जा रही है, बल्कि उस डिपार्टमैंट की तरफ से कुछ जमीन खरीदकर जो कोई इस प्रकार की चीज बनेगी, उसके लिए हम अलग–अलग टेंडर तलब करेंगे। फिर हम किस प्रकार की बनाना चाहेंगे, यह जमीन खरीदने के बाद ही तय किया जा सकेगा। हमारा केवल इतनी ही मन्शा थी, लेकिन अखबारों वालों ने खास तौर पर शोर मचाया और इसी शोर को मेहम की कड़ी से भी जोड़ दिया गया कि डिजनी लैंड बनाने के लिए किसानों की जमीन छिनी जा रही है। वहां के किसान मेहम में जाकर धरना देंगे, आन्दोलन करेंगे और मेहम के चुनाव में मुखालिफत करेंगे। लेकिन मैं, हाउस में बताना चाहूंगा कि वहां के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वे सब के सब पूरी तरह सन्तुश्ट हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि हम उन गरीब किसानों की जमीन किसी कीमत पर नहीं लेना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि कि कोई एक–आध एकड़ विकास कार्य के लिए किसी वजह से बाधक हुई तो वह ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि 26 गावों को उजाड़ दिया जाएगा। हमारी मन्शा गांव उजाड़ने की नहीं है। जब से सृश्टि की रचना हुई है, तब से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के, यानी चन्द्रलोक तक के सारे हालात इसमें दर्शाए जाएंगे और जो गांव हैं, उनको भी अच्छे ढंग से डिवैल्प किया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में चिराग और नारायण गांव है, असर वहां किसी पास एक छोटा सा कोठड़ा भी है, तो भी उसे कुछ करने की जरूरत नहीं

है, वह मालामाल है, उसका काम चलता है। हम किसी गांव को नहीं उजाडेंगे और जो छोटा किसान है, उसकी धरती भी नहीं लेंगे। जा लोग इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं कि कुछ अखबार वाले लोगों की भी वहां पर जमीन है। कुछ धर्म प्रतिश्ठान वालों की भी जमीन है, वे इसलिए प्रचार करते हैं ताकि उनकी जमीन बेची रहे।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इन्हें बोलते हुए काफी समय हो गया है, अब दूसरों ने भी बोलना है।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: यह अधिकार आपके पास कब से आ गया। यह अधिकार स्पीकर साहब के पास है। आप आराम से बैठिए। अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इन अखबार वालों को क्या कहा जाए? अखबार वालों में मेहम ने नौरंग रैस्टोरेंट के बारे में अखबार में खबर छापी है कि चौ. ओम प्रकाश ने उसका नाम 'नौरंग' इसलिए रख दिया कि मेरे दादा का नाम 'नौरंग' था। अखबार वालों ने यह भी लिख दिया कि मैं 'भगवान से भी नहीं डरता' ताकि इस देश में आस्तिक लोग खबर पढ़ते ही यह धारणा बना लें कि यह बड़ा मगरूर है। इस प्रकार के बखेड़े जानबूझ कर पैदा किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को फिर से तसल्ली दिलाऊंगा और यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार का मन्शा किसी किसान की जमीन इसलिए लेने का है कि उससे कोई द्वेश है बल्कि सरकार का मन्शा यह है कि एक ऐसा ऐम्यूजमैंट पार्क बन जाये जिससे

सरकार को आमदनी बढ़े। किसान को कोई धरती अगर मजबूरन इसमें आयेगी तो हम उसे अच्छा कम्पनसैट करेंगे। इसके प्रति सरकार की कोई दुर्भावना नहीं है। मैं इस बात को लम्बे अर्से से स्पश्ट करना चाहता था। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे एक ऐसा मंच दिया। अब तो मजबूरन इन प्रैस वालों को भी ये बातें लिखनी पड़ेगी और ये कंट्राडिक्शन भी शाया करेंगे। आपका इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, बड़े ही महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा हो रही है।

चौ. ओम प्रकाशा चौटाला: स्पीकर साहब, एक बात रह गयी। मेरे दादा का नाम लेख राम है। मेरे परदादा का नाम 'आसा' है। उसके बाप का नाम 'तेजा' है। इससे आगे भी कोई प्रैस के लोग पूछना चाहें तो मैं भिजवा सकता हूं। नौरंग मेरे दादा का नाम नहीं है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, बड़े ही महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा हो रही है और चौ. औम प्रकाश जी ने अखबार वालों को अपनी वंशावली भी बता दी है। स्पीकर साहब, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि क्या हरियाणा को इस ऐम्यजमैंट पार्क की आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि सी.एम. साहब ने फरमाया है कि किसान उजाड़े नहीं जायेंगे। श्री ओम प्रकाश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्वालपुरी नाम का पहाड़ कुछ लोगों ने

यह सोच कर लिया हुआ हो कि यहां पर ऐम्यूजमैंट पार्क बनने वाला है और बड़ा पैसा मिलेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ बात की है। मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में व्हाईअ पेपर शाया किया जाये कि कौन सी धरती है, कितनी–कितनी धरती कहां–कहां की है, कितनी ऐग्रीकल्चरल लैंड है, कितनी बारानी लैंड है, कितने पहाड़ लगते हैं और कितने जोहड़ उसमें आते हैं। यह सारी बातें साफ हो जायें तो ठीक रहेगा। केवल अखबार वालों को कोसने से बात नहीं बनेगी।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, डा. मंगल सैन जैसे जिम्मेवार आदमी का इस प्रकार का प्रश्न आया है। दफा 4 के नोटिस में सारा विवरण तफसील के साथ दिया हुआ है। इसलिये उसके बारे में श्वेत पत्र देने की जरूरत नही है। आप जहां से चाहेंगे, वह आपको मिल सकता है। उसमें एक–एक ईन्च की डिटेल का जिक्र है। एक–एक झील का जिक्र है, पहाड़ का जिक्र है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आपको धन्यवाद किया, हम भी आप का धन्यवाद करेंगे। मैं यह कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से इस ऐम्यूजमैंट पार्क की चर्चा चलती रही है। मैंने इस बारे में काल अटैंशन मोशन भी दिया और क्वैश्चन भी दिया है। मेरे सवाल के जवाब में इन्होंने यह फरमाया कि दफा 4 के नोटिस में यह बात सारी आ गयी है।

वह तो आंकड़ों की बात होगी। चाहे वहां पर यह डिटेल्ज भी हों लेकिन फिर भी मैं नेक सलाह देना चाहता हूं। दिल में तो शायद कुछ और ही बात कह रहे होंगे। तो मैं यह अपने लिये नहीं कहता मैं तो यह कहता हूं कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट की बात है। इसमें आपका इन्ट्रैस्ट, हमारा इन्ट्रैस्ट यानी सबका इन्ट्रैस्ट शामिल है। इस बारे में ये व्हाईट पेपर शाया करने को क्यों तैयार नहीं है।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कह दिया है कि इसके लिये जो दफा 4 को नोटिस इशू हुआ है, वह अपने आप में व्हाईट पेपर है। अलग से उसकी डिटेल्ज देने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी एक और बात स्पश्ट करना चाहता हूं। मनोरंजन पार्क की विलासिता का साधन बताया गया है। यह कोई विलासिता का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक आवश्यकता के हिसाब से ऐसा बनाया गया है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैं दो–तीन प्वायंटस रेज करना चाहूंगा और वे भी बड़े ही मुख्तसिर तौर पर कहूंगा। एक तो यह है कि इस ऐम्यूजमैंट पार्क के लिए मेरे विचार से केवल तीन सौ एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस सारी जमीन को ऐक्वायर करने के लिये क्या हरियाणा सरकार के पास प्रबन्ध है? एक प्वायंट तो यह है। दूसरा प्वायंट मेरा यह है कि इस प्रोजैक्ट को बनाने के लिये अन्दाजा यह लगाया गया कि 30000 करोड़ रूपये दरकार हैं। वैसे तो इन्होंने इनडायरैक्टली इस बारे में कुछ बता दिया है कि शायद दूसरे लोग जो वहां पर इसे

सैट–अप करेंगे, वह रूपया खर्च करेंगे मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने बड़े 30000 करोड़ रूपये के इस प्रोजैक्ट के लिये क्या इन्होंने कोई ऐस्टिमेट लगाया है कि यह पैसा कहां से आएगा?

Mr. Speaker: Punia Sahib, now you please take your seat.

श्री किरपा राम पुनिया: आन ए प्वायंट औफ और्डर। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने गल्तबयानी की है। मैं उसके बरे में क्लैरीफिकेशन चाहता हूं to keep the record strainght डिजनीलैंड दो सौ एकड़ जमीन पर है जबकि ये कह रहे हैं कि सत्ताईस हजार एकड़ जमीन पर है। इस बारे में ये क्लैरीफिकेशन दें? (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Speaker: This is not the way. Please put the question. आप पढ़े लिखे हैं। आप क्वैश्चन पुट करिए।

श्री किरपा राम पुनिया: सत्ताईस हजार एकड़ तो सब को मिलाकर है। डिजनी वर्ल्ड फलोरिडा स्टे में औरलैन्डा में है। वहां पर डिजनी वर्ल्ड एंड सी–वर्ल्ड दोनों बने हुए हैं जिसमें सी–वर्ल्ड बहुत बड़े समुन्द्र की तरह बनाया गया है जिसमें वाटर स्पोर्टस होते हैं। इसके लिए पूरा समुन्द्र है। इसलिए यह 27 हजार एकड़ का एरिया है मगर जो डिजनी लैंड ऐजंल्ज का है, वह केवल दो सौ एकड़ जमीन पर है।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, किरपा राम पुनिया को सब से ज्यादा चिन्ता यह है कि इसके लिए धन कहां से आएगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि सरकार यह जमीन अधिग्रहण करके जो जो चीज वहां कोई बनाएगा, उसको देंगे। ग्लोबल टैन्डर से यह मसला हल होने जा रहा है। सवाल जो पूछने वाला था, वह ये नहीं पूछ पाए। वह मैं बता देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह भी चर्चा चली, अखबारों में आया और कुछ साथियों ने प्रश्न काल के दौरान जिक्र भी किया कि लोग उजड़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह ऐम्यूजमैंट पार्क बनेगा तो कम से कम पचास हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि स्पैसिफिक प्रौजेट के लिये जितनी जमीन जरूरी हो उससे फालतू न ली जाए लेकिन सदन के नेता ने कहा है कि उससे कुछ फालतू जमीन ली जा रही है ताकि और लोग फालतू उस जमीन को इस्तेमाल न कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल मिनिस्ट्री औफ रूरल डिवैल्पमैंट ने बार बार इन्स्ट्रक्शंज जारी की हैं कि गैर जरूरी प्रोजैक्ट के लिए खेती बाड़ी की जमीन न ली जाए। हमने ऐस्टेबलिश कर दिया है कि यह जो प्रोजैक्ट है, यह गैर जरूरी प्रोजैक्ट नजर आता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस चीज को ध्यान में रखकर सदन के नेता, क्या यह जो

पिछली कांग्रेस सरकार का विवादास्पद प्रोजैक्ट है, इसको छोड़ने की कृपा करेंगे?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौ. सूरज भान स्वयं रैवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं। कानून के ज्ञाता हैं और ला ग्रेजुएट हैं। दफा चार में जमीन ली नहीं जाती केवल बाउन्ड की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के औब्लेकशंज आएंगे, उन सबके एतराजात को सुना जाएगा और उस पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भूमि अधिग्रहण की गई है, इसके अलावा साथ लगती हुई भूमि की रजिस्ट्री पर इसलिए रोक लगाई है ताकि और लोग सस्ते दामों पर खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश न करें। मैं यह क्लेरीफाई कर चुका हूं कि जितनी भूमि हमें दरकार होगी उतनी ही ली जाएगी। इसके लिए वही भूमि ली जाएगी जो अनप्रोडैक्टिव होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रौपर्टी डीलर्ज ने जो काश्तकार की भूमि और जो ले रखी है, फार्म हाउस बनाकर बेचने वाले लोग हैं, उनकी भूमि के साथ शायद रियायत न बरती जाए लेकिन यदि गरीब किसान की भूमि आएगी तो सरकार नहीं लेगीं ओर अगर मजबूरन लेनी भी पड़ी तो उसको अच्छा कम्पनसेशन दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अब सदन कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न* किया जाता है।

***18.54 बजे**

(तत्पश्चात सदन मंगलवार, दिनांक 20.3.1990 प्रातः 9. 30 बजे तक स्थगित हुआ।)

Appendix-1

***1081. Seth Lachman Dass Bajaj**: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the total number of fatal accidents involving Haryana Roadways buses occurred on G. T. Road in the State during the calender year 1989; and

(b) whether any amount as compensation has been paid as a matter of policy depending upon the nature of casualty suffered to the dependent of the deceased and the persons injured in the accidents referred to in part (a) above; if so the total amount paid as compensation?

Minister of State for Transport (Shri Dharambir Singh) :

(a) 76.

(b) NIL.

Appendix-2

***1070. Shri Udai Bhan**: Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) the category-wise number of employees working in the Faridabad Complex together with the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classed amongst them; and

(b) whether there is any backing in the reserved posts; if so the reasons thereof togetherwith the time by which these posts are likely to be filled up?

Local Government Minister (Shri Subhash Chand Katyal):

(a) Statement No. 1 is placed on the Table of the House.

(b) Yes. Statement No.2 is placed on the Table of the House.

Statement No.1

Sr. No.	Category of posts	Total employees working	Employees belonging to Scheduled Caste	Employees belonging to Backward Class
1	Chief Administrator	1		
2	Administrator	3		

3	Senior Town Planner	1		
4	Distt. Attorney	1		
5	Medical Officer of Health	1		
6	Tehsildar	1		
7	Administration Engineer (Public Health)	1		
8	Administration Engineer (B&R)	1		
9	Chief Accounts Officer-cum- Financial Adviser	1		
10	Deputy Town Planner	1		
11	Architect	1		
12	Senior Establisment Officer	1		
13	Asstt. Town Planner	1		
14	Asstt. Engineer (Civil)	4		
15	Asstt. Engineer (Elect.)	1		
16	Asstt. Engineer (Mech.)	2		
17	Asstt. Engineer (Hort.)	1		
18	Zonal & Taxation Officer	6		

19	Asstt. Accounts Officer	2		
20	Naib Tehsildar	1		
21	Supdt./ Land & Licensing Officer	15	2	
22	Fire Station Officer	2	1	
23	Asstt. Fire Station Officer	4	1	
24	Junior Engineer (Civil)/ Building Inspector	24	2	2
25	Asstt./Asstt. Octroi Supdt.	26	7	1
26	Junior Engineer (Mech.)	3		
27	Junior Engineer (Elect.)	3		
28	Junior Engineer (Hort.)	3		
29	Receptionist-cum-Technical Asstt.	1		
30	Stenographer	4		
31	Foreman (Water Supply)	1		
32	Foreman (Electrical)	1		
33	Senior Librarian	1		
34	Head Draftsman	2		

35	Junior Architectural Draftsman	1		
36	Road Inspector	7	2	
37	Draftsman/Asstt. Draftsman	8	1	
38	Dispenser	1		
39	Accounts Clerk/Octrol Inspector	46	9	3
40	Radiographer	1		
41	Junior Librarian	2		
42	Vehicle Driver	48	16	1
43	Road Roller Driver	2		
44	Fire Brigade Driver	23	3	4
45	Leading Fireman	9	2	
46	Senior Sanitary Inspector	6	1	
47	Sanitary Inspector	7		
48	Asstt. Sanitary Inspector	15	4	1
49	Sewer Inspector	1	1	
50	Horiculture Inspector	5	1	

51	Meter Mechanic	4	1	
52	Mechanic Tubewell	2		
53	Motor Mechanic	1		
54	Surveyor	2		
55	Electrician	7	1	
56	Clerk	246	40	21
57	Steno-Typist	10		1
58	Patwari	10	1	1
59	Tracer	1		
60	Plumber Fitter Grade-I	1		
61	Plumber Fitter Grade-II	8	1	1
62	Carpenter	1		1
63	Mason	6	1	
64	Tubewell Driverr	295	33	14
65	Fireman	35	3	1
66	Sewer Engine Driver	4		
67	Auxilary Nurse Midwife	5		
68	Lab. Asstt.	1		
69	Ward Cooli	1		

70	Library Attendent	5		
71	Library Peon	2	1	
72	Pherro Printer	1		
73	Khalasi	2		
74	Peon/Bill Distributor	133	24	12
75	Chowkidar	15	1	1
76	Belder	85	12	8
77	Head Mali	8	2	
78	Mali	150	23	12
79	Bill Distributor	8	2	
80	Craft Teacher	6	2	
81	Nurse Dai	1		
82	Lab. Attendant	3		
83	Safai Daroga	49	49	
84	Pump Cleaner	2		
85	Head Sewerman	6	6	
86	Sewerman	48	48	
87	Mali-cum-Chowkidar	20	2	
88	Helper to Electrician	3		

89	Helper to Mechanic	5		
90	Safai Karamchari	1265	1265	
91	Cleaner	10	10	
	Total	2771	1581	82

Statement No. 2

1. There is a backlog of 116 posts only of which 72 posts belong to Scheduled Castes and 44 posts to Backward Classes.

2. Person appointed on adhoc/daily wage basis and belonging to general category have been holding posts meant for reserved categories of Scheduled Castes and Backward Classes for quite a long time. Services of these persons cannot be terminated in view of stay orders/status quo orders granted in most cases by competent courts of law. Steps will be taken to remove the backlog as soon as stay orders are vacated by Courts.